बिहार से निर्यातों का संवर्द्धनः विश्लेषण और नीतिगत परिप्रेक्ष्य

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

कार्यकारी आलेख संख्या : 88

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

कार्यकारी आलेख संख्या : 88

बिहार से निर्यातों का संवर्द्धनः विश्लेषण और नीतिगत परिप्रेक्ष्य

एक्ज़िम बैंक की कार्यकारी आलेख श्रृंखला बैंक द्वारा किए गए शोध अध्ययनों के निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करने का एक प्रयास है। शोध अध्ययनों के ये निष्कर्ष निर्यातकों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और निर्यात संवर्द्धन एजेंसियों के साथ-साथ शोधकर्ताओं की रुचि के विषय हो सकते हैं। तथापि आवश्यक नहीं कि शोध अध्ययन में अभिव्यक्त विचार बैंक के ही हों। हालांकि आंकड़ों और सूचना की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी ऐसी मदों की प्रामाणिकता, शुद्धता या पूर्णता के लिए एक्ज़िम बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

© भारतीय निर्यात-आयात बैंक

मार्च 2019

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
चार्टों की सूची	5
तालिका सूची	7
बॉक्सों की सूची	8
कार्यकारी सारांश	9
1. प्रस्तावना	14
2. व्यापक आर्थिक प्रोफाइल	16
3. आर्थिक परिदृश्य	22
4. बिहार से निर्यात : वर्तमान परिदृश्य और संभावनाएं	30
5. निर्यात वृद्धि के लिए रणनीतियां	39
अनुलग्नक : प्रोडक्ट चैंपियंस श्रेणी में बिहार के लिए प्रमुख बाजार तथा प्रतिस्पर्धी	56

प्रोजेक्ट टीम :

सुश्री जाह्नवी, प्रबंधक, शोध एवं विश्लेषण समूह

सुश्री नेहा रामन, उप प्रबंधक, शोध एवं विश्लेषण समूह

अनुवाद :

श्री नवेन्दु वाजपेयी, उप महाप्रबंधक, राजभाषा समूह

श्री विकास वशिष्ठ, प्रबंधक, राजभाषा समूह

श्री कुणाल गुलाटी, मुख्य प्रबंधक, कॉर्पोरेट संचार समूह

चार्टों की सूची

चार्ट सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	बिहार - प्रमुख मेट्रिक्स	15
2	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 2012 = 100) में मासिक उतार-चढ़ाव	17
3	प्रमुख आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल मूल्य योजन (2017-18)	18
4	अनाज के क्षेत्र और उत्पादन में अंचल-वार हिस्सा (2016-17)	23
5	टेक्सटाइल, अपैरल और चमड़े के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र	27
6	पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र	29
7	बिहार के समग्र और गैर-पीओएल निर्यातों के प्रमुख आयातक (2017-18)	32
8	बिहार से बंदरगाह-वार निर्यात (2017-18)	33
9	बिहार से निर्यात योग्य उत्पादों को चिह्नित करना	36
10	निर्यात रणनीति के प्रमुख तत्त्व	39
11	कोल्ड चेन स्टोरेज की जरूरत वाले खंड	49
12	बिहार निर्यात संवर्द्धन परिषद की रूपरेखा	55

तालिका सूची

तालिका सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	भारत के सकल घरेलू उत्पाद से बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना (करोड़ रुपये)	16
2	बिहार के लिए क्षेत्र-वार सकल मूल्य योजन (जीवीए) (करोड़ रुपये)	17
3	बिहार के लिए क्षेत्र-वार जीवीए हिस्सा (प्रतिशत)	18
4	बिहार के कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में जीवीए (करोड़ रुपये)	19
5	बिहार के उद्योग क्षेत्र में जीवीए (करोड़ रुपये)	20
6	बिहार के सेवा क्षेत्र में जीवीए (करोड़ रुपये)	20
7	बिहार में कृषि जलवायु अंचल	21
8	भारत और बिहार का तुलनात्मक कृषि उत्पादन (2016-17)	23
9	भारत और बिहार का तुलनात्मक बागबानी उत्पादन (2017-18)	24
10	बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन	25
11	बिहार में औद्योगिक उत्पादन का परिदृश्य (2015-16)	26
12	जिला-वार प्रमुख हथकरघा उत्पाद	28
13	बिहार में पर्यटकों का आगमन (मिलियन में)	29
14	बिहार से निर्यातों में रुझान	31
15	बिहार से उत्पाद-वार निर्यात (2017-18)	32
16	भारत के निर्यातों में सर्वाधिक हिस्सेदारी रखने वाले उत्पाद (2017-18)	32
17	वैकल्पिक परिदृश्य के तहत बिहार के लिए निर्यात लक्ष्य (2024-25)	36
18	बिहार में क्षेत्र-वार प्रोडक्ट चैंपियंस	39
19	बिहार में उम्मीदों से कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा	40
20	बिहार से निर्यातों के विशाखन के अवसर	42
21	बिहार से निर्यातित प्रमुख उत्पादों के प्रमुख आयातक और आयात स्रोत	45
22	आईसीडी की स्थापना के लिए जिलों की तुलना	46
23	बिहार में गोदामों की क्षमता (एमटी)	50
24	बिहार में कोल्ड चेन का बुनियादी ढांचा (यथा अगस्त 2017; मूल्य एमटी में)	51
25	बिहार के भौगोलिक उपदर्शन (आई) उत्पाद	52

बॉक्स सूची

बॉक्स सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	निर्यातों का रोजगार और वेतन पर प्रभाव	15
2	अहिंसा सिल्क	44

कार्यकारी सारांश

बिहार, भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित बंदरगाह विहीन प्रदेश है। इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा जहां नेपाल से लगती है, वहीं घरेलू सीमा इसे उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जोड़ती है। हाल के कुछ वर्षों में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वृद्धि दर्ज की गई है। 2011-12 से 2017-18 के दौरान राज्य के जीएसडीपी में 6.5 प्रतिशत की यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई। इससे भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बिहार का योगदान बढ़ा है। बिहार की आर्थिक वृद्धि को बढ़ते पूंजीगत खर्च, उद्योगों, लॉजिस्टिक सुविधाओं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में विस्तार से रफ्तार मिली है। तथापि, 2016-17 के लिए किए गए आकलन बताते हैं कि बिहार के जीएसडीपी में वस्तु निर्यातों का योगदान लगभग 1.3 प्रतिशत मात्र रहा । यद्यपि, बिहार के समान आर्थिक स्थिति वाले दूसरे राज्यों की तुलना में यह स्थिति बेहतर है, लेकिन 12.1 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह योगदान काफी कम है। बिहार की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र में बहुआयामी उपायों की जरूरत है।

इस अध्ययन में बिहार की आर्थिक प्रोफाइल और निर्यात निष्पादन की सूक्ष्म पड़ताल इसी पृष्ठभूमि में की गई है। दरअसल, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार से उठती मांग के साथ राज्य की आर्थिक वृद्धि के इन कारकों को मैप करने का एक प्रयास है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में राज्य से निर्यातों की संभाव्यताओं का विश्लेषण भी किया गया है। साथ ही निर्यातों के लिए डायनैमिक उत्पादों और निर्यातकों के लिए अग्रणी बाजारों को चिह्नित किया गया है, ताकि निर्यातकों को बेहतर लाभ मिल सके और सरकार सुधारों में तेजी ला सके। अध्ययन में राज्य स्तर पर व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा निर्यातों के लिए और बेहतर परिवेश बनाने की रणनीतियां भी सुझाई गई हैं।

बिहार का आर्थिक प्रोफाइल

बीते कुछ वर्षों में बिहार के जीएसडीपी के निम्न स्तर पर रहने के बाद 2016-17 से इसमें तीव्र वृद्धि देखी गई है, जो भारत के समग्र जीडीपी से भी अधिक रही है। स्थिर कीमतों पर राज्य का जीएसडीपी 2017-18 में रुपए 361504.3 करोड़ रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। यह राज्य की सकारात्मक आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। इस वृद्धि में राज्य के सेवा क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा।

यद्यपि बिहार में बड़ी संख्या में कम कीमत पर मजदूर उपलब्ध हैं, फिर भी राज्य का औद्योगिक क्षेत्र छोटा है। राज्य के सकल मूल्य योजन (जीवीए) में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान लगभग 19.7 प्रतिशत है। लेकिन रोजगार की दृष्टि से राज्य की अर्थव्यवस्था पर कृषि क्षेत्र का प्रभाव काफी अधिक है, क्योंकि लगभग 77 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्र से जुड़ी है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि के इस महत्त्व को देखते हुए एक निर्यात रणनीति के साथ-साथ इस क्षेत्र को उच्चतर वृद्धि वाले क्षेत्र में लाने के प्रयासों की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ, राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को ऐसे उत्पादों वाले उद्योगों के रूप में विकसित करने की जरूरत है, जिनके लिए निर्यात बाजारों में ऊंची कीमत मिलती है। उद्योगों को इस रूप में विकसित करते समय देश के अन्य राज्यों और दूसरे देशों से मिलने वाले प्रतिस्पर्धी दबाव के प्रति लचीलापन अपनाने की जरूरत होगी। सेवा खंड की बात की जाए तो पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो राज्य के लिए विदेशी मुद्रा आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा। आकलनों के अनुसार, पर्यटन क्षेत्र से विदेशी मुद्रा आय 1 अरब यूएस डॉलर रहने का अनुमान है। अतः राज्य से निर्यातों में पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। तथापि, हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में मामूली वृद्धि को देखते हुए इस क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ाने के प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी आधारित सेवाओं को भी बढ़ावा देने की जरूरत है।

बिहार का निर्यात निष्पादन

बिहार से 2017-18 में वस्तु निर्यात 1.35 अरब यूएस डॉलर का रहा, जिसमें 2012-13 के 0.4 अरब यूएस डॉलर के मुकाबले उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। तथापि, भारत से कुल वस्तु निर्यातों में बिहार से वस्तु निर्यातों का योगदान 1 प्रतिशत से भी कम रहा। अतः इस क्षेत्र में भी सुधार की काफी गुंजाइश है।

पेट्रोलियम उत्पाद राज्य के लिए महत्त्वपूर्ण निर्यात मद है। कृषि और

संबंधित उद्योगों तथा टेक्सटाइल और गारमेंट श्रेणियों में निर्यात बढ़ने से गैर-तेल निर्यात खंड में 2016-17 से अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन इस वृद्धि के बावजूद, बिहार के समग्र निर्यातों में गैर-तेल निर्यातों का हिस्सा एक तिहाई ही है। अतः इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए भी एक सुनियोजित रणनीति की जरूरत है।

भू-मार्ग से जुड़े होने के कारण बिहार से सबसे अधिक निर्यात नेपाल को किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, बिहार से निर्यातों का लगभग 78 प्रतिशत नेपाल को रहा। इसके बाद वियतनाम (4 प्रतिशत हिस्सा), बांग्लादेश (3 प्रतिशत), थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (प्रत्येक 2 प्रतिशत) का स्थान रहा। विश्लेषण बताता है कि बिहार से गैर पेट्रोलियम, तेल और ल्यूब्रिकैंट (गैर-पीओएल) उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक भी नेपाल ही है। हालांकि इसका हिस्सा 65 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, ताइवान, इराक, जापान और चीन भी नेपाल से गैर-पीओएल उत्पादों के शीर्ष आयातकों में शामिल हैं। लेकिन समग्र निर्यातों में यह स्थिति थोड़ी भिन्न है। इसलिए इन प्रमुख बाजारों को गैर-पीओएल निर्यातों के विशाखन के लिए निर्यात बढ़ाने की और संभावनाएं तलाशनी होंगी।

बिहार के लिए निर्यात लक्ष्य

प्राथमिक अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में बिहार से लगभग 900 अरब यूएस डॉलर के वस्तु निर्यातों की संभावना है, जिसे अभी तक भुनाया नहीं गया है। यदि इन संभावनाओं को वास्तविकता के धरातल पर उतारा जा सके तो राज्य से वस्तु निर्यात 2 अरब यूएस डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। तथापि, मध्यम अवधि में समुचित रणनीति के जरिए निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है।

बिहार से निर्यातों को बढ़ाने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी और व्यापक निर्यात रणनीति की जरूरत है, जिसमें देश की वृद्धि दर के लक्ष्यों के अनुरूप राज्य से निर्यात लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। निर्यात नीति का उद्देश्य सर्वप्रथम बिहार के जीएसडीपी में निर्यातों का हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 19 प्रतिशत (देश के वर्तमान औसत) के बराबर लाना होना चाहिए। इसके बाद, इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2024-25 के लिए 25 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप करने का प्रयास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, रोजगारों पर विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रभाव को देखते हुए इस प्रकार की नीति बनाई जानी चाहिए जिससे राज्य के जीएसडीपी में वस्तु निर्यातों का हिस्सा बढ़ाया जा सके। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य से निर्यातों का लक्ष्य 2024-25 तक बढ़ाकर 40 अरब यूएस डॉलर किया जाना चाहिए। इसमें वस्तु निर्यातों का लक्ष्य 27 अरब यूएस डॉलर और सेवा निर्यातों का लक्ष्य 13 अरब यूएस डॉलर तय किया जाना चाहिए।

बिहार के निर्यातकों के लिए प्रमुख उत्पाद और बाजार

बिहार से निर्यातों में अच्छी वृद्धि को देखते हुए ऐसे प्रमुख उत्पादों और बाजारों को चिह्नित किया जाना चाहिए, जो राज्य की फर्मों की प्रगति के लिए अवसर प्रदान करें और बड़े पैमाने पर किफायती उत्पादन कर सकें तथा उनकी क्षमता भी बढ़ सके। अध्ययन में ऐसे उत्पादों का बारीकी से विश्लेषण किया गया है, जिनमें राज्य के निर्यात तुलनात्मक रूप से लाभदायक रहे हैं और वैश्विक बाजारों में जिनके आयात की मांग है।

इस विश्लेषण के आधार पर, अध्ययन में ऐसे उत्पादों और उनके लिए लक्षित बाजारों को चिह्नित किया गया है, जहां घरेलू क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसे उत्पादों को प्रोडक्ट चैंपियंस (जिनमें अधिकतम संभावनाएं हैं) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे ही अन्य उत्पाद खंड हैं - अंडरअचीवर्स (जिन्हें प्रतियोगी आपूर्तिकर्ताओं से अपना खोया बाजार वापस पाने और निर्यात बढ़ाने की जरूरत है); अचीवर्स इन एडवर्सिटी (जिनके लिए विशाखन और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की जरूरत है) और डिक्लाइनिंग सेक्टर (जिनके विशाखन की जरूरत है)। तदनुसार, प्रोडक्ट चैंपियंस खंड में 81, अचीवर्स इन एडवर्सिटी खंड में 171, अंडरअचीवर्स खंड में 570 और डिक्लाइनिंग सेक्टर खंड में 1137 उत्पादों को शामिल किया गया है।

अल्पावधि से मध्यम अवधि में, राज्य को प्रोडक्ट चैंपियंस खंड में अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वहां लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मध्यम से दीर्घावधि में, राज्य को अंडरअचीवर्स खंड में क्षमता विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है।

बिहार के प्रोडक्ट चैंपियंस खंड में शामिल कुछ शीर्ष क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल उत्पाद, पशु और पशु उत्पाद, टेक्सटाइल्स और गारमेंट, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद तथा वनस्पति उत्पाद आते हैं। अंडरअचीवर्स खंड में सर्वाधिक उत्पाद टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र

से हैं। लेकिन राज्य से निर्यातों के मूल्य की बात की जाए तो रसायन और संबद्ध उत्पाद, तैयार खाद्य पदार्थ, फार्मास्यूटिकल उत्पाद और मशीनरी इस खंड के अंतर्गत शीर्ष उत्पाद हैं। कम होती वैश्विक मांग और वस्तुओं के मूल्य में आते उतार-चढ़ाव के इस परिदृश्य में इन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर बिहार से निर्यातों में आवश्यक लचीलापन लाया जा सकता है।

कुछ चिह्नित उत्पाद श्रेणियों में नेपाल प्रमुख आयातक देश है। सड़क मार्ग से जुड़े होने के चलते नेपाल में बिहार के निर्यातकों के लिए उल्लेखनीय अवसर हैं। नेपाल द्वारा आयात किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों में बिहार के निर्यातकों के लिए अपना बाजार बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं हैं। नेपाल के अतिरिक्त, मध्य पूर्व और पूर्व एशिया के देश भी बिहार के लिए महत्त्वपूर्ण आयातक हैं। बिहार के निर्यातकों के लिए इन देशों का महत्त्व विशेष रूप से तब तक बना रहेगा, जब तक कि राज्य में इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन विकसित नहीं हो जाते हैं और बाजार विशाखन के लिए प्रोत्साहनपूर्ण फ्रेमवर्क नहीं बन जाता है।

निर्यात वृद्धि के लिए रणनीतियां

अध्ययन में राज्य के औद्योगिक और निर्यात आधार के विशाखन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और ऐसे संभावित क्षेत्रों तथा बाजारों को चिह्नित किया गया है, जिन्हें लक्षित किया जा सके। राज्य को इन क्षेत्रों और बाजारों में अपने निर्यातों के विशाखन के लिए अपनी निर्यात स्पर्धात्मकता में भी सुधार करना होगा और एक सुनियोजित निर्यात रणनीति की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

समग्र रूप से देखें तो बिहार से निर्यातों के संवर्द्धन के लिए रणनीतिक योजना में विभिन्न स्तरों पर रणनीतियां बनाना शामिल होगा। मोटे तौर पर ये रणनीतियां छह आवश्यक आयामों पर बनाई जा सकती हैं - फोकस उत्पाद और बाजार; बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उसका लाभ उठाना; क्षमता विकास; वित्तीय प्रोत्साहन; निर्यात संवर्द्धन अभियान; और संस्थागत समन्वय।

फोकस उत्पाद और बाजार

यह मूल्य वर्धन पर आधारित निर्यातों के विशाखन के लिए निर्यात अवसर बढ़ाने के सक्षम तरीकों में से एक है। अध्ययन में संभावित उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों को चिह्नित किया गया है, जो बिहार से निर्यातों के विशाखन में मददगार हो सकते हैं। इनमें कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल और गारमेंट, रसायन और संबद्ध उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, हस्तशिल्प उत्पाद और पर्यटन तथा आतिथ्य शामिल हैं।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में राज्य कृषि उत्पादों के बड़े स्तर पर प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और ऑर्गैनिक उत्पादन बढ़ा सकता है। टेक्सटाइल खंड में राज्य टेक्निकल टेक्सटाइल्स और अहिंसा सिल्क उत्पादन पर फोकस कर सकता है। इन दोनों ही उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उच्च मूल्य हासिल किया जा सकता है। रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में अन्य के साथ-साथ रंगों और रंजकों, निर्माण रसायनों, सौंदर्य प्रसाधनों के घटकों और जल शोधन रसायनों पर फोकस किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल्स में मौजूदा निर्यात खंडों में क्षमता बढ़ाने तथा प्रतिरक्षी उत्पादों, पशु चिकित्सा संबंधी वैक्सीनों एवं अपारदर्शी औषध मिश्रणों जैसे अन्य ऐसे खंडों में विशाखन की जरूरत है, जिन्हें अभी तक भुनाया नहीं गया है।

इसके अतिरिक्त, अध्ययन में इस ओर भी संकेत किया गया है कि अधिकांश उत्पाद श्रेणियों में बिहार से अधिकतर निर्यातक वर्तमान में प्रमुख आयातक देशों को निर्यात नहीं कर रहे हैं। अतः अपने उत्पादों के लिए नए-नए बाजारों तक पहुंचना राज्य के लिए जरूरी है। राज्य को नए क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इंजीनियरिंग सामान जैसे उच्च-तकनीकी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि, इन क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात इन खंडों में निर्यात उन्मुख प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर निर्भर करता है। बिहार सरकार को भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप मेक इन बिहार जैसा कार्यक्रम बनाने, अपनाने और उसे क्रियान्वित करने की जरूरत है।

बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उसका लाभ उठाना

बेहतरीन निर्यात वृद्धि की इबारत लिखने और बिहार के समान अर्थव्यवस्था वाले राज्यों से प्रतिस्पर्धा के लिए बिहार को निर्यात के लिए अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने की जरूरत है। इसके लिए एक इनलैंड कंटनेर डिपो (आईसीडी) की स्थापना करना

सबसे महत्त्वपूर्ण होगा। बिहार में फिलहाल एक आईसीडी है, जो पटना में है और इस पर केवल घरेलू ढुलाई होती है। द्वितीयक स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए प्राथमिक शोध अध्ययन के आधार पर अध्ययन में मुजफ्फरपुर और भागलपुर में एक-एक आईसीडी स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निर्यात परिवहन के लिए पटना वाले आईसीडी में एक सीमा शुल्क मंजूरी संबंधी कार्यालय स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है।

पर्याप्त परिवहन, भंडारण और वितरण सेवाओं का अभाव भी देशभर के निर्यातकों के लिए एक बड़ा मसला है। यदि बिहार के संदर्भ में बात करें तो यह प्रमुख बाधा के रूप में उभरकर सामने आता है। क्योंकि बिहार से निर्यातों में जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की अच्छी मात्रा है। अतः राज्य में गोदाम और कोल्ड चेन स्टोरेज संबंधी बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने की जरूरत है। यदि उत्पादन के लगभग 70 प्रतिशत की भंडारण क्षमता भी मानें तो बिहार में 13 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों की जरूरत है, जबकि वर्तमान में सिर्फ 0.6 मिलियन मीट्रिक टन की ही क्षमता है। इसके अतिरिक्त, राज्य में अनुमानित 2.2 मिलियन मीट्रिक टन के कोल्ड चेन स्टोरेज बुनियादी ढांचे के विकास की भी जरूरत है।

अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि बिहार में वर्तमान में कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नहीं हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति, कानून या नियम भी नहीं हैं। औद्योगिक विकास और निर्यातों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के महत्त्व को देखते हुए यह राज्य के लिए चिंता का विषय है। राज्य में निर्यात उन्मुख एफडीआई आकर्षित करने और निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करना महत्त्वपूर्ण कदम होगा। अध्ययन में पटना, मुजफ्फरपुर या भागलपुर में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की संस्तुति की गई है, जो सड़क और रेल मार्ग से बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं।राज्य के कृषि क्षेत्र से निर्यातों की अच्छी संभावना को ध्यान में रखते हुए इनमें से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र केवल कृषि उत्पादों के लिए हो सकता है।

क्षमता सृजन

राज्य में भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) का दर्जा प्राप्त कई उत्पाद हैं। जीआई दर्जे का लाभ उठाने के लिए, जीआई ब्रांड को बाजार में एक विश्वसनीय और पसंदीदा ब्रांड के रूप में स्थापित करना और उसकी एक अलग जगह बनाना महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में, बिहार सरकार मूलतः बिहार से बनने वाले उत्पादों के लिए वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी ब्रांड बनाने हेतु एक ब्रांड इक्विटी फंड स्थापित कर सकती है। इस फंड से इन ब्रांडेड उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मार्केटिंग के लिए भी सहायता ली जा सकती है। इसमें मखाना जैसे कृषि उत्पाद और लिट्टी-चोखा व लक्ठो जैसे खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं।

मानकों, विनियमों और गुणवत्ता की बात करें तो बहुत से आयातक देश उत्पादों के लिए विशिष्ट विवरण निर्धारित करते हैं और उन विवरणों का मानकों के अनुसार सख्ती से पालन जरूरी होता है और इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना स्टेकहोल्डरों की जिम्मेदारी होती है। इस संबंध में, फाइटो-सैनिटेशन प्रमाणन, ऑर्गैनिक प्रमाणीकरण, कीटनाशक मुक्त उत्पादन के लिए कड़े परीक्षण, पैकेजिंग और लेबलिंग की जरूरत होगी। इसके लिए, सरकार कंफर्माइट यूरोपियन (सीई), चाइना कंपल्सरी सर्टिफिकेट (सीसीसी), जीएमपी आदि जैसे सांविधिक प्रमाणीकरण प्राप्त करने में हुए खर्च को रिफंड करने पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही, इन प्रमाणीकरणों से संबंधित जानकारियों के प्रसार के लिए प्रमुख उत्पादन केंद्रों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। इसमें प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने में मदद से लेकर बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहयोग की जानकारी दी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम जैसी योजनाओं के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने में भी सहायता कर सकती है, ताकि उच्च-प्रौद्योगिकी वाले निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यातक इनका लाभ उठा सकें। चूंकि ये कार्यक्रम प्रौद्योगिकी अधिग्रहण की एक निश्चित लागत को ही पूरा करते हैं, इसलिए राज्य सरकार मामले-वार आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकती है।

वित्तीय प्रोत्साहन

बिहार में निर्यात अभी उदीयमान अवस्था में है। ऐसे में राज्य के निर्यातकों को कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। ऐसा ही एक वित्तीय प्रोत्साहन ढुलाई भाड़े में सब्सिडी प्रदान करना हो सकता है। इस सब्सिडी से निर्यातकों को बुनियादी ढांचे के अभाव के चलते

अपने निर्यातों की बढ़ी लागत को कम करने में मदद मिलेगी। बजट को ध्यान में रखते हुए, ढुलाई भाड़ा सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की राशि और पात्रता जिला तथा उत्पाद-वार निर्धारित की जा सकती है।

निर्यात संवर्धन अभियान

कृषि और संबद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों, रसायन और संबद्ध उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और गारमेंट, इंजीनियरिंग सामान और पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निर्यातकों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए निर्यात पुरस्कारों की शुरुआत की जा सकती है। राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अलग से पुरस्कारों की शुरुआत की जा सकती है।

निर्यात संवर्द्धन की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य में क्लस्टरों का विकास और उन्नयन भी महत्त्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है। आवश्यक पहले कदम के रूप में राज्य को मौजूदा क्लस्टरों का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र बनाने की जरूरत है। क्लस्टरों के मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। क्षमता विकास के प्रमुख तत्त्वों में भौतिक बुनियादी ढांचे और भवनों, संस्थाओं का निर्माण तथा मानव संसाधनों का विकास शामिल होगा।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की विपणन (मार्केटिंग) विकास सहायता योजना जैसी पहलें निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों के लिए निर्यातकों के लिए मददगार साबित हुई हैं। अतः राज्य स्तर पर भी ऐसी ही योजना शुरू की जा सकती है। इस प्रकार की सहायता से निर्यातों का विशाखन करने में मदद मिल सकती है।

संस्थागत समन्वय

बिहार के समग्र आर्थिक परिवेश को इस रूप में विकसित करने की जरूरत है जो राज्य से निर्यातों को बढ़ावा देने में सक्षम हो। संबंधित राज्य मशीनरियों से बना संस्थागत ढांचा इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण हो सकता है। इस संदर्भ में, अध्ययन में बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत बिहार निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना करने की संस्तुति की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य से निर्यात निष्पादन को बढ़ावा देना होगा। इस परिषद की स्थापना राज्य सरकार, निर्यातकों और उद्योग संघों की भागीदारी से की जा सकती है। साथ ही यह परिषद विचारों तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान कर सकती है तथा निर्यातकों के सामने आने वाली परेशानियों को चिह्नित करने और उनसे निपटने के उपाय कर सकती है।

निष्कर्ष

राज्य से 40 अरब यूएस डॉलर के निर्यातों के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापार स्पर्धात्मकता बढ़ाने, नवोन्मेष को बढ़ावा देने, निर्यात वित्त की उपलब्धता बढ़ाने, ब्रांडिंग के वृहत्तर प्रयास करने और निर्यातों के लिए संस्थागत क्षमताएं बढ़ाने जैसे उपायों की जरूरत होगी। इस अध्ययन में रेखांकित की गई छह-बिंदुओं वाली रणनीति राज्य के लिए निर्यात नीति बनाने तथा वांछित परिणाम हासिल करने के लिए कार्ययोजना बनाने में मददगार होगी।

1: परिचय

भारत के पूर्वी इलाके में स्थित बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 93.6 लाख हेक्टेयर है। यह बंदरगाह विहीन राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल है।

भौगोलिक रूप से, बिहार को मोटे तौर पर दो अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है- उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों-बीच बहती है और इसे इन दो क्षेत्रों में विभाजित करती है। उत्तर का हिस्सा जलोढ़ मैदान है, लेकिन यहां खनिज संसाधन बहुत सीमित मात्रा में हैं। दक्षिणी हिस्सा भी जलोढ़ मैदान है, जहां मुख्य रूप से खेती की जाती है। यहां अल्प मात्रा में खनिज संसाधन भी हैं। कृषि उत्पादन में जहां दोनों हिस्सों का उल्लेखनीय योगदान रहता है, वहीं औद्योगिक गतिविधियां दक्षिणी बिहार में अधिक रही हैं।

आर्थिक पृष्ठभूमि

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 2011-12 से 2017-18 के दौरान 6.5 प्रतिशत की यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई। यह भारत के समग्र जीडीपी की 5.4 प्रतिशत सीएजीआर की तुलना में अधिक रही। उच्च वृद्धि दर के चलते भारत के जीडीपी में बिहार का योगदान भी बढ़ा और 2017-18 में भारत के कुल उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 2.8 प्रतिशत रहा।

यह वृद्धि बढ़ते पूंजीगत खर्च और राज्य में बेहतर होते निवेश परिवेश के चलते रही। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग द्वारा जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2017 में बिहार की स्थिति उल्लेखनीय रूप से अच्छी रही। इसमें सुधार के 12 क्षेत्रों की ओर ध्यान खींचा गया है और नियामकीय प्रक्रियाओं, नीतियों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर 405 सिफारिशें की गई हैं। इनमें श्रम नियामक, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना, संपत्ति की रजिस्ट्री, निरीक्षण सुधार, सिंगल विंडो सिस्टम, भूमि की उपलब्धता और आवंटन, निर्माण मंजूरी, पर्यावरणीय रजिस्ट्रेशन, उपयोग की मंजूरी लेना, करों का भुगतान, सूचनाओं तक पहुंच और पारदर्शिता सहित किसी व्यवसाय के पूर्ण चक्र में क्षेत्र विशेष में सुधार शामिल हैं। बिहार में व्यवसाय सुगमता संबंधी सुधारों को प्राथमिकता दी गई है और व्यवसाय सुगमता सूचकांक में बिहार का उछाल इसका प्रमाण है। बीआरएपी 2017 में बिहार का क्रियान्वयन स्कोर 81.91 प्रतिशत रहा और इसे हिमाचल प्रदेश तथा असम के साथ तेजी से बढ़ते राज्यों की श्रेणी में रखा गया।

हालिया आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक क्षमताओं के साथ-साथ लॉजिस्टिक सुविधाओं के बढ़ने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के मजबूत होने के चलते रही। वर्तमान में, राज्य में 1 इनलैंड कंटेनर डिपो; 2 एकीकृत चेक पोस्ट; 2 राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और जिला मार्गों सहित 20,068 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क; 6,870 किलोमीटर के रेल नेटवर्क सहित और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (भागीरथी-हुगली-गंगा), राष्ट्रीय जलमार्ग-37 (गंडक नदी) और कोसी नदी के साथ इनलैंड जलमार्गों के विकास की संभावनाएं हैं।

निर्यात रणनीति की जरूरत

वर्ष 2016-17 के आकलन बताते हैं कि बिहार के जीएसडीपी में वस्तु निर्यातों का हिस्सा 1.3 प्रतिशत रहा। हालांकि 2011-12 के 0.2 प्रतिशत की तुलना में यह अच्छी बढ़ोत्तरी है। तथापि, बिहार की समतुल्य अर्थव्यवस्थाओं जैसे हरियाणा (13.1 प्रतिशत हिस्सा), ओडिशा (10.8 प्रतिशत) और पंजाब (8.3 प्रतिशत) की तुलना में यह काफी कम है। यह 12.1 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से भी कम है। स्पष्ट है कि निर्यात वृद्धि से राज्य की जीएसडीपी वृद्धि को भी बल मिलेगा। निर्यात वृद्धि का रोजगारों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा **(बॉक्स 1)**।

भारत के निर्यातों में बिहार का हिस्सा भी जीडीपी, क्षेत्रफल और देश की आबादी में इसके हिस्से के अनुरूप नहीं है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा लगभग 2.9 प्रतिशत है। भारत की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत हिस्सा बिहार में है और देश के जीडीपी का 2.8 प्रतिशत बिहार का है। भारत के वस्तु निर्यातों में बिहार का हिस्सा देश के कुल वस्तु निर्यातों के 1 प्रतिशत से भी कम रहा **(चार्ट 1)**।

बॉक्स 1 : रोजगारों और वेतन पर निर्यातों का प्रभाव

निर्यात आर्थिक वृद्धि के इंजन होते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उत्पादकों के लिए बाजारों का विस्तार करने में निर्यातों की अहम भूमिका होती है, बल्कि इसलिए भी कि क्षमता सुधारों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कामगारों के कौशल पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। सामयिक विश्लेषणात्मक अध्ययन से पता चला है कि निर्यात समावेशी विकास को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं, विशेष रूप से किसी अर्थव्यवस्था में निर्यात रोजगारों से किस प्रकार जुड़े होते हैं। एक्ज़िम बैंक के अध्ययन के अनुसार, 2012-13 के दौरान भारत में कुल रोजगारों में लगभग 14.5 प्रतिशत रोजगार निर्यातों से जुड़े रहे। विश्व बैंक-अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के हालिया अध्ययन में वेतन में बढ़ोत्तरी और अनौपचारिक श्रम में कमी के संबंध में रोजगारों पर निर्यातों के सकारात्मक असर को रेखांकित किया गया है। अध्ययन के अनुसार, 1999-2011 की अवधि के आकलन से पता चलता है कि भारत से निर्यातों में प्रति श्रमिक 1,500 यूएस डॉलर की बढ़ोत्तरी से प्रति श्रमिक वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई और 12.4 मिलियन श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में जुड़े।

स्पष्ट है कि निर्यात आधारित वृद्धि की रणनीति से श्रम बाजार में ठोस परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हालांकि, हाल के समय में, बिहार में श्रम बाजार पर निर्यातों का असर बहुत मामूली रहा है। विश्लेषण बताता है कि 1999-2011 के दौरान बिहार में केवल 1.4 प्रतिशत वेतन निर्यातों से बढ़ाया जा सका है और व्यापार से अनौपचारिक श्रम में केवल 0.4 प्रतिशत कमी लाई जा सकी है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है ।

अतः एक सुदृढ़ निर्यात रणनीति श्रम बाजार में विद्यमान अंतरों और राज्य में लंबे समय से मौजूद अनौपचारिकता को कम कर सकती है। लेकिन इस रणनीति के साथ-साथ व्यापार से होने वाले लाभों को अधिक समावेशी बनाने वाली नीतियां बनाने की भी जरूरत होगी। इनमें से कुछ नीतियां (1) निर्यातों को लोगों से जोड़ना (उदाहरण के लिए, बुनियादी ढांचे और बेहतर संपर्क तथा मुक्त व्यापार के उपायों में निवेश के जरिए); (2) उत्पादन में विकृतियों को कम करना (उदाहरण के लिए, पूंजी/श्रम इनपुट में विकृतियों को कम करना, वस्तु निर्यातों में महिलाओं की भागीदारी और श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ाना); और (3) श्रमिकों का संरक्षण (उदाहरण के लिए, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश के जरिए) हो सकती हैं।

चार्ट 1 : बिहार - प्रमुख विशेषताएं

स्रोत : एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

निरंतर आर्थिक वृद्धि, निवेश के परिवेश में आते सुधार और निर्यात प्रोफाइल के विस्तार को देखते हुए इस अध्ययन में बिहार के आर्थिक प्रोफाइल और निर्यात निष्पादन की गहराई से पड़ताल की गई है और अंतरराष्ट्रीय बाजार से आने वाली मांगों के साथ इन सभी कारकों को मैप करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में निर्यातों की संभावनाओं का विश्लेषण करने के साथ-साथ बिहार से निर्यात किए जा सकने वाले डायनैमिक उत्पादों और उन उत्पादों के लिए अग्रणी बाजारों को चिह्नित करने का भी प्रयास किया गया है, ताकि निर्यातकों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके और सरकार इस दिशा में सुधार के प्रयास तेज कर सके। साथ ही अध्ययन में राज्य स्तर पर व्यापार स्पर्धात्मकता और निर्यातों के लिए राज्य में अधिक अनुकूल परिवेश विकसित करने की रणनीतियां भी सुझाई गई हैं।

2: व्यापक आर्थिक प्रोफाइल

जीएसडीपी किसी राज्य की तरक्की, आर्थिक विकास तथा उसकी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से होने वाली आय के बराबर होता है। पूंजी मूल्यह्रास / उपभोग को बिना समायोजित किए मूल्य वर्धन अनुमान को सकल मूल्य योजन (जीवीए)[1] कहा जाता है।

बिहार के जीएसडीपी में स्थिर कीमतों (2011-12) पर 2012-13 से 2015-16 के दौरान भारत के जीडीपी वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, 2016-17 के बाद से राज्य के जीएसडीपी में भारत के जीडीपी से अधिक मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। राज्य का जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर 2017-18 में बढ़कर 361504.3 करोड़ रुपये हो गया और इसमें 11.3 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। ये रुझान राज्य में सकारात्मक आर्थिक प्रगति की ओर संकेत करते हैं **(तालिका 1)**।

हालिया दौर में राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य के सेवा क्षेत्र में 2011-12 से 2017-18 के दौरान जीवीए में 8.2 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई **(तालिका 2)**। तदनुसार, बिहार के जीवीए में सेवाओं की हिस्सेदारी 2011-12 की 55.5 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 62.3 प्रतिशत हो गई, जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों की हिस्सेदारी 2011-12 की 25.7 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 19.7 प्रतिशत रह गई। इसी अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.8 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत रह गई **(तालिका 3)**।

तालिका 1 : भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये)

वर्ष	बिहार		भारत	
	जीएसडीपी-स्थिर (2011-12)	वृद्धि प्रतिशत	जीएसडीपी-स्थिर (2011-12)	वृद्धि प्रतिशत
2011-12	247144		8736329	
2012-13	256851	3.9	9213017	5.5
2013-14	269650	5.0	9801370	6.4
2014-15	279482	3.6	10527674	7.4
2015-16	295622	5.8	11386145	8.2
2016-17	324778	9.9	12196006	7.1
2017-18	361504	11.3	13010843	6.7

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

तालिका 2 : बिहार के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य योजन (करोड़ रुपये)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	सीएजीआर
कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	62067	68040	59516	59349	60754	66864	67779	1.5%
उद्योग	45540	39555	51668	56824	58104	60483	62021	5.3%
सेवा	134092	144015	149478	153245	166366	187613	214947	8.2%
कुल जीवीए	241698	251609	260662	269418	285223	314959	344747	6.1%

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

[1] केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

तालिका 3 : बिहार के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य योजन का हिस्सा (प्रतिशत)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	25.7	27.0	22.8	22.0	21.3	21.2	19.7
उद्योग	18.8	15.7	19.8	21.1	20.4	19.2	18.0
सेवा	55.5	57.2	57.3	56.9	58.3	59.6	62.3

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

हाल के समय में राज्य में अच्छी वृद्धि के चलते अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि और विकास से कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी। कई मुद्रास्फीति संकेतक हैं जो सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि को मापते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एक निश्चित आबादी द्वारा उपभोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली, ली जाने वाली और उनके लिए भुगतान की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में समय के साथ आने वाले बदलावों को मापता है।

राज्य और भारत के स्तर पर सीपीआई (बेस : 2012=100) की तुलना, बिहार में औसत कीमतों के उच्च स्तर की ओर इंगित करती है। अखिल भारतीय स्तर पर मार्च 2018 में जहां सीपीआई में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं बिहार के लिए 4.6 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि रही **(चार्ट 2)**। बिहार और भारत में अक्टूबर 2016 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान, सीपीआई में समान अस्थिरता रही है। दोनों में ही 2.7 बिंदुओं का मानक विचलन रहा। बिहार में प्रतिस्पर्धी उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए मुद्रास्फीति का कम और स्थिर बने रहना महत्त्वपूर्ण होगा।

प्रमुख आर्थिक गतिविधियां

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

बिहार के कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन क्षेत्र में 2011-12 से 2017-18 के दौरान जीवीए में 1.5 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई। मत्स्यपालन और जलीय कृषि एवं पशुधन में इस अवधि के दौरान क्रमशः 9.3 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई **(तालिका 4)**। इस क्षेत्र में 2017-18 के दौरान, 11.1 प्रतिशत के जीवीए के साथ सबसे बड़ा हिस्सा कृषि खंड का रहा। पशुधन 5.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ इस क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा खंड रहा, जो राज्य में बड़े पशुपालन क्षेत्र की ओर संकेत करता है **(चार्ट 3)**।

चार्ट 2 : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मासिक उतार-चढ़ाव (बेस : 2012=100)

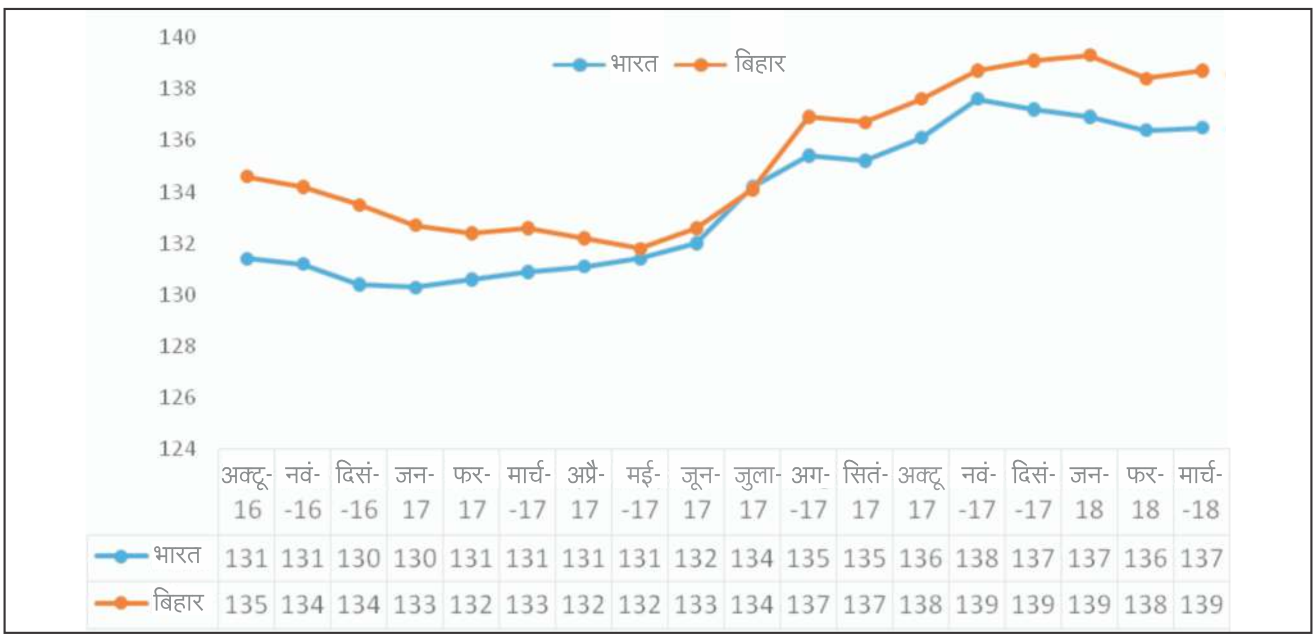

स्रोत : आरबीआई-भारतीय अर्थव्यवस्था का डाटाबेस, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

तालिका 4 :बिहार के कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन क्षेत्र में जीवीए (करोड़ रुपये)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	सीएजीआर (वित्त12-वित्त18)
फसलें	42608	47493	37107	35254	35348	40021	38294	-1.8%
पशु	12028	12525	14008	15359	16281	17556	19312	8.2%
वानिकी और लॉगिंग	4187	4253	4330	4218	4353	4492	4637	1.7%
मत्स्यपालन और जलीय कृषि	3244	3768	4071	4518	4772	4793	5535	9.3%
कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	62067	68040	59516	59349	60754	66864	67779	1.5%

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

औद्योगिक क्षेत्र

बिहार में औद्योगिक क्षेत्र छोटा-सा है। यह स्थिति तब है, जब राज्य में किफायती औद्योगिक श्रम संसाधन बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं और जीवीए में इनका हिस्सा क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत है। निर्माण क्षेत्र में जहां 2011-12 से 2017-18 के दौरान 1.5 प्रतिशत की मामूली सीएजीआर दर्ज की गई, वहीं विनिर्माण क्षेत्र में 9.9 प्रतिशत की अच्छी सीएजीआर दर्ज की गई। औद्योगिक क्षेत्र में 45.0 प्रतिशत की अधिकतम सीएजीआर खनन और उत्खनन खंड में दर्ज की गई **(तालिका 5)**।

भविष्य में बिहार, विशेष रूप से कृषि आधारित उद्योगों के लिए एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सकता है और इसके लिए पर्याप्त क्षमता है। विनिर्माण खंड पहले से ही वृद्धि के पथ पर अग्रसर है और वृद्धि की इस गति के बने रहने की उम्मीद है।

चार्ट 3 : प्रमुख आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल मूल्य योजन (2017-18)

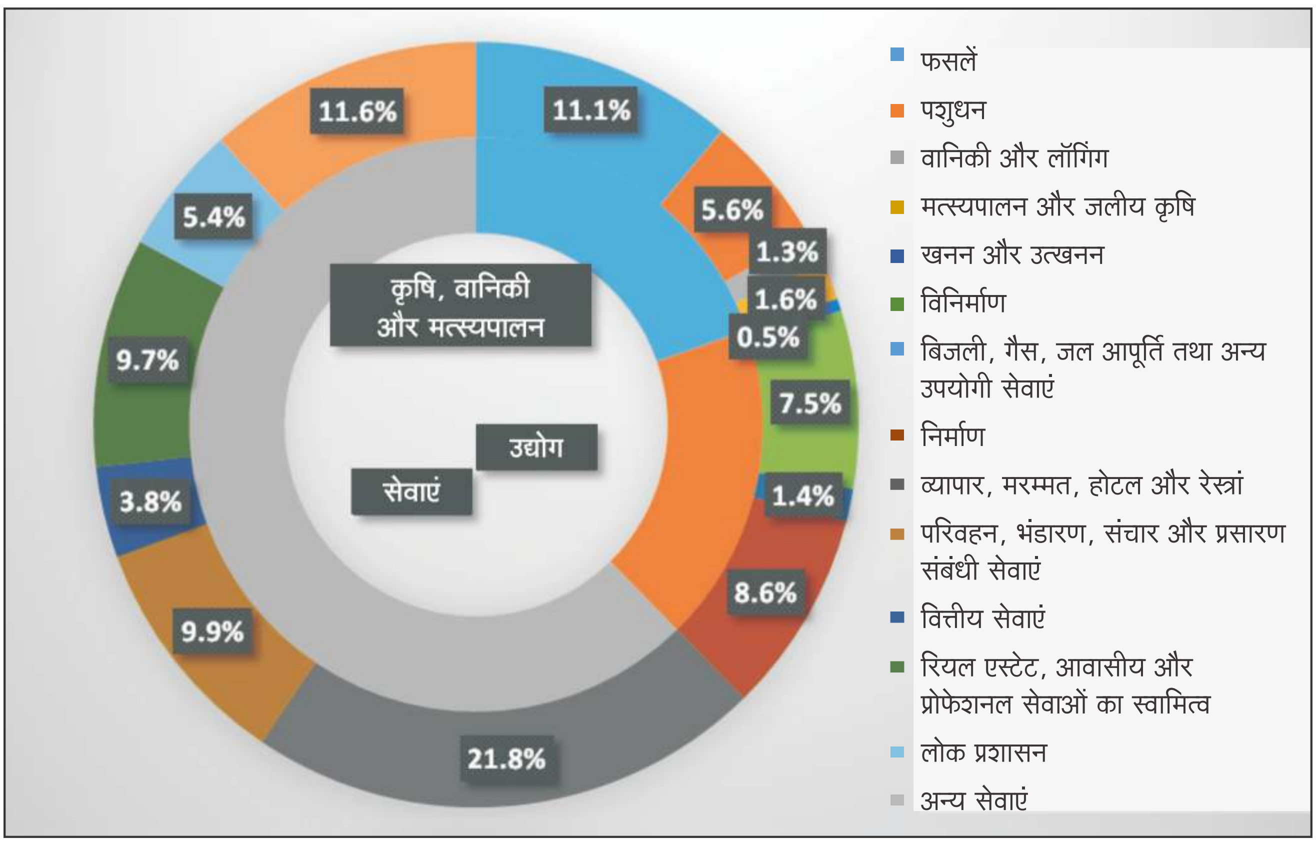

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

तालिका 5 : बिहार के उद्योग क्षेत्र में जीवीए (करोड़ रुपये)

क्षेत्र	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**सीएजीआर** (वित्त12-वित्त18)
खनन और उत्खनन	199	216	1386	577	1789	1787	1849	45.0%
विनिर्माण	14666	9714	18893	25958	23371	25151	25835	9.9%
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	3659	4017	4128	4270	4275	4587	4753	4.5%
निर्माण	27017	25608	27261	26019	28668	28957	29584	1.5%
उद्योग	**45540**	**39555**	**51668**	**56824**	**58104**	**60483**	**62021**	5.3%

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

सेवाएं क्षेत्र

सेवा क्षेत्र में विचाराधीन अवधि के दौरान प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में मूल्य योजन में योगदान के मामले में व्यापार और मरम्मत सेवा खंड (राज्य के जीवीए में 20.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी) अग्रणी रहे। इसके बाद परिवहन, भंडारण और संचार (9.9 प्रतिशत), और रियल एस्टेट तथा प्रोफेशनल सेवाओं (9.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। सेवा क्षेत्र में 2011-12 से 2017-18 के दौरान हुई वृद्धि के प्रमुख कारकों में वायु परिवहन (35.6 प्रतिशत); सड़क परिवहन (13.3 प्रतिशत); और व्यापार और मरम्मत सेवाएं (9.8 प्रतिशत) **(तालिका 6)** शामिल रहे।

तालिका 6 : बिहार के सेवा क्षेत्र में जीवीए (करोड़ रुपये)

क्षेत्र	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**सीएजीआर (वित्त12-वित्त18)**
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्त्रां	**43904**	**46729**	**45683**	**42626**	**50421**	**61638**	**75185**	**9.4%**
व्यापार और मरम्मत सेवाएं	41109	43945	42775	39877	47496	58547	71947	9.8%
होटल और रेस्त्रां	2796	2784	2908	2749	2925	3091	3238	2.5%
परिवहन, भंडारण, संचार व प्रसारण से जुड़ी सेवाएं	**17545**	**20372**	**23473**	**26054**	**28375**	**29996**	**34212**	**11.8%**
रेलवे	2751	3346	3965	4092	4070	3926	4359	8.0%
सड़क परिवहन	8405	9962	11373	12678	14010	15678	17788	13.3%
जल परिवहन	49	24	15	17	18	20	22	-12.4%
वायु परिवहन	31	54	38	64	126	139	192	35.6%
परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाएं	893	1043	1202	1344	1499	1688	1896	13.4%
भंडारण	74	79	71	75	80	83	85	2.3%
प्रसारण से संबंधित संचार और सेवाएं	5342	5863	6808	7785	8572	8463	9871	10.8%
वित्तीय सेवाएं	**8839**	**9580**	**10273**	**11653**	**12393**	**11845**	**13259**	**7.0%**
रियल एस्टेट, आवास और प्रोफेशनल सेवाओं का स्वामित्व	**28023**	**28686**	**29819**	**30739**	**30032**	**31365**	**33454**	**3.0%**
लोक प्रशासन	**13587**	**13350**	**12752**	**13171**	**13132**	**17522**	**18729**	**5.5%**
अन्य सेवाएं	**22193**	**25297**	**27478**	**29002**	**32012**	**35248**	**40108**	**10.4%**
सेवाएं	**134092**	**144015**	**149478**	**153245**	**166366**	**187613**	**214947**	**8.2%**

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

राज्य में संसाधनों की स्थिति

राज्य की संसाधन स्थिति के विश्लेषण से उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जा सकता है जिनमें राज्य प्रतिस्पर्धी लाभ की स्थिति में है। इससे राज्य में निहित निर्यात क्षमता को चिह्नित करने और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने हेतु रणनीति तैयार करने में मदद मिल सकती है।

कृषि

कृषि क्षमता को पूरी तरह समझने के लिए राज्य के भीतर विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों को चिह्नित करना पहला कदम होगा। भारत में 1987 में मिट्टी, तापमान, वर्षा और जल संसाधनों के आधार पर 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों को चिह्नित किया गया था। बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (एनएआरपी) के तहत इन क्षेत्रों को 126 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया।

बिहार भौगोलिक रूप से एक कृषि-जलवायु क्षेत्र- मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है । इसके तीन मुख्य कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं जो फसल चक्र में विविधता बनाए रखने में सहायक हैं। ये क्षेत्र हैं- अंचल 1 - उत्तर जलोढ़ मैदान, अंचल 2 - उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, और अंचल 3 - दक्षिण जलोढ़ मैदान (जिसे अंचल 3 ए और अंचल 3 बी में वर्गीकृत किया गया है) **(तालिका 7)**।

खनिज

औद्योगिक गतिविधियों में खनिज संसाधनों का सर्वाधिक महत्त्व होता है। इनका इस्तेमाल विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है और ये किसी भी अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में मददगार होते हैं। बिहार में वर्तमान में ऐसे कई खनिज संसाधन हैं, जिनका या तो बहुत कम दोहन किया गया है या जो अभी तक अदोहित हैं।

बिहार में भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में चूना पत्थर; नवादा जिले में अभ्रक; भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा जिलों में क्वाट्र्ज / सिलिका रेत; रोहतास जिले में पायराइट्स; लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिलों में क्वार्टजाइट; मुंगेर में टाल्क / सोपस्टोन / स्टीटाइट जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। अन्य मौजूद खनिजों में मुंगेर और रोहतास जिलों में बॉक्साइट; भागलपुर और मुंगेर जिलों में चीनी मिट्टी; गया, जमुई और पूर्णिया जिलों में फेल्डस्पार; भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई जिलों में ग्रेनाइट शामिल हैं।

बिहार के जमुई जिले में धातु और मिश्र धातु के रूप में सोना प्रमुख रूप से मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के कुल स्वर्ण अयस्क भंडार का 44 प्रतिशत हिस्सा बिहार में ही है। हालांकि, खनन और प्रसंस्करण की आर्थिक व्यवहार्यता ने प्राकृतिक संसाधनों के विकास को सीमित कर दिया है। सल्फर और पायराइट संसाधनों के राष्ट्रीय भंडार में 95 प्रतिशत हिस्से के साथ बिहार भारत का प्रमुख खनिज संसाधन संपन्न राज्य है।

राज्य में उत्पादित प्रमुख खनिज चूना पत्थर है, जिसके लिए राज्य में केवल एक खदान रिपोर्ट की गई थी। राज्य में 2016-17 के दौरान सूक्ष्म खनिजों के उत्पादन का मूल्य 4,272 करोड़ रुपये आंका गया था।

मानव पूँजी

भारत की 8.8 प्रतिशत आबादी बिहार में रहती है। राज्य की वृद्धि क्षमता को फलीभूत करने के लिए यह आबादी एक अच्छा मानव पूँजी आधार है। राज्य में किफायती औद्योगिक श्रम संसाधनों का एक बड़ा आधार है, जो इसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में निवेश के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। राज्य शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मानव पूँजी आधार की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी ध्यान दे रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कई सुधार हुए हैं। वर्ष 2001 से 2011 तक 10 साल की अवधि में, साक्षरता दर 47.0 प्रतिशत से बढ़कर 61.8 प्रतिशत हो गई है। यद्यपि राज्य में साक्षरता दर अब भी 72.9 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन बिहार में महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही शिक्षा में लैंगिक अंतर में भी कमी आई है।

तालिका 7 : बिहार में कृषि-जलवायु अंचल

एनएआरपी अंचल	जिले	प्रमुख फसलें
उत्तर जलोढ़ मैदान	पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर	चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना, आम, लीची
उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान	मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय और सहरसा	मक्का, जूट, अनानास
दक्षिण जलोढ़ मैदान	भोजपुर, रोहतास, पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा, मुंगेर और भागलपुर	चावल, गेहूं, आलू, चना, आम, अमरूद

स्रोत : बिहार सरकार

संभावनाएं

बिहार सक्रिय नीति, भौगोलिक स्थिति और बड़े संसाधन आधार के चलते भारत के आर्थिक उत्पादन में धीरे-धीरे एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है। राज्य की दीर्घकालिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए बिहार को अपने जीएसडीपी के प्रमुख योगदानकर्ताओं में तेजी से विशाखन लाने की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र को हर तरफ से सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही, इस क्षेत्र से निर्यातों को भी उपयुक्त संस्थागत समन्वय, क्षमता विकास, बाजार सहायता और उपयुक्त प्रोत्साहन ढांचे के माध्यम से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

3: आर्थिक परिदृश्य

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

बिहार में तीन कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यहां की मिट्टी भी अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग है। इसलिए राज्य में कृषि और बागबानी में काफी विविधता की संभावनाएं हैं। इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। राज्य के जीवीए में इसका करीब 19.7 प्रतिशत हिस्सा है। रोजगार के मामले में इस क्षेत्र का योगदान और भी उल्लेखनीय है, क्योंकि राज्य की लगभग 77 प्रतिशत आबादी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न है। इस क्षेत्र का महत्त्व इस आंकड़े से भी समझा जा सकता है कि बिहार की लगभग 56.55 प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। बक्सर, नालंदा, मधेपुरा, भोजपुर और सीवान जैसे राज्यों में निवल खेतिहर जमीन काफी अधिक है।

विश्लेषण बताते हैं कि बिहार में तिरहुत प्रमंडल प्रमुख खेतिहर इलाका है। मुजफ्फरपुर जिला और पड़ोसी जिले पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा बिहार के अग्रणी कृषि जिलों में गिने जाते हैं।

उत्पादन परिदृश्य

कृषि क्षेत्र में बिहार के दबदबे को देखना है तो भारत के कृषि उत्पादन में बिहार के योगदान को देखा जा सकता है। बिहार का भू-भाग देश के कुल भू-भाग का 2.9 प्रतिशत है। लेकिन कुल अनाज उत्पादन के भू-भाग का 5.2 प्रतिशत हिस्सा बिहार में ही है और कुल अनाज उत्पादन का 6.7 प्रतिशत उत्पादन भी इसी राज्य में होता है। देश में अनाज उत्पादन के मामले में बिहार आठवें और तिलहन उत्पादन में छठे स्थान पर है। वस्तुतः बिहार विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष अनाज उत्पादक राज्यों में आता है। 2016-17 के दौरान, देश के कुल मक्का उत्पादन का 14.6 प्रतिशत बिहार में ही हुआ। इसी प्रकार कुल धान उत्पादन का 7.5 प्रतिशत, गेहूं उत्पादन का 6.1 प्रतिशत और गन्ना उत्पादन का 4.3 प्रतिशत बिहार में हुआ। बिहार जूट और मेस्टा का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां भारत के कुल उत्पादन का 14.8 प्रतिशत उत्पादन होता है **(तालिका 8)**।

राज्य के फसल चक्र में अनाजों का प्रभुत्व है। कुल फसलोत्पादन के 85 प्रतिशत से अधिक में अनाजों की खेती की जाती है। लेकिन अधिकांश अनाजों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है। तथापि मक्के और दलहन में उच्च उत्पादकता के चलते राज्य का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा।

तालिका 8 : बिहार और भारत के कृषि उत्पादन का तुलनात्मक विवरण (2016-17)
(क्षेत्र हजार हेक्टेयर में; उत्पादन हजार टन में; पैदावार किलोग्राम / हेक्टेयर में)

फसल	बिहार			बिहार का हिस्सा		अखिल भारतीय पैदावार
	क्षेत्र	उत्पादन	पैदावार	क्षेत्र	उत्पादन	
चावल	3339.8	8238.8	2467	7.7%	7.5%	2551
गेहूँ	2105.8	5985.8	2843	6.9%	6.1%	3216
मक्का	720.9	3845.7	**5335**	7.3%	14.6%	2657
दलहन	493.1	461.7	**936**	1.7%	2.0%	780
जौ+मोटा अनाज	50.1	57.6	1150	0.3%	0.3%	1203
कुल खाद्यान्न	6709.7	18589.6	**2771**	5.2%	6.7%	2154
तिलहन	108.9	125.8	1156	0.4%	0.4%	1225
गन्ना	237.0	13040.0	55021	5.4%	4.3%	69,705
जूट/मेस्टा	0.1	1.6	**2626**	14.2%	14.8%	2529

नोट : बोल्ड आंकडे पैदावार संबंधी आंकड़े वे हैं, जहां पैदावार अखिल भारतीय स्तर से अधिक रही।
स्रोत : कृषि विभाग (बिहार सरकार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

चार्ट 4 : खाद्यान्न बुवाई के क्षेत्रफल और उत्पादन में अंचल-वार हिस्सा (2016-17)

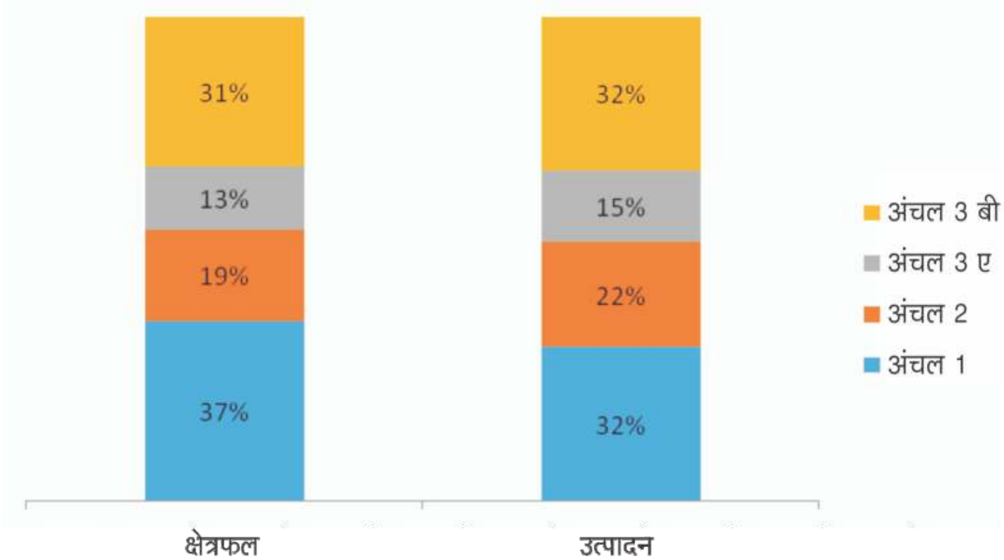

स्रोत : कृषि विभाग (बिहार सरकार), एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

अंचल 1 और अंचल 3बी में खाद्यान्नों की जोत भूमि सबसे अधिक क्रमशः 37 प्रतिशत और 31 प्रतिशत है। अंचल 1 में खेती के लिए तिरहुत अग्रणी प्रमंडल है, वहीं अंचल 3बी में पटना और गया प्रमुख प्रमंडल हैं। अंचल 1 में उत्पादकता अपने आप में एक चुनौती है और राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में इसका हिस्सा 32 प्रतिशत ही है **(चार्ट 4)**। अंचल 2 और अंचल 3ए में उत्पादकता अधिक है। यहां अंचल 1 और अंचल 3बी की तुलना में पैदावार उल्लेखनीय रूप से अधिक रहती है।

बागबानी

अलग-अलग कृषि जलवायु के चलते राज्य में बागबानी को भी प्रोत्साहन मिला है। इसी के चलते फलोत्पादन में बिहार भारत का आठवां सबसे बड़ा और सब्जी उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारत के कुल सब्जी उत्पादन का 8.6 प्रतिशत और कुल फलोत्पादन का 5.3 प्रतिशत तथा शहद उत्पादन का 9.5 प्रतिशत बिहार में ही होता है **(तालिका 9)**।

बिहार मखानों का भी अग्रणी उत्पादक राज्य है। खाद्यान्न उत्पादन की ही तरह अंचल 1 में फलों और सब्जियों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अंचल 3बी का स्थान आता है।

तालिका 9 : बिहार और भारत के बागबानी उत्पादन का तुलनात्मक विवरण (2017-18)
(क्षेत्र हजार हेक्टेयर में; उत्पादन हजार टन में)

श्रेणी	उत्पादन मूल्य		भारत में हिस्सा	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
फल	296.7	5117.1	4.6%	5.3%
सब्जियां	824.6	15863.2	8.0%	8.6%
वृक्षारोपण	11.4	52.9	0.3%	0.3%
एरोमैटिक और औषधीय	4.1	1.2	0.6%	0.1%
पुष्प	0.6	5.5	0.2%	0.3%
मसाले	0.1	8.3	0.0%	0.2%
शहद	10.5	10.0	0.1%	9.5%
कुल	**1145.5**	**21060.5**	**4.5%**	**6.8%**

स्रोत : राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

सब्जी खंड में, बिहार लौकी का सबसे बड़ा, फूल गोभी का दूसरा सबसे बड़ा, पत्ता गोभी और आलू का तीसरा सबसे बड़ा और बैंगन, मूली और भिंडी का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा लीची उत्पादक भी बिहार ही है, जिसका भारत के कुल लीची उत्पादन में 24.1 प्रतिशत हिस्सा है। यह अमरूदों (10.2 प्रतिशत) का तीसरा सबसे बड़ा और आमों (7.5 प्रतिशत)[2] का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।

बिहार का एक और अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पाद है मखाना, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग है। यह दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में सर्वाधिक होता है। एक अनुमान के अनुसार, देश में सालाना 50,000 मीट्रिक टन (एमटी) मखानों का उत्पादन होता है, जिसमें से घरेलू स्तर पर सिर्फ 2 प्रतिशत की ही खपत होती है। अतः निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में इसकी उपलब्धता रहती है। एपीडा के अनुसार, मखानों की वैश्विक आयात मांग लगभग 4 अरब डॉलर की आंकी गई है। आने वाले समय में बिहार मखानों जैसे ग्लूटेन मुक्त प्रोटीन सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल उत्पादों के मूल्य वर्धन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

पशुपालन

पशु गणना 2012 के अनुसार, राज्य में पशुओं की कुल संख्या 329.39 लाख है। इनमें से दुधारू पशुओं की संख्या 60 प्रतिशत है। कुल पशुधन संसाधनों के मामले में बिहार पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। इसी प्रकार, बकरियों की संख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा, सूअरों की संख्या के मामले में चौथा सबसे बड़ा और गाय-भैंसों की संख्या के लिहाज से छठा सबसे बड़ा राज्य है।

विपुल पशुधन के चलते बिहार घरेलू खपत, प्रसंस्करण और निर्यातों के लिए मांस के प्रमुख उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, देश के कुल मांस उत्पादन का 4.5 प्रतिशत और कुल दुग्ध उत्पादन का 5.2 प्रतिशत बिहार में ही होता है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान दुग्ध उत्पादन में बिहार ने 6.45 प्रतिशत की अच्छी सीएजीआर दर्ज की है। यह राज्य में दुग्ध उद्योग में प्रगतिशील त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे को अपनाने के कारण संभव हुआ है। राज्य में 2013-14 से 2017-18 के दौरान मांस उत्पादन में भी 4.11 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई है **(तालिका 10)**।

इसके अतिरिक्त, विपुल पशुधन के साथ-साथ राज्य में बहने वाली नदियां बिहार में अंतर्देशीय मत्स्यपालन के अवसर प्रदान करती हैं। परिणामतः बिहार की अर्थव्यवस्था में मत्स्यपालन का भी उल्लेखनीय योगदान रहता है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान, राज्य में मत्स्योत्पादन में 7.97 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई। इस अच्छी वृद्धि के चलते 2017-18 में बिहार मत्स्योत्पादन में 7.4 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया।

तालिका 10 : बिहार में पशुधन और मत्स्योत्पादन

वर्ष	दूध (लाख टन)	अंडे (करोड़)	ऊन (लाख किलो)	मांस (लाख टन)	मछली (लाख टन)
2013-14	71.97	93.08	2.71	2.92	4.32
2014-15	77.75	98.35	2.78	2.94	4.79
2015-16	82.88	100.21	2.4	3.02	5.07
2016-17	87.1	111.17	2.81	3.26	5.09
2017-18	92.41	121.85	2.98	3.43	5.87
सीएजीआर	6.45	6.97	2.40	4.11	7.97

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19

[2] आंकड़े यथा 2016-17

तालिका 11 : बिहार में औद्योगिक उत्पादन का परिदृश्य (2015-16)

विनिर्माण गतिविधि	उत्पादन का सकल मूल्य (रु. लाख)	भारत के उत्पादन के सकल मूल्य में हिस्सा (%)	सकल मूल्य योजन (रु. मिलियन)	भारत के सकल मूल्य योजन में हिस्सा (%)
कुल	***477343.8***	***0.7***	***60834.1***	***0.5***
कोक और रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पाद	218817.9	2.6	13634.3	0.8
खाद्य उत्पाद	119516.8	1.4	14363.3	1.7
मूल धातु	40680.7	0.5	607.1	0.1
अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद	17806.6	0.8	3665.4	0.7
प्रकाशन गतिविधियां	14355.7	21.0	8360.7	28.5
तम्बाकू उत्पाद	13763.1	2.9	10963.7	5.7
पेय पदार्थ	7173.2	1.0	1887.8	1.1
कागज और कागज के उत्पाद	4911.1	0.5	1281.8	0.8
रबर और प्लास्टिक उत्पाद	4825.0	0.2	592.7	0.1

स्रोत : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

औद्योगिक क्षेत्र

बिहार में औद्योगिक क्षेत्र अभी उदीयमान अवस्था में है। वर्ष 2015-16 में भारत के कुल उत्पादन के सकल मूल्य का लगभग 0.7 प्रतिशत और देश के सकल मूल्य योजन में लगभग 0.5 प्रतिशत बिहार से रहा। कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य उत्पाद और मूल धातुएं राज्य के प्रमुख औद्योगिक खंड हैं। कोक और रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन का देश के सकल मूल्य योजन में लगभग 2.6 प्रतिशत हिस्सा रहा। भारत में प्रकाशन गतिविधियों के सकल मूल्य योजन में बिहार का हिस्सा 21 प्रतिशत रहा। (तालिका - 11)

कोक और रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पाद

कोक और रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पाद बिहार में सबसे बड़े औद्योगिक उत्पादन की श्रेणी में आते हैं। भारत की 23 और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 9 रिफाइनरियों में से एक बेगूसराय की बरौनी रिफाइनरी के चलते रिफाइन्ड पेट्रोलियम उद्योग बिहार के अग्रणी उद्योगों में गिना जाता है। रूस और रोमानिया के सहयोग से बनी बरौनी रिफाइनरी 1964 में चालू हुई थी। शुरुआत में इसे असम से न्यून सल्फर वाले कच्चे तेल के प्रसंस्करण के लिए डिजाइन किया गया था। समय के साथ, रिफाइनरी का उन्नयन होता गया और आज यह उच्च सल्फर वाले कच्चे तेल के प्रसंस्करण में भी सक्षम है। इस रिफाइनरी की क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और 2017-18 में इसकी 97 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया।

यह रिफाइनरी बिहार के प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में से एक बन गई है और इससे सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसमें पेट्रोरसायन और रसायन उद्योगों का विकास शामिल है। उदाहरण के लिए, ग्रेफाइट इंडिया लिमिडटेड के कोक प्रभाग ने बरौनी में कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के विनिर्माण के लिए लगभग 30,000 टन सालाना क्षमता वाली ईकाई स्थापित की है।

राज्य में कृषि-रसायनों और उर्वरक खंड में भी कई कंपनियां हैं। कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियों ने राज्य में अपनी ईकाइयां स्थापित की हैं।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

आर्थिक गतिविधि के एक खंड के रूप में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों के बीच बड़े ही अनूठे ढंग से स्थापित उद्योग है और इसमें राज्य के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित होने की तमाम संभावनाएं हैं।

बिहार प्राथमिक रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए यहां बेहतरीन कृषि और पशु उत्पादन है। इन संभावनाओं को देखते हुए, बिहार सरकार ने राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को इस उम्मीद से प्राथमिकता का दर्जा दिया है कि यह उद्योग राज्य के औद्योगीकरण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र के उद्यमियों को कई तरह के प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। इनमें पूँजीगत सब्सिडी, बुनियादी ढांचागत विकास, बिजली पर सब्सिडी, करों में छूट, ब्याज अनुदान, शुल्कों में छूट, भूमि संबंधी रियायतें और शोध एवं विकास (आर एंड डी) तथा प्रौद्योगिकी संबंधी प्रोत्साहन शामिल हैं। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित उद्योग मित्र द्वारा मक्का प्रसंस्करण, फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण तथा पोल्ट्री एवं मत्स्य प्रसंस्करण को इस क्षेत्र में प्राथमिकता वाले खंडों में शामिल किया गया है।

वर्तमान में, राज्य में गन्ना कृषि आधारित प्रमुख उद्योग है। राज्य में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें से नौ निजी क्षेत्र में हैं। राज्य में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना ने उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन प्रक्रिया में चीनी के प्रतिशत में सुधार लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (कॉम्फेड) का बिहार के डेयरी उद्योग के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। कॉम्फेड की स्थापना "आणंद" मॉडल के अनुरूप राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेंसी के रूप में 1983 में हुई थी। यह एक संगठित दुग्ध प्रसंस्करण सहकारी संघ है, जो विभिन्न जिला स्तरीय सहकारी ईकाइयों से दूध जुटाकर उसका प्रसंस्करण करता है और उसे बाजार में बेचता है।

कॉम्फेड ने बिहार में थ्री-टियर सहकारी ढांचे की शुरुआत की। इस व्यवस्था में ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी, जिला स्तर पर दुग्ध संघ और राज्य स्तर पर दुग्ध मंडल होते हैं। कॉम्फेड के अंतर्गत, वर्ष 2017-18 तक 21,002 दुग्ध सहकारी सोसायटियां संगठित थीं। कॉम्फेड दूध जुटाने से लेकर डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग और पशुसेवाओं संबंधी विभिन्न कार्य करता है। यह अपने सदस्यों को प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला, प्रशिक्षण आदि के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इसने अपने विभिन्न उत्पादों के लिए "सुधा" नाम से अच्छी ब्रांड वैल्यू भी बनाई है। अब अंतरराष्ट्रीय

चार्ट 5 : टेक्सटाइल, अपैरल और लेदर क्षेत्र में निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र

बुनाई / सिलाई	अपैरल और होम टेक्सटाइल उत्पादन	बनाना फाइबर / जूट फाइबर	चमड़ा / कृत्रिम चमड़ा और वैकल्पिक सामग्री
•पावरलूम और बुनाई •बने बनाए कपड़ों का उत्पादन	• बुने हुए अपैरल का विनिर्माण • होजरी उत्पादों का विनिर्माण • कालीन और अन्य होम टेक्सटाइल	• बनाना फाइबर प्रसंस्करण के लिए एकीकृत ईकाइयां और बनाना फाइबर से उत्पादों का विनिर्माण • जूट फाइबर के प्रसंस्करण के लिए एकीकृत ईकाइयां और जूट फाइबर से उत्पादों का विनिर्माण	•गारमेंट्स/ जूते-चप्पलों का विनिर्माण •फर्नीचर, ऑटोमोबाइल सामग्री का विनिर्माण •चमड़े की वस्तुओं का विनिर्माण

स्रोत : उद्योग मित्र, उद्योग विभाग, बिहार सरकार

बाजार में पहुंच बनाने के लिए इस सुधा ब्रांड की मार्केटिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में करने की जरूरत है।

टेक्सटाइल

टेक्सटाइल उद्योग का योगदान 2015-16 में बिहार के कुल औद्योगिक उत्पादन में मामूली ही रहा। तथापि, राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बड़ी संख्या में श्रम की उपलब्धता के चलते टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास की अच्छी संभावना है।

बिहार में लगभग 1 लाख बुनकरों का बड़ा समुदाय है। सूत कातना और उसका प्रसंस्करण करना तथा परिधान बनाना इन लोगों का परंपरागत काम है और आजीविका का पारंपरिक स्रोत है। टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए संसाधन आधार की बात की जाए तो बिहार जूट और रेशम (सिल्क) का देश में प्रमुख उत्पादक राज्य है। यह देश में दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। राज्य में रेशम उत्पादन के लिए रेशमकीट पालन का एक स्थापित उद्योग है। कच्चे रेशम का उत्पादन 2016-17 में 77 टन रहा और राज्य में तीन तरह के सिल्क का उत्पादन किया गया- मलबेरी सिल्क, तसर सिल्क और एरी सिल्क। भागलपुर का तसर सिल्क बिहार की अनूठी कमोडिटी है, जिसके उत्पाद महंगे मिलते हैं।

राज्य में रोजगारों और आजीविका के मामले में इस क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए टेक्सटाइल, अपैरल और लेदर क्षेत्र में निवेश के लिए विभिन्न खंडों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

बिहार के टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र में हथकरघा (हैंडलूम) एक महत्त्वपूर्ण खंड है। राज्य में 1089 प्राथमिक सहकारी सोसायटियां हैं, जो लगभग 15,000 हथकरघा ईकाइयों का प्रबंधन संभालती हैं। तालिका 12 में राज्य के विभिन्न जिलों के प्रमुख हथकरघा उत्पादों की सूची दी गई है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न जिलों को उन्नत सुविधाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ और अधिक संगठित क्लस्टरों के रूप में विकसित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए भागलपुर को मेगा हथकरघा क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। नवादा और डेहरी में दो ब्लॉक-स्तरीय क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। मारंगा में एक अन्य जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। इनसे राज्य में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

तालिका 12 : जिला-वार प्रमुख हथकरघा उत्पाद

जिले	हथकरघा उत्पाद
भागलपुर	रेशम (सिल्क), कॉटन, फर्निशिंग कपड़ा, स्टेपल चादर, निर्यात योग्य रेशम, सूती कपड़ा
बांका	तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशम का कपड़ा
गया	सूती और रेशमी कपड़ा
नालंदा	सजावटी पर्दे,बिस्तर कवर, आंतरिक सजावटी सामग्री, सजावटी कपड़े
नवादा	तसर रेशम, महिलाओं की पोशाक संबंधी सामग्री
दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी	महीन सूती लंबा कपड़ा, धोती, झालर
औरंगाबाद, रोहतास	ऊनी कंबल, ऊनी कालीन, और साड़ी
कैमूर	ऊनी कालीन, बनारसी साड़ी
पटना, सीवान	सूती कपड़ा, फर्निशिंग कपड़ा
पूर्णिया, कटिहार	जूट बैग, जूट-मिश्रित सामग्री, आंतरिक सजावटी सामग्री

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2019

पर्यटन

बिहार की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए राज्य में पर्यटन क्षेत्र से अच्छी विदेशी मुद्रा आय की संभावना है। इस क्षेत्र में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसे प्रतिस्पर्धी मजबूती प्रदान करती है। यह सांस्कृतिक समृद्धि बिहार ने इतिहास से हासिल की है, जिसमें यह राज्य धार्मिक विकास के केंद्र के रूप में दर्ज है। उल्लेखनीय है कि बौद्ध और जैन धर्म प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य में ही विकसित हुए, जो आधुनिक बिहार में ही स्थित है।

इस क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग ने राज्य में 8 पर्यटन सर्किट बनाए हैं - बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट, शिव शक्ति सर्किट, सूफी सर्किट, सिख सर्किट, गांधी सर्किट और निसर्ग / वन्यजीव सर्किट।

बिहार विदेशी पर्यटकों के लिए महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार आने वाले कुल पर्यटकों में घरेलू पर्यटक जहां मात्र 1.96 प्रतिशत रहे, वहीं भारत आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में से 4.02 प्रतिशत विदेशी पर्यटक बिहार आए **(तालिका 13)**। वस्तुतः 2017 में विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में देश में बिहार का नौंवा स्थान रहा। यदि सभी राज्यों में पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों द्वारा किए जाने वाले खर्च को समान मान लिया जाए तो भी बिहार की विदेशी मुद्रा आय 1 अरब यूएस डॉलर से अधिक होगी। इसी अवधि के दौरान राज्य से वस्तु निर्यातों का मूल्य 1.35 अरब यूएस डॉलर से अधिक आंका गया। इस आंकड़े को देखते हुए भी पर्यटन से होने वाली यह विदेशी मुद्रा आय महत्त्वपूर्ण है। लेकिन इस क्षेत्र में वृद्धि स्थिर है। वर्ष 2011-2017 के दौरान बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की सीएजीआर 1.8 प्रतिशत रही, जो भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की 5.5 प्रतिशत की सीएजीआर की तुलना में काफी कम है।

बिहार सरकार पर्यटन को उद्योग विभाग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत लाकर पर्यटन क्षेत्र में अपना खर्च बढ़ा रही है। विदेशी मुद्रा आय की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए कुछ उच्च प्राथमिकता वाले खंडों को चिह्नित किया गया है **(चार्ट 6)**। इन निवेशों से इस क्षेत्र में धीमी वृद्धि दर को रफ्तार देने में मदद मिलेगी।

आगे की राह

बिहार की अर्थव्यवस्था पर कृषि क्षेत्र का प्रभाव बने रहने की उम्मीद है। अतः निर्यात रणनीति में इस क्षेत्र की महत्ता को ध्यान में रखने और इसे उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों में ले जाने के प्रयास करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को ऐसे उत्पादों के लिए विकसित करने की जरूरत है, जिन्हें निर्यात बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। साथ ही ऐसा करते समय अन्य राज्यों और देशों से मिलने वाले प्रतिस्पर्धी दबावों के प्रति अधिक लचीला रुख अपनाने की जरूरत है। सेवाओं संबंधी खंड में पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, जो विदेशी मुद्रा आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा। तथापि, इस क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें हाल के कुछ वर्षों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी आधारित सेवाओं जैसे खंडों को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

तालिका 13 : बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या (मिलियन में)

वर्ष	पर्यटकों की संख्या		
	घरेलू	विदेशी	कुल
2011	18.40	0.97	19.37
2012	21.45	1.10	22.54
2013	21.59	0.77	22.35
2014	22.54	0.83	23.37
2015	28.09	0.92	28.95
2016	28.52	1.01	29.53
2017	32.41	1.08	33.50
सीएजीआर (%)	9.90%	1.80%	9.60%
भारत में हिस्सा (2017)	1.96%	4.02%	2.00%

स्रोत : पर्यटन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

चार्ट 6 : पर्यटन में निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र

परिवहन	•पर्यटन स्थलों पर टैक्सी संचालक •पर्यटन स्थलों पर कैब एग्रीगेटर / रेडियो टैक्सी •पर्यटन सर्किटों पर लग्जरी कोच और कारें •पर्यटन सर्किटों के लिए एयर टैक्सी और हेलिकॉप्टर सेवाएं •विशेष पर्यटक ट्रेनें, नौकाएं, स्टीमर आदि।
आवास	•चिह्नित किए गए पर्यटन सर्किटों के 10 किलोमीटर के दायरे में होटल, मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, होम स्टे आदि •कारवां, कैंपिंग सुविधाएं / टेंट आवास / हेरिटेज होम आदि।
टूअर्स एंड ट्रैवल्स	•पर्यटन स्थलों पर ट्रैवल एजेंसियां, टूअर ऑपरेटर, प्रदर्शनी केंद्र, कार्यक्रम आयोजनकर्ता आदि।
एमआईसीई सुविधाएं	•पर्यटन स्थलों पर बैठक केंद्र (मीटिंग हब), कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी केंद्र, कार्यक्रम आयोजनकर्ता आदि।
मानव संसाधन विकास संस्थान	•होटल मैनेजमेंट संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, यात्रा एवं व्यापार संस्थान, मानव संसाधन प्रशिक्षण केंद्र, पर्यटक गाइड प्रशिक्षण संस्थान, पर्यटन क्षेत्र संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रबंधन संस्थान।
स्मृति चिह्न की दुकानें	•पर्यटन स्थलों पर हस्तशिल्प दुकानें, स्मृति चिह्न की दुकानें, एथनिक बुटीक, परंपरागत आभूषणों की दुकानें आदि।
हमराही (राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर सुविधाएं	•पर्यटन स्थलों पर सड़कों पर विभिन्न सुविधा केंद्र, रेस्त्रां, जलपान बार, ढाबे, सशुल्क शौचालय, उपयोगी सामान की दुकानें, पार्किंग और राज्य में बनने वाले हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों की दुकानें
स्वास्थ्य सुविधाएं	•पर्यटन स्थलों पर आयुर्वेद केंद्र, वेलनेस स्पा, उपचार केंद्र, योग विश्वविद्यालय आदि।
नदिया के पार	•क्रूज, तैरते रेस्त्रां, रिवर राफ्टिंग, पैरा सेलिंग जैसी जल क्रीड़ाएं, मछली पकड़ना, डोल्फिन दर्शन जैसी मनोविनोद सुविधाएं।
मनोरंजन	•पर्यटन स्थलों पर अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, क्राफ्ट ग्राम, रोपवे, विज्ञान केंद्र, संग्रहालय, तारामंडल आदि।
सिनेमा	•फिल्म सिटी

स्रोत : उद्योग मित्र

4. बिहार से निर्यात : वर्तमान परिदृश्य और संभावनाएं

बिहार अपने निर्यातों को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर है। आर्थिक वृद्धि, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में सुधार और सकारात्मक नीतिगत परिवेश राज्य से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिवेश रच रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में बिहार से वस्तु निर्यातों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2012-13 में राज्य से वस्तु निर्यात जहां 0.4 अरब यूएस डॉलर का रहा था, वहीं 2017-18 में यह बढ़कर 1.35 अरब यूएस डॉलर का हो गया। तथापि, इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है, क्योंकि भारत से वस्तु निर्यातों में बिहार से वस्तु निर्यातों का योगदान 1 प्रतिशत से भी कम है।

बिहार से निर्यातों में रुझान

बिहार से वस्तु निर्यातों में 2015-16 में आई गिरावट के बाद 2016-17 और 2017-18 के दौरान लगातार वृद्धि दर्ज की गई है **(तालिका 14)**। वस्तु निर्यातों में 2015-16 में आई गिरावट के दो प्रमुख कारण रहे। एक, नेपाल में प्रमुख सीमा क्रॉसिंग के 24 सितंबर, 2015 से दो महीने तक बंद रहना और दूसरा, अप्रैल 2015 में आए नेपाल में भूकंप से तबाह हुआ परिवहन नेटवर्क और बुनियादी ढांचा। वर्ष 2015-16 के दौरान कमोडिटी कीमतों में आई गिरावट के चलते भी बिहार से कुल निर्यात घट गया।

राज्य से निर्यातों के गैर-तेल खंड में 2016-17 से उल्लेखनीय उछाल आया है। यह उछाल कृषि और संबद्ध उद्योगों तथा टेक्सटाइल और गारमेंट का निर्यात बढ़ने के चलते आया। इस वृद्धि के बावजूद, बिहार के समग्र निर्यातों में गैर-तेल खंड का योगदान केवल एक तिहाई रहा। अतः इस खंड से निर्यातों को बढ़ाने के लिए एक रणनीति की जरूरत है।

प्रमुख निर्यातित उत्पाद

बरौनी रिफाइनरी निर्यातों के लिहाज से बिहार की एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक ईकाई है। राज्य से वस्तु निर्यातों में इस रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों का योगदान लगभग दो-तिहाई है। बिहार के अन्य प्रमुख निर्यात उत्पाद हैं - भैंस का मांस (वस्तु निर्यातों में 6.1 प्रतिशत हिस्सा), अन्य अनाज (5.1 प्रतिशत), चावल (बासमती से इतर) (5.0 प्रतिशत) और दवाओं के फॉर्मुलेशन व जैविक पदार्थ (3.7 प्रतिशत) **(तालिका 15)**।

कृषि आधारित कई उत्पादों में भारत के समग्र निर्यातों में बिहार का काफी अच्छा योगदान है। भारत से कच्चे जूट के निर्यातों में बिहार का योगदान लगभग 34.9 प्रतिशत है। बिहार के कृषि उत्पादन में अनाज उत्पादन अधिक होने के चलते बिहार से होने वाले निर्यातों में अनाजों का अच्छा योगदान रहता है। भारत के कुल गेहूं निर्यात का 18.4 प्रतिशत, चावल (बासमती से इतर) का 1.8 प्रतिशत और अन्य अनाजों का 27.7 प्रतिशत निर्यात बिहार से होता है। राज्य से सबसे अधिक निर्यातित पेट्रोलियम उत्पादों का भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 2.4 प्रतिशत का योगदान है **(तालिका 16)**।

तालिका 14 : बिहार से निर्यातों में रुझान

वर्ष	निर्यात मिलियन यूएस डॉलर			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)			कुल निर्यातों में हिस्सा	
	कुल	तेल	गैर-तेल	कुल	तेल	गैर-तेल	तेल	गैर-तेल
2013-14	949.9	656.7	293.1				69.1%	30.9%
2014-15	1034.7	743.1	291.5	8.9	13.2	-0.5	71.8%	28.2%
2015-16	546.3	335.7	210.6	-47.2	-54.8	-27.8	61.5%	38.5%
2016-17	823.5	552.9	270.6	50.7	64.7	28.5	67.1%	32.9%
2017-18	1353.2	898.5	454.7	64.3	62.5	68.0	66.4%	33.6%

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

तालिका 15 : बिहार से उत्पाद-वार निर्यात (2017-18)

निर्यात श्रेणी	निर्यात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)	हिस्सा %
पेट्रोलियम उत्पाद	898.5	66.4
भैंस का मांस	82.5	6.1
अन्य अनाज	68.8	5.1
चावल (बासमती से इतर)	67.2	5.0
दवाओं के फॉर्मुलेशन, जैविक पदार्थ	50.3	3.7
गेहूं	17.8	1.3
ताजा सब्जियां	12.3	0.9
समुद्री उत्पाद	12.1	0.9
ऑटो टायर और ट्यूब	11.8	0.9
चमड़े के सामान	8.8	0.7
कुल निर्यात	**1353.2**	**100.0**

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

तालिका 16 : भारत के निर्यातों में उच्चतम हिस्सेदारी वाले उत्पाद (2017-18)

निर्यात श्रेणी	निर्यात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)	भारत के निर्यातों में हिस्सा %
जूट, कच्चा	5.2	34.9%
अन्य अनाज	68.8	27.7%
गेहूं	17.8	18.4%
कोयला, कोक और कोयले की ईंटें (ब्रिकेट) आदि	8.6	5.1%
अन्य तिलहन	6.4	3.6%
अभ्रक	2.0	2.5%
उर्वरक क्रूड	0.3	2.4%
पेट्रोलियम उत्पाद	898.5	2.4%
अन्य जूट विनिर्माण	2.7	2.2%
भैंस का मांस	82.5	2.0%
जूट यार्न	0.4	2.0%
चावल (बासमती से इतर)	67.2	1.8%
ताजा सब्जियां	12.3	1.5%
दुग्ध उत्पाद	3.9	1.3%
जूट हेसियन	1.8	1.3%
प्राकृतिक रेशम यार्न, कपड़े, मेडअप	0.4	0.8%
मानव केश, उनके उत्पाद	2.0	0.8%
गुड़	0.1	0.7%
ऑटो टायर और ट्यूब	11.8	0.7%
सीमेंट, क्लिंकर और एस्बेस्टस सीमेंट	2.9	0.6%

निर्यात श्रेणी	निर्यात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)	भारत के निर्यातों में हिस्सा %
चमड़े के सामान	8.8	0.6%
अन्य कच्चे खनिज	0.9	0.6%
खली	6.4	0.6%
प्रसंस्कृत फल और जूस	3.4	0.5%
ताजा फल	3.8	0.5%
कुल निर्यात	**1353.2**	**0.4%**

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

प्रमुख आयातक

भौगोलिक सीमा से सटे होने के कारण नेपाल बिहार से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का प्रमुख आयातक है। वर्ष 2017-18 के दौरान, बिहार के लगभग 78 प्रतिशत वस्तु निर्यात नेपाल को रहे। इसके बाद वियतनाम (4 प्रतिशत हिस्सा), बांग्लादेश (3 प्रतिशत), थाईलैंड और यूएई (प्रत्येक 2 प्रतिशत) **(चार्ट 7)** का स्थान रहा।

विश्लेषण करने पर पता चलता है कि राज्य से गैर-पेट्रोलियम, तेल और ल्यूब्रिकेंट (गैर-पीओएल) निर्यातों का भी सबसे बड़ा आयातक नेपाल ही है और इसका हिस्सा 65 प्रतिशत है। इसके बाद वियतनाम का स्थान है, जिसका हिस्सा 13 प्रतिशत है। ताईवान, इराक, जापान और चीन बिहार से निर्यात होने वाले गैर-पीओएल उत्पादों के अन्य प्रमुख आयातक हैं, किन्तु समग्र निर्यातों में ये शीर्ष स्थान पर नहीं हैं **(चार्ट 7)**। अतः गैर-पीओएल निर्यातों में विशाखन की आवश्यकता है, जो इन प्रमुख बाजारों में निर्यातों के अवसर बनाते हुए पूरी की जा सकती है।

चार्ट 7 : बिहार के समग्र और गैर-पीओएल निर्यातों के शीर्ष आयातक (2017-18)

समग्र निर्यातों के आयातक (1.35 अरब यूएस डॉलर)

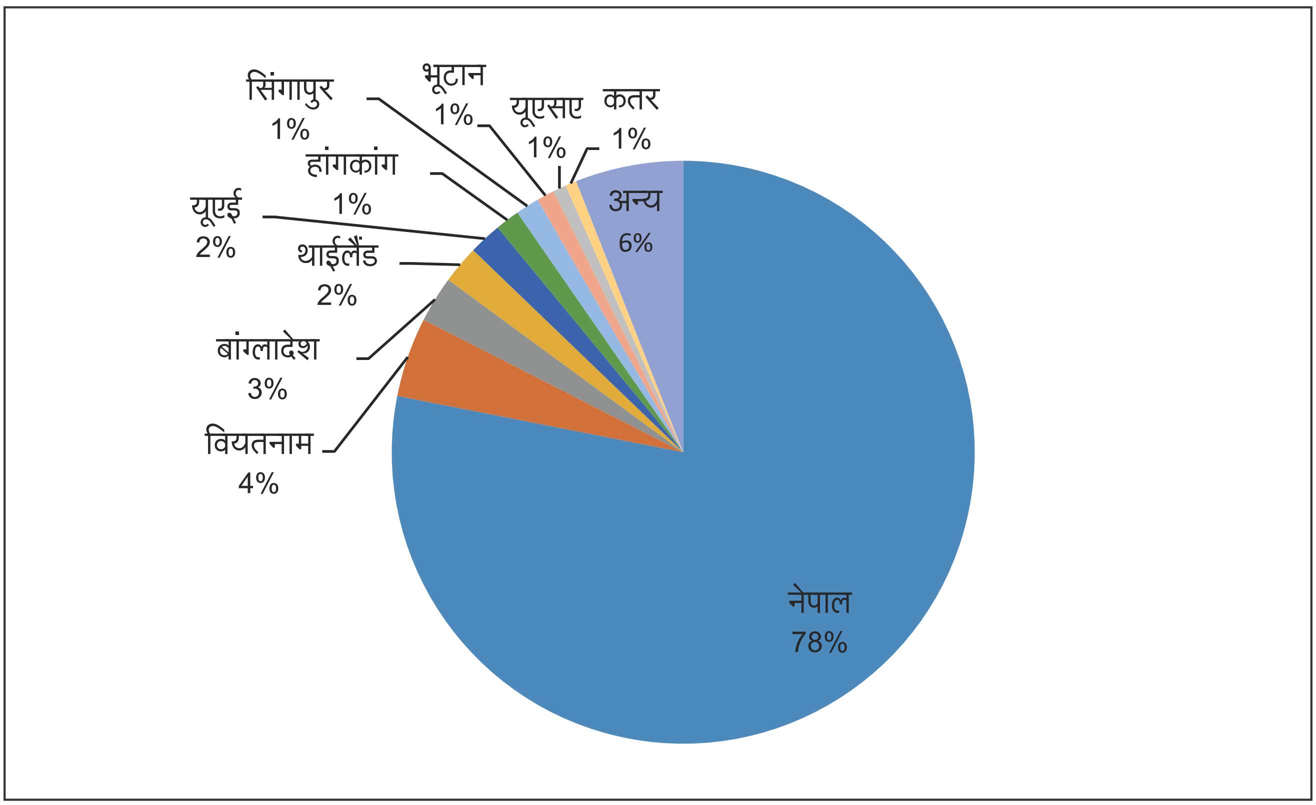

गैर-पीओएल निर्यातों के आयातक (0.45 बिलियन यूएस डॉलर)

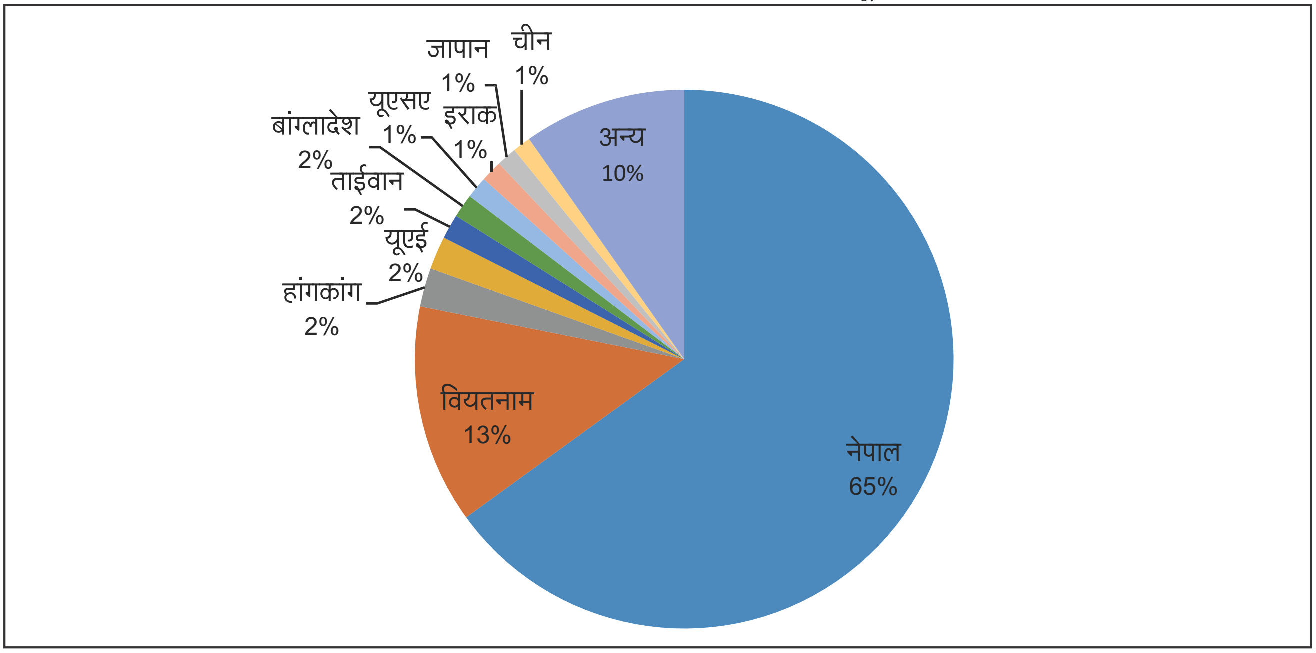

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

चार्ट 8 : बिहार से बंदरगाह-वार निर्यात (2017-18)

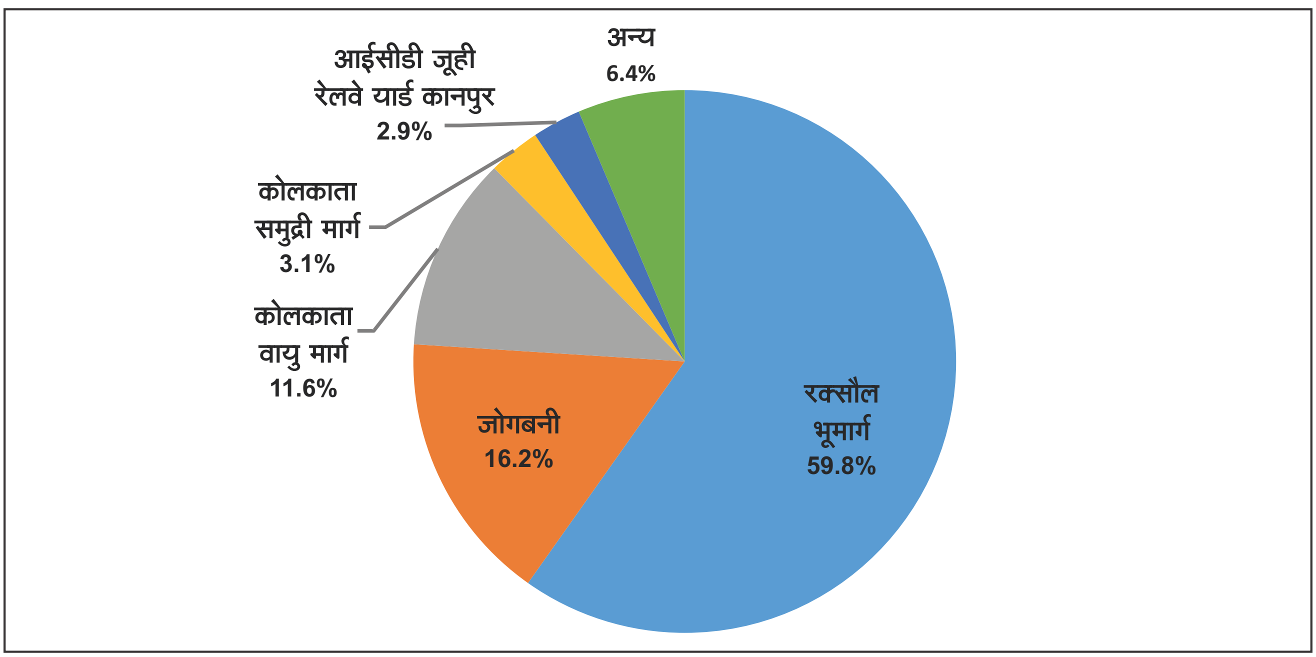

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

बिहार में फिलहाल एक इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) है, जो पटना में है। लेकिन यह सिर्फ घरेलू ढुलाई के ही काम आता है। अधिकांश निर्यात दो एकीकृत चेक पोस्टों रक्सौल और जोगबनी के जरिए होते हैं। नेपाल को निर्यातों के लिए इन्हीं दोनों एकीकृत चेक पोस्टों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अतिरिक्त, बिहार से निर्यातों के लिए अन्य प्रमुख केंद्र कोलकाता बंदरगाह और कोलकाता हवाई अड्डा हैं। कोलकाता के बंदरगाह और हवाईअड्डे से बिहार से होने वाले निर्यातों का लगभग 14.7 प्रतिशत निर्यात किया जाता है **(चार्ट 8)**। कोलकाता के जरिए बिहार से वस्तु निर्यातों के प्रमुख आयातक बांग्लादेश, थाईलैंड, यूएई, सिंगापुर, हांगकांग, कतर और भूटान जैसे मध्य पूर्व और पूर्वी देश हैं।

निर्यात लक्ष्य

प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में बिहार में वस्तु निर्यातों में करीब 900 मिलियन यूएस डॉलर की ऐसी निर्यात संभावनाएं हैं, जिन्हें अभी तक भुनाया नहीं गया है। यदि इन्हें भुना लिया जाए तो राज्य से वस्तु निर्यातों का आंकड़ा 2 अरब यूएस डॉलर को पार कर सकता है। हालांकि, मध्यम अवधि में, समुचित रणनीति के जरिए निर्यातों को और बढ़ाया जा सकता है।

उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2024-25 तक भारत 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था होगा। आशा है कि 2024-25 तक भारत से होने वाले निर्यातों का आंकड़ा भी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर को पार कर चुका होगा। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार से निर्यातों के लिए ऐसी महत्त्वाकांक्षी और सर्वतोमुखी निर्यात रणनीति अपनाने की जरूरत है, जो देश के वृद्धि लक्ष्यों के अनुरूप हो।

निर्यात नीति का उद्देश्य बिहार के जीएसडीपी में निर्यातों का हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 19 प्रतिशत के वर्तमान राष्ट्रीय औसत के समतुल्य करना होना चाहिए। इसके बाद, इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2024-25 के लिए 25 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप करने का प्रयास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य से निर्यातों में वस्तु निर्यातों का हिस्सा और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्तमान में वस्तु निर्यात जहां 1.35 अरब यूएस डॉलर के हैं, वहीं अकेले पर्यटन क्षेत्र से होने वाली विदेशी मुद्रा आय 1 अरब यूएस डॉलर के आसापास रहने का आकलन है, जो राज्य के निर्यातों में वस्तु और सेवा निर्यातों का हिस्सा लगभग आधा-आधा बनाए रखते हैं। रोजगारों पर विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रभाव को देखते हुए राज्य द्वारा अपने निर्यातों में वस्तु निर्यातों का हिस्सा बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

सकारात्मक परिदृश्य

एक्ज़िम बैंक का शोध बताता है कि भारत सरकार के आकलनों के अनुरूप 2024-25 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 325.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकता है। इस परिदृश्य में वृद्धि निर्यातों के साथ-साथ देश में घरेलू मांग पर आधारित होगी। चूंकि इस उच्च वृद्धि दर में निर्यातों की अहम भूमिका होगी, अतः हमारे आकलनों के अनुसार, भारत के जीडीपी में निर्यातों का हिस्सा वर्तमान के लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत तक होगा।

इस परिदृश्य में, बिहार को वर्तमान दर से अधिक जीएसडीपी वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य बनाना चाहिए, जो भारत के समग्र जीडीपी में राज्य का योगदान बढ़ाए। इससे बिहार का जीएसडीपी 2024-25 तक 10.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच सकता है। यदि यह मान लिया जाए कि व्यापार परिदृश्य में सुधार तथा और अनुकूल नीतिगत परिवेश के साथ बिहार के जीएसडीपी में निर्यातों का योगदान भारत के लिए आकलित 25 प्रतिशत के योगदान के समान हो जाता है, तो 2024-25 तक राज्य से निर्यातों का आंकड़ा 40.1 अरब यूएस डॉलर तक पहुंच सकता है। इसमें अकेले वस्तु निर्यातों का हिस्सा ही 26.7 अरब यूएस डॉलर होगा। यदि बिहार निर्यातों के इस स्तर को हासिल कर लेता है तो भारत के निर्यातों में बिहार के योगदान में उल्लेखनीय सुधार आएगा और यह लगभग 3.2 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

बेसलाइन परिदृश्य

एक्ज़िम बैंक के आकलन के अनुसार, बेसलाइन परिदृश्य में भारत के जीडीपी के 2024-25 तक 280.5 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचने और जीडीपी में निर्यातों का हिस्सा 19 प्रतिशत पर ही स्थिर रहने की उम्मीद है। इस बेसलाइन परिदृश्य में वृद्धि मुख्यतः घरेलू मांग पर निर्भर रहेगी। हाल ही में बिहार की जीएसडीपी वृद्धि भारत की जीडीपी वृद्धि से अधिक हो गई। बेसलाइन परिदृश्य में इस रुझान के जारी रहने के आसार हैं। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के जीडीपी में बिहार का योगदान पहले से उच्चतर, 3 प्रतिशत रहेगा और बिहार का जीएसडीपी 8.4 ट्रिलियन रुपये हो जाएगा। सुनियोजित निर्यात रणनीति के जरिए निर्यातों को बढ़ावा देने के साथ बिहार के जीएसडीपी में निर्यातों का हिस्सा भारत के जीडीपी में निर्यातों के 19 प्रतिशत के हिस्से के समतुल्य लाया जा सकता है। ऐसे बेसलाइन परिदृश्य में, बिहार से निर्यात 2024-25 तक बढ़कर 24.6 अरब यूएस डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद है। इसमें वस्तु निर्यात 16.4 अरब यूएस डॉलर के होंगे। बेसलाइन परिदृश्य में, भारत के निर्यातों में बिहार के निर्यातों का हिस्सा लगभग 3.0 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

गिरावट का परिदृश्य

यदि वैश्विक व्यापार डगमगाता है या संरक्षणवाद की स्थिति गहराती है तो जीडीपी में निर्यातों का हिस्सा गिरने की आशंका है। एक्ज़िम बैंक के आकलन के अनुसार, गिरावट के परिदृश्य में भारत का जीडीपी 235.2 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचने और जीडीपी में निर्यातों का हिस्सा वर्तमान से मामूली गिरावट के साथ 18 प्रतिशत होने की आशंका है।

ऐसे परिदृश्य में, 2024-25 तक भारत के जीडीपी में बिहार के जीएसडीपी का योगदान वर्तमान के लगभग 2.8 प्रतिशत के आसपास रहने और 6.6 ट्रिलियन रुपये के स्तर तक आने का अनुमान है। यद्यपि सुनियोजित निर्यात रणनीति के बलबूते निर्यातों के वर्तमान से बेहतर गति से बढ़ने और 2024-25 तक बिहार के जीएसडीपी में निर्यातों का हिस्सा बढ़कर 18 प्रतिशत होने की उम्मीद है। ऐसे परिदृश्य में, 2024-25 तक 12.2 अरब यूएस डॉलर के वस्तु निर्यातों के साथ निर्यातों के बढ़कर 18.2 अरब यूएस डॉलर का होने की उम्मीद है।

तालिका 17 : वैकल्पिक परिदृश्य में बिहार के लिए निर्यात लक्ष्य (2024-25)

	गिरावट का परिदृश्य	बेसलाइन परिदृश्य	सकारात्मक परिदृश्य
भारत का जीडीपी (रु. ट्रिलियन)	235.2	280.5	325.8
जीडीपी में निर्यातों का हिस्सा (भारत)	18.0%	19.0%	25.0%
भारत के जीएसडीपी में बिहार का हिस्सा	2.8%	3.0%	3.2%
जीएसडीपी बिहार (रु. ट्रिलियन)	6.6	8.4	10.4
बिहार से निर्यात (अरब यूएस डॉलर)	18.2	24.6	40.1
वस्तु निर्यात (अरब यूएस डॉलर)	12.2	16.4	26.7
सेवा निर्यात (अरब यूएस डॉलर)	6.1	8.2	13.4
भारत के निर्यातों में बिहार का हिस्सा	**2.8%**	**3.0%**	**3.2%**

स्रोत : सीएमआईई, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के डाटा तथा आर कोर टीम (2013) का इस्तेमाल करते हुए एक्ज़िम बैंक का आकलन। विश्लेषण के लिए, आर : ए लैंग्वेज एंड एन्वायर्नमेंट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग. आर. फाउंडेशन फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, वियना, ऑस्ट्रिया, यूआरएल : http://www.R-project.org

अतः एक्ज़िम बैंक के अनुमानों के आधार पर 2024-25 तक राज्य से निर्यातों का लक्ष्य 40 अरब यूएस डॉलर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें वस्तु निर्यातों के लिए 27 अरब यूएस डॉलर और सेवा निर्यातों के लिए 13 अरब यूएस डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

वस्तु निर्यातों के लिए प्रमुख उत्पाद

बिहार से निर्यातों में अच्छी वृद्धि की संभावना को देखते हुए प्रमुख उत्पादों और बाजारों को चिह्नित करना आवश्यक है, जिनसे राज्य की फर्मों को वृद्धि के अवसर मिलें और वे किफायती निर्यातों में सक्षम हो सकें तथा उनकी क्षमता भी बढ़े।

इस खंड में ऐसे उत्पादों का बारीकी से विश्लेषण किया गया है, जिनके निर्यातों से राज्य के निर्यातों में तुलनात्मक रूप से लाभ दर्ज किया गया है और उन उत्पादों की वैश्विक मांग को भी पूरा किया है। तुलनात्मक लाभ की गणना से ऐसे उत्पादों को चिह्नित करने में मदद मिलेगी, जिनका राज्य से अच्छा निर्यात है और ऐसे उत्पादों को चिह्नित करने में भी मदद मिलेगी, जिनके निर्यातों में पर्याप्त अवसरों के बावजूद सीमित कामयाबी मिली है।

निर्यात वृद्धि के लिए सबसे पहले ऐसे उत्पादों को अल्पावधि या मध्यम अवधि में लक्षित किया जा सकता है, जिनमें बिहार प्रतिस्पर्धी लाभ की स्थिति में है और जिनके लिए वैश्विक आयात मांग बढ़ रही है। राज्य सरकार मध्यम अवधि या दीर्घावधि में निर्यात वृद्धि हेतु उन उत्पादों के लिए कुछ प्रोत्साहन नीतियां लागू कर सकती है, जिन उत्पादों में राज्य की प्रतिस्पर्धी स्थिति नहीं है, लेकिन उन उत्पादों की वैश्विक मांग अच्छी है।

पद्धति

निर्यात स्पर्धात्मकता का विश्लेषण रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज (प्रकट तुलनात्मक लाभ - RCA) नामक अवधारणा से किया गया है। आरसीए सूचियों का इस्तेमाल ऐसी निर्यात श्रेणियों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है, जिनमें किसी अर्थव्यवस्था को तुलनात्मक लाभ होता है। इसके लिए उस देश के व्यापार परिदृश्य और विश्व व्यापार परिदृश्य की तुलना की जाती है। इस अवधारणा के अंतर्गत एक आधारभूत मान्यता यह है कि व्यापार प्रोफाइल से तुलनात्मक लागत और गैर-कीमत पहलुओं के संबंध में अंतर-देशीय अंतरों का पता चलता है। बालासा (1965) उपायों के अनुसार, i देश की j कमोडिटी के लिए सूचकांक है।

$$RCA_{ij} = \frac{(X_{ji}/X_i)}{(X_{wj}/X_w)}$$

जहां,

X_{ji} : i देश से j कमोडिटी का निर्यात है

X_i : i देश से कुल निर्यात है

X_{wj} : j कमोडिटी का कुल वैश्विक निर्यात है

X_w : विश्व से कुल निर्यात

1 ब्रेक-ईवन पॉइंट के साथ आरसीए सूचकांक 0 से अनंत तक हो सकता है। अर्थात 1 से कम आरसीए वैल्यू का मतलब है कि उस उत्पाद को कोई निर्यात तुलनात्मक लाभ हासिल नहीं है, वहीं वैल्यू 1 का मतलब है कि उत्पाद को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है।

नॉर्मलाइज्ड रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज (सामान्यीकृत प्रकट तुलनात्मक लाभ - एनआरसीए) सूचकांक के जरिए किसी उत्पाद के लिए तुलनात्मक लाभ को आरसीए की तुलना में और अधिक बारीकी और निरंतरता से देखा जा सकता है। एनआरसीए को निम्नलिखित अनुसार परिभाषित किया जा सकता है :

$$NRCA_{ij} = \frac{RCA_{ij} - 1}{RCA_{ij} + 1}$$

एनआरसीए में पाई गई बिहार की निर्यात स्पर्धात्मकता को उन उत्पादों की वैश्विक मांग से मैप किया गया अर्थात बिहार से उन उत्पादों की निर्यात स्पर्धात्मकता को वैश्विक मांग के सापेक्ष देखा गया। इस आधार पर उत्पादों की चार श्रेणियां चिह्नित की गईं :

- **प्रोडक्ट चैंपियंस -** प्रतिस्पर्धी निर्यात (एनआरसीए > 0); बढ़ती आयात मांग (उत्पाद आयात एएजीआर > 0): इन उत्पादों में अधिकतम संभावनाएं हैं, क्योंकि 2013-2017 के दौरान इन उत्पादों के लिए वैश्विक मांग में अच्छी वृद्धि हुई है और इन उत्पादों के लिए बिहार के निर्यात प्रतिस्पर्धी हैं।

- **अंडरअचीवर्स -** ऐसे उत्पाद, जो निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं हैं (एनआरसीए < 0); बढ़ती आयात मांग (उत्पाद आयात एएजीआर > 0): बिहार को इन उत्पादों में प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त नहीं है। किन्तु विचारणीय अवधि के दौरान इन उत्पादों की वैश्विक मांग में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अतः राज्य द्वारा इन उत्पादों में स्पर्धात्मकता बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

- **डिक्लाइनिंग सेक्टर्स -** निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं हैं (एनआरसीए < 0); आयात की मांग भी अच्छी नहीं है (उत्पाद आयात एएजीआर < 0): इन उत्पादों में बिहार को तुलनात्मक लाभ हासिल नहीं है और इन क्षेत्रों में विचारणीय अवधि के दौरान वैश्विक आयात मांग में भी नराकात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

- **अचीवर्स इन एडवर्सिटी -** प्रतिस्पर्धी निर्यात (एनआरसीए > 0); आयात की मांग भी अच्छी नहीं है (उत्पाद आयात एएजीआर < 0): इन उत्पादों में बिहार की स्पर्धात्मकता है, लेकिन दुनिया में आयात के लिए इन उत्पादों की आयात मांग नकारात्मक है।

अल्पावधि से मध्यम अवधि में, राज्य को प्रोडक्ट चैंपियंस खंड में अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वहां लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मध्यम से दीर्घावधि में, राज्य को अंडरअचीवर्स खंड में क्षमता विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है।

चिह्नित उत्पाद

बिहार से 2017-18 के दौरान एचएस-6 डिजिट लेवल में 1959 उत्पादों का निर्यात किया गया। ऊपर उल्लिखित पद्धति के अनुसार, बिहार से निर्यात किए गए 81 उत्पादों को 'प्रोडक्ट चैंपियंस' श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्य से इन उत्पादों का संयुक्त निर्यात 89.9 मिलियन यूएस डॉलर का रहा और राज्य के निर्यातों में इनका

6.6 प्रतिशत हिस्सा रहा **(चार्ट 9)**। मध्यम और दीर्घावधि में निर्यात वृद्धि के लिए इन उत्पादों में सर्वाधिक संभावनाएं हैं।

बिहार को 'अंडरअचीवर' श्रेणी के उत्पादों पर भी फोकस करने की जरूरत है, जिनका वैश्विक आयात मांग में 1/5वां हिस्सा है, किन्तु 2017-18 के दौरान राज्य से निर्यातों में केवल 0.9 प्रतिशत हिस्सा रहा **(चार्ट 9)**। राज्य में निवेशों को आकर्षित करने के लिए इन उत्पाद श्रेणियों में समुचित प्रोत्साहन योजना के जरिए क्षमता सृजन की जरूरत है। गिरती वैश्विक मांग और कमोडिटी कीमतों में आते उतार-चढ़ाव के इस दौर में इन उत्पादों पर फोकस करने से बिहार से निर्यातों में जरूरी लचीलापन आ सकेगा, जिसकी काफी जरूरत है।

अधिकांश उत्पादों को 'डिक्लाइनिंग सेक्टर' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक आयातों में एक चौथाई मांग इन उत्पादों की है, लेकिन वैश्विक मंदी और कमोडिटी कीमतों का इस क्षेत्रों पर विपरीत असर पड़ा है और 2013-2017 के दौरान इन उत्पादों की आयात मांग नकारात्मक रही।

बिहार से कुल निर्यात मूल्य देखा जाए तो अधिकांश 'अचीवर्स इन एडवर्सिटी' श्रेणी में रहा। ये वे उत्पाद हैं, जिनमें राज्य को प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल है, लेकिन हाल के कुछ समय के दौरान इन उत्पादों की वैश्विक मांग में गिरावट आई है और इससे बिहार के निर्यातों पर विपरीत असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। राज्य से निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पादों का अच्छा योगदान है, किन्तु उन्हें इसी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। राज्य को इस खंड के अलावा अपने निर्यातों में विशाखन की जरूरत है और निर्यातों में तेजी लाने के लिए प्रोडक्ट चैंपियंस और 'अंडरअचीवर' खंड में अधिक विशाखन की जरूरत है।

चार्ट 9 : बिहार से निर्यातों के लिए उत्पादों को चिह्नित करना

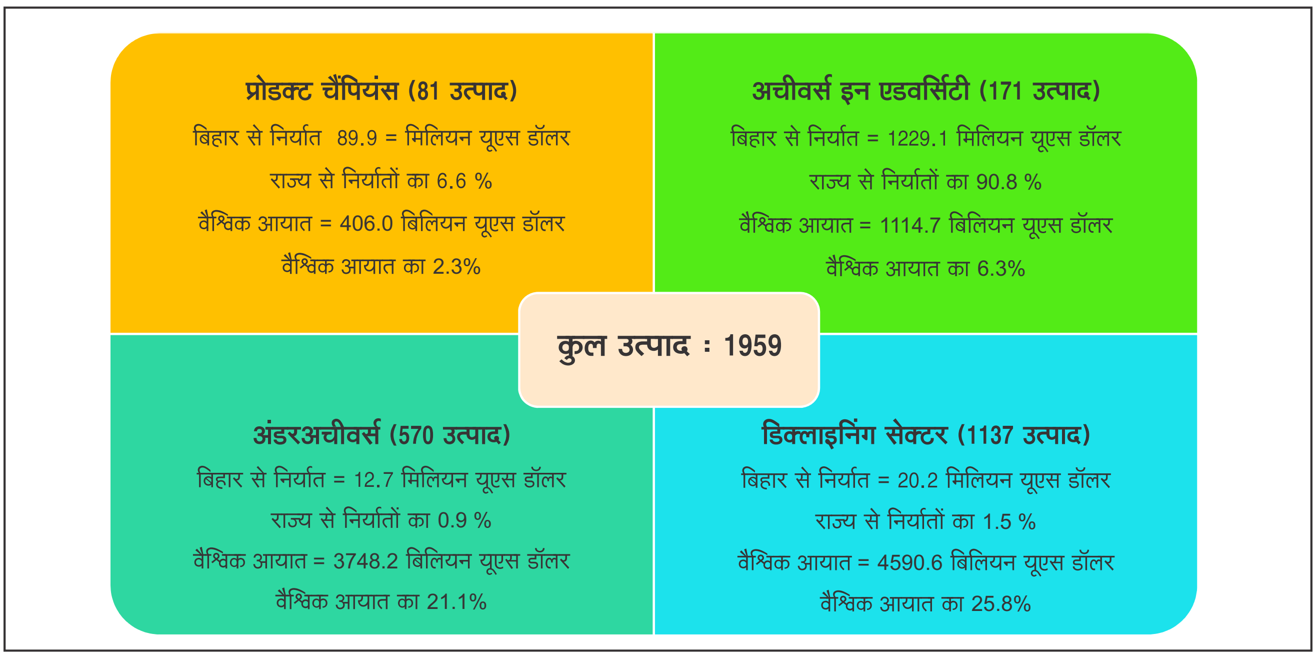

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, आईटीसी ट्रेड मैप, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

प्रमुख क्षेत्र

फार्मास्यूटिकल उत्पाद, पशु और पशु उत्पाद, टेक्सटाइल्स व गारमेंट, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद तथा वनस्पति उत्पाद बिहार के 'प्रोडक्ट चैंपियंस' खंड में शामिल शीर्ष क्षेत्रों में से प्रमुख हैं। 'प्रोडक्ट चैंपियंस' खंड में शामिल 81 में से लगभग 24 उत्पाद टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र से हैं। तथापि, सर्वाधिक निर्यात मूल्य फार्मास्यूटिकल उत्पादों का है, जिसके बाद पशु और पशु उत्पादों का स्थान है **(तालिका 18)**।

'अंडर अचीवर्स' खंड में भी सबसे अधिक उत्पाद टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र से ही हैं। तथापि, राज्य से निर्यातों के मूल्य को देखा जाए तो रसायन और संबद्ध क्षेत्र, तैयार खाद्य पदार्थ, फार्मास्यूटिकल उत्पाद और मशीनरी प्रमुख क्षेत्र हैं **(तालिका 19)**।

इस खंड में चिह्नित 'प्रोडक्ट चैंपियंस' के लिए प्रमुख आयात बाजारों और इन बाजारों को आपूर्ति करने वाले प्रमुख निर्यातकों को अनुलग्नक में सूचीबद्ध किया गया है। बिहार के निर्यातक इन बाजारों और इन बाजारों के संबंध में आगामी खंडों में दी गई योजनाओं को लक्ष्य कर सकते हैं।

चिह्नित की गई कुछ उत्पाद श्रेणियों में नेपाल प्रमुख आयातक देश है, जो भौगोलिक सीमा से सटे होने के चलते बिहार के निर्यातकों को बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। नेपाल द्वारा आयात किए जा रहे कई उत्पादों में बाजार में अपनी पैठ बढ़ाकर निर्यात बढ़ाने के अच्छे अवसर हैं। उदाहरण के लिए, रॉ शर्करा की श्रेणी में, ऐडेड फ्लेवर या बिना रंगों की मिलावट वाली ठोस शर्करा (एचएस कोड : 170113) का नेपाल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक रहा, जिसका वैश्विक आयातों में 4.5 प्रतिशत हिस्सा रहा। वस्तुतः इस श्रेणी में भारत के लिए नेपाल सबसे बड़ा आयातक रहा। तथापि, इस श्रेणी में भारत के निर्यातों में बिहार का हिस्सा केवल 1.2 प्रतिशत रहा, जो 2017 में नेपाल द्वारा 30.5 मिलियन यूएस डॉलर की आयात मांग की तुलना में 2017-18 में 0.2 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। अगरबत्ती और समरूपी अन्य पदार्थों (एचएस कोड : 330741), जूट और टेक्सटाइल आधारित अन्य फाइबर, रॉ या गला हुआ (एचएस : 530310), कृत्रिम स्टैपल फाइबर के सिलाई धागे, खुदरा बिक्री के लिए या अन्यथा रखे गए (एचएस : 550820), वजन में 85% से कम कृत्रिम स्टैपल फाइबर वाले बुने हुए फैब्रिक (एचएस : 551449), बुने हुए और क्रोशिया किए हुए 30 सेमी से कम चौड़ाई वाले फैब्रिक (एचएस : 600390) और टेबल, रसोई के अन्य घरेलू सामान, बर्तन साफ करने का स्क्रबर (एचएस : 741810)।

तालिका 18 : बिहार के लिए क्षेत्रवार 'प्रोडक्ट चैंपियंस'

उत्पाद श्रेणी	**एचएस 6 डिजिटल स्तर के उत्पादों की संख्या**	**2017-18 में निर्यात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)**
फार्मास्यूटिकल उत्पाद	3	43.1
पशु और पशु उत्पाद	11	20.5
टेक्सटाइल और गारमेंट	24	8.1
चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	3	6.3
वनस्पति उत्पाद	18	4.6
रसायन और संबद्ध उत्पाद	4	3.1
खनिज उत्पाद	2	1.0
तैयार खाद्य पदार्थ	4	0.8
मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण; इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स	3	0.8
विविध उत्पाद	4	0.7
धातु और धातु के उत्पाद	4	0.6
पशु या वनस्पति वसा एवं तेल तथा उनके उत्पाद	1	0.1
कुल प्रोडक्ट चैंपियंस	**81**	**89.9**

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, आईटीसी ट्रेड मैप, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

तालिका 19 : बिहार के लिए क्षेत्रवार 'अंडरअचीवर सेक्टर'

उत्पाद श्रेणी	एचएस 6 डिजिटल स्तर के उत्पादों की संख्या	2017-18 में निर्यात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)
रसायन और संबद्ध उत्पाद	58	2.5
तैयार खाद्य पदार्थ	23	1.4
फार्मास्यूटिकल उत्पाद	6	1.4
मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण; इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स	95	1.1
टेक्सटाइल और गारमेंट	101	1.1
विविध	62	0.9
धातु और धातु उत्पाद	58	0.8
वाहन, विमान, पोत और संबद्ध परिवहन उपकरण	14	0.8
वनस्पति उत्पाद	38	0.7
ऑप्टिकल, मापक, चिकित्सा और समान उपकरण और पुर्जे	34	0.5
प्लास्टिक और प्लास्टिक की चीजें	16	0.4
खनिज उत्पाद	12	0.3
पशु और पशु उत्पाद	4	0.3
चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	5	0.1
निर्माण सामग्री	12	0.1
रबर और रबर की चीजें	9	0.1
कागज और कागज की चीजें	8	0.1
कांच और कांच की बनी वस्तुएं	11	0.0
पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके उत्पाद	4	0.0
कुल अंडरअचीवर	**570**	**12.7**

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, आईटीसी ट्रेड मैप, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

नेपाल के अतिरिक्त, मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया के देश भी बिहार के लिए महत्त्वपूर्ण आयातक हैं। बिहार के निर्यातकों के लिए इन देशों का महत्त्व विशेष रूप से तब तक बना रहेगा, जब तक कि राज्य में इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन विकसित नहीं हो जाते हैं और बाजार विशाखन के लिए प्रोत्साहनपूर्ण फ्रेमवर्क नहीं बन जाता है। अनुलग्नक में इन बाजारों का अल्पावधि और दीर्घावधि में निर्यातकों के लिए फोकस बाजार के रूप में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

5. निर्यात वृद्धि के लिए रणनीतियां

पिछले अध्यायों में बिहार की आर्थिक वृद्धि को नई ऊर्जा और गति प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के जरिए राज्य के औद्योगिक और निर्यात आधारों में विशाखन की जरूरत को रेखांकित किया गया है। साथ ही वृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संभावित ऐसे क्षेत्रों और बाजारों को भी चिह्नित किया गया है, जिन्हें लक्षित किया जा सकता है। निर्यातों के विशाखन के लिए राज्य को अपनी निर्यात स्पर्धात्मकता में सुधार लाने की जरूरत होगी तथा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्यात रणनीति एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होगी।

यद्यपि व्यापार और वाणिज्य केंद्र सरकार के विषय हैं और संसद को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। किन्तु इस प्रकार की गतिविधियों के परिचालन के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्र राज्य सरकार के विशेषाधिकार में होते हैं। इसलिए बिहार सरकार के लिए एक सुदृढ़ निर्यात रणनीति बनाने और उसे अपने आर्थिक एजेंडा में शामिल करने की जरूरत है। समग्र रूप से देखें तो बिहार से निर्यातों के संवर्धन के लिए योजना में विभिन्न स्तरों पर रणनीतियां बनाना शामिल होगा। मोटे तौर पर ये रणनीतियां छह आवश्यक आयामों पर बनाई जा सकती हैं - प्रमुख उत्पाद और बाजार; बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उसका लाभ उठाना; क्षमता विकास; वित्तीय प्रोत्साहन; निर्यात संवर्धन अभियान; और संस्थागत समन्वय **(चार्ट 10)**।

उत्पादों और बाजारों पर ध्यान

बिहार से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की संख्या बढ़ाने से राज्य से निर्यातों में जरूरी लचीलापन लाया जा सकता है। निर्यातों को बढ़ाने का एक संभावित उपाय वैल्यू एडिशन के आधार पर विशाखन करना है। निर्यातों के विशाखन के दो तरीके हैं। एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजेंटल विशाखन किसी क्षेत्र विशेष में ही किया जाता है। इस तरह के विशाखन में उसी क्षेत्र विशेष में नए-नए उत्पाद जोड़े जाते रहते हैं। वर्टिकल विशाखन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विशाखन शामिल होता है। वर्टिकल विशाखन में प्रसंस्करण, मार्केटिंग या अन्य सेवाओं के जरिए मूल्य वर्धित गतिविधियां बढ़ाते हुए मौजूदा उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ाना शामिल है। तालिका 20 में संभावित उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों की सूची दी गई है, जिससे बिहार से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विशाखन में मदद मिल सकती है।

कृषि और संबद्ध उत्पाद बिहार से निर्यात किए जाने वाले गैर-तेल उत्पादों में प्रमुख उत्पाद हैं। आने वाले समय में राज्य कृषि उत्पादों के अधिक प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वर्तमान में अनाज राज्य से निर्यात होने वाले महत्त्वपूर्ण उत्पादों में से एक है। किन्तु अनाज से बनने वाले अन्य उत्पादों का निर्यात कम है। डेयरी और मांस उत्पादों के उच्च स्तर के प्रसंस्करण से भी निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, ऑर्गैनिक उत्पादन पर फोकस बढ़ाया जा सकता है। वैश्विक ऑर्गैनिक बाजार 2016 में लगभग 89.7 अरब यूएस डॉलर का आंका गया था और राज्य के निर्यातकों के लिए इसमें अच्छे अवसर हैं। ऑर्गैनिक उत्पादों में निहित संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में ऑर्गैनिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। राज्य में ऑर्गैनिक कॉरिडोर स्थापित करने की योजना है और राज्य में ऑर्गैनिक खेती करने वाले किसानों को कृषि सामग्री में सब्सिडी दी जा रही है। निर्यातों के

चार्ट 10 : निर्यात रणनीति के प्रमुख तत्व

लिहाज से देखा जाए तो आयातक बाजारों की आवश्यकतानुसार ऑर्गैनिक उत्पादन के प्रमाणीकरण, पैकेजिंग और लेबलिंग की जरूरत है।

टेक्सटाइल खंड में बिहार सूती, जूट और रेशम (सिल्क) के कपड़ों का प्रमुख निर्यातक है। वस्तुतः जूट और जूट के उत्पाद बिहार से निर्यात होने वाले महत्त्वपूर्ण निर्यात उत्पादों में शामिल हैं। हालांकि जूट फाइबर कपड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल्स में उनका प्रसंस्करण किया जा सकता है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमत भी मिलेगी। जूट फाइबर का इस्तेमाल एग्रोटेक, बिल्डटेक, क्लॉथटेक, जियोटेक, मोबिलटेक, पैकटेक, प्रोटेक और ओकोटेक में किया जा सकता है।

राज्य के लिए रेशम (सिल्क) भी एक महत्त्वपूर्ण निर्यात उत्पाद है। रेशम के उत्पादन में हिंसा के पहलू के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते अहिंसा सिल्क **(बॉक्स 2)** लोकप्रिय हो रहा है। नई उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत रेशम कृमि की हत्या किए बिना रेशम उत्पादन किया जाता है और अतंरराष्ट्रीय बाजार में अहिंसा सिल्क के उत्पादों को अधिक स्वीकृति मिल रही है। इन नई प्रक्रियाओं से बनने वाले उत्पादों को सही तरीके से बाजार में उतारा जाए तो इनके लिए अच्छी कीमत भी मिल जाएगी।

रसायन और पेट्रोरसायनों के निर्यातों में भी बिहार की अच्छी मौजूदगी है। बिहार से कार्बनिक, अकार्बनिक और विशिष्ट रसायनों जैसे कई तरह के रसायनों का निर्यात किया जाता है। किन्तु, इन निर्यातों का मूल्य अभी कम है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। रंजकों (डाई) और रंगद्रव्यों (पिगमेंट), निर्माण रसायन, सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और जल शोधन में इस्तेमाल होने वाले रसायनों जैसे खंडों पर फोकस बढ़ाया जा सकता है।

तालिका 20 : बिहार के निर्यातों में विशाखन के अवसर

क्षेत्र	मौजूदा उत्पाद	संभावित उच्च-मूल्य वर्धित निर्यात	टिप्पणी
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	अनाज- मक्का, चावल, गेहूं	स्नैक्स, पकाने / खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों, बेकरी उत्पादों जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों के लिए अनाज का प्रसंस्करण	अनाज से तैयार उत्पादों के खंड में बिहार की सीमित उपस्थिति है।
	डेयरी - दूध, क्रीम, मक्खन, प्रसंस्कृत पनीर	मट्ठा उत्पाद (एचएस 0404)	डेयरी उत्पाद बिहार से निर्यातित महत्त्वपूर्ण निर्यात उत्पाद हैं, किन्तु वर्तमान में मट्ठा उत्पादों का निर्यात नहीं किया जाता है। 2017[1] में वैश्विक मट्ठा आयात 4.6 अरब यूएस डॉलर का रहा। चीन और इंडोनेशिया के बाजारों में निर्यात के प्रयास किए जा सकते हैं।
	समुद्री उत्पाद- जीवित मछलियां; फ्रोजन श्रिंप, प्रॉन, देशी मछलियां	समुद्री उत्पाद, मछली का तेल (एचएस 1504), डिब्बाबंद समुद्री उत्पाद	मछली के तेल का उपयोग दवा के रूप में, खाद्य उत्पादों और औद्योगिक कार्यों में भी किया जाता है। इसकी वैश्विक मांग 2017 में 1.8 अरब यूएस डॉलर[1] की रही।
	बागबानी - फल, सब्जियां, फूल	ऑर्गैनिक उत्पादन और निर्यातों और फूलों की अन्य किस्मों पर फोकस	वैश्विक ऑर्गैनिक खाद्य बाजार 2016 में 89.7 अरब यूएस डॉलर का रहा था।[2] बिहार से प्रमाणित ऑर्गैनिक उत्पादन और निर्यातों के लिए 'जैविक उत्पादन राष्ट्रीय कार्यक्रम' के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। फूल उत्पादन में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार आगे है। फूल उत्पादन और निर्यात बढ़ाया जा सकता है।

टेक्सटाइल और गारमेंट	जूट निर्यात में अधिकांश हिस्सा कच्चे जूट का है	टेक्निकल टेक्सटाइल खंड की ओर ध्यानः एग्रोटेक-कैनवस कपड़ा और तिरपाल बिल्डटेक - जूट लैमिनेट्स क्लॉथटेक - जूट और जूट मिश्रित फैब्रिक जियोटेक - मृदा संरक्षक फर्नीचर, इंटीरियर टेक्सटाइल्स और फर्श कवरिंग - जूट मिश्रणों से बने पर्दे, जूट की दीवार कवरिंग, डिवाइडर आदि। मोबिलटेक - जूट / जूट मिश्रण से बने बिना बुनाई के ध्वनि और ताप रोधक। पैकटेक - सॉफ्ट लगेज फैब्रिक, जूट की लैमिनेटेड टाट कपड़ा और बोरियां प्रोटेक - जूट के धागे से बने आग और फफूंदी रोधक कपड़े और अन्य पारंपरिक / उच्च गुणवत्ता वाले खोल ओकोटेक जूट / जूट के मिश्रण से बने कैनवस कपड़े और तिरपाल	टेक्निकल टेक्सटाइल बाजार 2016 में 157.68 अरब यूएस डॉलर का आंका गया था और 2022 तक इसके 220.37 अरब यूएस डॉलर का होने का अनुमान है।
	प्राकृतिक रेशम - कच्चा, कपड़े, और इनसे बने उत्पाद	'अहिंसा सिल्क' उत्पाद, जो रेशम कृमियों को मारे बिना या उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना बनने वाले सिल्क के उत्पाद हैं तथा शुद्ध रेशम कालीन	अहिंसक तरीके से निर्मित, पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ गारमेंट्स की बढ़ती मांग का पारंपरिक रेशम उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके चलते अहिंसा सिल्क के लिए अच्छे दाम मिल सकते हैं।
रसायन और संबद्ध क्षेत्र	विभिन्न प्रकार के कृषि रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन	सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, जल शोधन रसायन, निर्माण रसायन, रंजक और रंगद्रव्य (पिगमेंट)	बिहार इनमें से कुछ उत्पादों का पहले से निर्यात करता रहा है, लेकिन निर्यातित उत्पादों की मात्रा कम है।
फार्मास्यूटिकल	विभिन्न प्रकार के ड्रग फॉर्म्युलेशन और कुछ थोक दवाइयां	प्रतिरक्षी उत्पाद; पशु चिकित्सा के लिए टीके; अपारदर्शी औषध मिश्रण; इफेड्रिन; स्यूडोफेड्रिन; एल्कलॉइड या डेरिवेटिव; इंसुलिन युक्त दवाएं आदि।	फार्मास्यूटिकल उत्पाद प्रोडक्ट चैंपियंस श्रेणी में शामिल हैं। इनके मौजूदा निर्यात खंड में क्षमता बढ़ाने और अन्य अप्रयुक्त श्रेणियों में विशाखन की जरूरत है।
हस्तशिल्प	मधुबनी पेंटिंग, घास शिल्प, लाख की चूड़ियां, पत्थर पर नक्काशी, लकड़ी के खिलौने, टेराकोटा वस्तुएं और गमले	आधुनिक सामान और उपहार, फर्नीचर, दीवार सज्जा, लैम्प आदि।	डिजाइन और मार्केटिंग तकनीकों में सुधार महत्त्वपूर्ण होगा। उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मांग रुझानों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
पर्यटन और आतिथ्य	धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन	महोत्सव पर्यटन (छठ पूजा के आसपास), खान-पान पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन	पर्यटकों के अनुभवों को और मनोरम बनाने के लिए बिहार अपने अनूठे भोजन और उत्सव संस्कृति का लाभ उठा सकता है।

नोट : [1]आईटीसी ट्रेडमैप, [2]एफआईबीएल और आईएफओएएम

स्रोत : एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

बॉक्स 2 : अहिंसा सिल्क

यह सन 2000 के आसपास की बात है, जब अहिंसा सिल्क का वाणिज्यीकरण किया गया। यह रेशम उत्पादन का नया तरीका है, जिससे उत्पादित रेशम को शांति सिल्क भी कहा जाता है। अहिंसा सिल्क में रेशम उत्पादन की हिंसक प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। इस तरह बने रेशम की न तो गुणवत्ता पर कोई असर पड़ता है और न ही उत्पादन परिचालन प्रभावित होता है। रेशम उत्पादन के परंपरागत तरीके में कृमिकोष से धागा बनाने से पहले रेशम कृमियों को मारना पड़ता है। किन्तु अहिंसा सिल्क की उत्पादन प्रक्रिया में वयस्क कीट जीवित निकाल लिए जाते हैं और रेशम के धागों को उसके बाद कृमिकोष से निकालकर काता या बुना जाता है। जंगल में मिलने वाले कृमिकोषों और कृत्रिम कृमिकोषों, दोनों में इसी प्रक्रिया से रेशम बनाया जाता है।

एरी रेशम कृमि (फिलोसेमिया रेसिनि) अहिंसा सिल्क के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त रेशम कृमि होते हैं। परंपरागत रेशम उत्पादन में रेशम कृमि का भोजन जहां शहतूत की पत्तियां होती हैं, वहीं अहिंसा सिल्क में रेशमकृमि अरंडी के पेड़ से अपना भोजन पाते हैं। अहिंसा सिल्क के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य कृमियों में तसर कृमि (उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों) तथा मूगा रेशम कृमि भी शामिल हैं। भले ही अहिंसा सिल्क की चमक रेगुलर सिल्क से थोड़ी कम हो, किन्तु यह पहनने में उससे ज्यादा आरामदायक होता है। इसमें सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं और यह सीधा रहता है।

पर्यावरण के प्रति सजग और अहिंसा को आगे बढ़ाने वाले ग्राहक वर्ग के बीच दुनिया भर में अहिंसा सिल्क की मांग बढ़ रही है। बुनकर और डिजाइनर इस मांग को पहचान रहे हैं। परिणामतः अहिंसा सिल्क के विभिन्न उत्पाद बाजार में आ गए हैं। इनमें शॉल, स्टोल, स्कार्फ, टाई, फर्निशिंग फैब्रिक, बुनाई किए हुए, अपैरल फैब्रिक, दरियां और अन्य विविध उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं।

बिहार से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए नए बाजारों तक पहुंचना भी जरूरी है। बिहार से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के प्रमुख आयातकों के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश उत्पाद श्रेणियां ऐसी हैं, जहां बिहार के निर्यातक उन आयातक देशों को निर्यात नहीं कर रहे, जो उन उत्पादों के प्रमुख आयातक हैं **(तालिका 21)**। निर्यातकों को उन प्रमुख आयातक देशों के बाजारों को निर्यात करने के लिए विनियमों को समझने और उन बाजारों में प्रवेश करने के लिए एक समुचित कार्य योजना बनाने की जरूरत है।

बिहार को नए क्षेत्रों, प्राथमिक रूप से उच्च-प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों पर भी फोकस करने की जरूरत है। इनमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इंजीनियरिंग सामान की श्रेणियां शामिल हैं। वैश्विक आयात बाजार में खनिज ईंधन के बाद इन उत्पादों का सबसे बड़ा हिस्सा है। साथ ही, सस्ते दामों में आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से इन उत्पादों में प्रतिस्पर्धा भी कम है। तथापि, इन क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात, निर्यात-उन्मुख प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर निर्भर करेगा। बिहार सरकार को भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अनुरूप 'मेक इन बिहार' जैसा कार्यक्रम बनाने, अपनाने और उसे क्रियान्वित करने की जरूरत है।

बायोडीजल भी ऐसा ही एक नया क्षेत्र है, जिसमें निर्यातकों के लिए संभावनाएं हैं। तेल की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को देखते हुए बायोडीजल वैश्विक स्तर पर उभरता हुआ क्षेत्र है। बिहार के निर्यातक इस अवसर को भुना सकते हैं, क्योंकि बिहार में सोयाबीन, सूरजमुखी, ताड़, सफेद सरसों, कपास, मूंगफली, जट्रोफा, महुआ, शहतूत, जोजोबा, नीम आदि अच्छे होते हैं, जिनका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने के लिए किया जा सकता है। इनमें से कुछ संयंत्रों के लिए राज्य की ऊसर भूमि का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां कंपनियां बायोडीजल के संयंत्र लगा सकती हैं।

बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और उसका सदुपयोग करना

यदि बिहार की तुलना हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे बंदरगाह विहीन राज्यों से की जाए तो इन सभी राज्यों में बिहार की अपेक्षा अधिक गहन लॉजिस्टिक नेटवर्क है। इनमें से कुछ राज्य भौगोलिक रूप से बिहार से छोटे हैं, लेकिन उनमें परिचालनरत इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की संख्या अधिक है। इनमें से कुछ राज्यों में निर्यातों के लिए सुदृढ़ बुनियादी ढांचे की बदौलत निर्यात अच्छे रहे हैं। इन राज्यों से स्पर्धा और निर्यातों में बेहतर वृद्धि

के लिए बिहार को अपने मौजूदा निर्यात बुनियादी ढांचे के उन्नयन की जरूरत है।

इनलैंड कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशन

राज्य में निर्यातों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में से एक है इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी)। बिहार में वर्तमान में केवल एक कंटेनर डिपो है, जो पटना में है। इस पर केवल घरेलू ढुलाई होती है। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार आईसीडी को सामूहिक उपयोक्ता सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण का दर्जा प्राप्त होता है और यहां अचल सुविधाओं के साथ-साथ सीमा शुल्क तथा घरेलू इस्तेमाल, गोदामों में भंडारण, अस्थायी भंडारण, पुनः निर्यात, अग्रेषण और प्रत्यक्ष निर्यात के लिए सीमा शुल्क के अलावा अन्य सक्षम प्राधिकारियों के नियंत्रण वाले आयात / निर्यात माल से लदे और खाली कंटेनरों की हैंडलिंग और अस्थायी भंडारण के लिए सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। ऐसे स्टेशन से कार्गो का पोतांतरण भी किया जा सकता है।

यदि आईसीडी से बेहतर कनेक्टिविटी हो तो ये बिहार जैसे बंदरगाह विहीन राज्य के आर्थिक विकास को सुगम बनाने में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आने वाले समय में उत्पादन क्लस्टरों से समन्वय के जरिए आईसीडी का विशेष आर्थिक क्षेत्र में विस्तार; समुद्री बंदरगाह टर्मिनलों से वितरण संबंधी गतिविधियों का संचालन और परिवहन के बहुविधि मॉडल का इस्तेमाल भी आर्थिक विकास में गति लाने में मददगार हो सकते हैं।

तालिका 21 : बिहार से निर्यातित प्रमुख उत्पादों के लिए निर्यात स्थल और शीर्ष आयात स्रोत

एचएस	एचएस विवरण	बिहार के लिए शीर्ष निर्यात स्थल	शीर्ष आयातक
27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ	नेपाल (84.9), बांग्लादेश (3.1), थाईलैंड (3.1), यूएई (1.7), सिंगापुर (1.7)	चीन (12.3), यूएसए (10.0), जापान (6.9) भारत (6.0), दक्षिण कोरिया (5.4)
10	अनाज	नेपाल (94.6), भूटान (1.3), श्रीलंका (1.2) बांग्लादेश (1.2), बेनिन (0.6)	चीन (5.8), जापान (4.9), मेक्सिको (4.0), मिस्र (4.0), इंडोनेशिया (3.6)
2	मांस और खाद्य मांस ऑफल	वियतनाम (64.3), हांगकांग (11.4), ताइवान (7.9), इराक (7.1), यूएई (2.9)	जापान (8.6), चीन (8.1), यूएसए (7.0), जर्मनी (6.5), हांगकांग (5.6)
30	फार्मास्यूटिकल उत्पाद	नेपाल (99.1), हांगकांग (0.3), मॉल्डोवा (0.2), म्यांमार (0.1), यूक्रेन (0.1)	यूएसए (17.2), जर्मनी (9.6), बेल्जियम (6.2), यूके (5.9), स्विट्ज़रलैंड (5.1)
7	खाद्य सब्जियां और कंद-मूल	नेपाल (94.1), बांग्लादेश (4.9), यूएई (0.6) यूके (0.2), कतर (0.1)	यूएसए (14.0), जर्मनी (9.4), यूके (5.7), भारत (5.4), फ्रांस (4.8)
40	रबर और रबर की वस्तुएं	नेपाल (98.5), भूटान (0.4), श्रीलंका (0.3) बांग्लादेश (0.2), सऊदी अरब (0.2)	यूएसए (14.5), चीन (9.7), जर्मनी (8.3), फ्रांस (3.7), मेक्सिको (3.6)
3	मछली और क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी जीव	वियतनाम (44.9), जापान (33.1), नेपाल (11.1), चीन (4.2), हांगकांग (3.3)	यूएसए (15.6), जापान (10.2), चीन (7.0), स्पेन (6.0), फ्रांस (4.7)
23	खाद्य उद्योग के अवशेष और अपशिष्ट	नेपाल (83.7), बांग्लादेश (10.8), वियतनाम (5.1), कंबोडिया (0.5)	जर्मनी (5.4), चीन (4.6), नीदरलैंड (4.6), वियतनाम (4.3), यूएसए (4.0)
42	चमड़े का सामान, घोड़े की ज़ीन, एनिमल गट्स	यूएसए (29.6), जर्मनी (20.7), यूके (13.2) स्पेन (4.6), नीदरलैंड (4.4)	यूएसए (18.2), जापान (7.7), हांगकांग (6.5), फ्रांस (6.3), जर्मनी (6.2)
12	तेल के बीज अलसी के फल; विविध-अनाज, बीज और फल	नेपाल (95.3), वियतनाम (3.4), थाईलैंड (0.6), ताइवान (0.6)	चीन (42.8), जर्मनी (5.7), जापान (4.3), नीदरलैंड (3.9), मेक्सिको (3.1)

नोट : बोल्ड में दर्शाए गए बाजार, बिहार से निर्यातित उत्पादों के प्रमुख आयातक हैं तथा उत्पाद श्रेणी में भी शीर्ष आयातक देश के रूप में दर्शाए गए हैं। आयातकों संबंधी आंकड़े 2017-18 के हैं तथा विश्व आयातों संबंधी आंकड़े 2017 के हैं।

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, आईटीसी ट्रेडमैप, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

बिहार में सात प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं - पटना प्रमंडल में पटना; मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय; तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर; पटना प्रमंडल में रोहतास; और पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया। राज्य में संभावित आईसीडी के लिए इन सातों प्रमुख उत्पादन केंद्रों का विश्लेषण किया गया। इन जिलों की वर्तमान उत्पादन क्षमता, लॉजिस्टिक नेटवर्क और बेहतर भौगोलिक स्थिति के आधार पर आईसीडी के लिए इन जिलों पर विचार किया गया। नए आईसीडी **(तालिका 22)** की स्थापना के लिए इन क्षेत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। इसमें उत्पादन केंद्रों से नजदीकी, परिवहन की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं तक पहुंच, सहायता सेवाओं, अन्य लॉजिस्टिक प्लैटफॉर्मों से नजदीकी और निवेश तथा परिचालनगत परिवेश जैसे पहलुओं पर विचार किया गया।

तालिका 22 : आईसीडी की स्थापना के लिए जिलों का तुलनात्मक विवरण

संकेतक	**मुजफ्फरपुर**	**भागलपुर**	**पूर्णिया**	**पटना**	**रोहतास**	**बेगूसराय**	**मुंगेर**	**बिहार राज्य**
जीडीडीपी प्रति व्यक्ति (जिला) - रु.	**15402**	**17324**	**10099**	**63063**	**13909**	**17587**	**22051**	**14574**
जनसंख्या - राज्य का %	**4.6**	**2.9**	**3.1**	**5.6**	**2.8**	**2.9**	**1.3**	**100**
उत्पादन संबंधी आंकड़े- राज्य के कुल उत्पादनका %								
कृषि उत्पादन - स्थान	**2**	**6**	**4**	**3**	**1**	**5**	**7**	**-**
कुल कृषि उत्पादन	4.24%	2.49%	3.04%	3.15%	**4.68%**	2.96%	1.15%	100
चावल	2.1%	0.9%	3.4%	2.2%	**7.8%**	1.0%	1.1%	100
गेहूं	4.3%	2.7%	1.4%	3.4%	**7.7%**	3.8%	0.6%	100
मक्का	1.5%	3.6%	**7.4%**	0.4%	0.0%	5.5%	0.1%	100
दलहन	2.7%	2.2%	1.5%	**12.5%**	3.0%	1.1%	0.8%	100
आम	**6.6%**	5.0%	1.7%	2.6%	4.0%	2.9%	0.9%	100
अमरूद	3.2%	1.6%	0.9%	2.4%	**7.3%**	1.2%	0.6%	100
लीची	**20.4%**	2.2%	4.2%	-	-	1.7%	1.1%	100
केला	**17.8%**	3.6%	2.9%	1.8%	1.0%	3.0%	1.1%	100
आलू	4.0%	2.6%	2.1%	**5.6%**	3.2%	2.9%	2.2%	100
प्याज	**5.6%**	3.2%	3.4%	5.2%	2.2%	3.4%	2.2%	100
गोभी	**6.6%**	2.9%	3.5%	0.1%	2.2%	3.5%	1.3%	100
बैंगन	3.2%	3.2%	1.8%	4.3%	1.7%	**5.2%**	1.4%	100
पशुधन संपदा - स्थान	**1**	**3**	**2**	**5**	**4**	**6**	**7**	**-**
कुल पशुधन संपदा	**4.5%**	3.6%	3.8%	2.7%	2.8%	2.1%	1.2%	100
गाय	2.8%	**4.2%**	4.1%	2.5%	3.2%	3.0%	1.4%	100
भैंस	3.7%	2.5%	1.8%	**3.9%**	**3.9%**	1.3%	0.7%	100
सूअर	0.8%	1.4%	2.9%	5.9%	1.7%	0.6%	1.2%	100
भेड़	1.0%	0.2%	0.0%	5.7%	**6.0%**	0.0%	0.1%	100
बकरी	4.6%	**4.8%**	4.2%	1.5%	3.0%	1.9%	1.4%	100
मुर्गी पालन	**6.7%**	2.8%	4.4%	3.1%	1.5%	2.0%	1.1%	100

संकेतक	मुजफ्फरपुर	भागलपुर	पूर्णिया	पटना	रोहतास	बेगूसराय	मुंगेर	बिहार राज्य
डेयरी उत्पादन-स्थान	**2**	**3**	**6**	**1**	**5**	**4**	**7**	**-**
जिला	3.8%	3.8%	2.40%	**5.5%**	3.1%	3.7%	1.6%	100
प्रमंडल	15.0%	6.4%	10.2%	**20.1%**	**20.1%**	12.0%	12.0%	100
सुदृढ़ परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे की मौजूदगी								
सड़क घनत्व - किमी/किमी² (स्थान)	**2**	**3**	**7**	**1**	**6**	**5**	**4**	**-**
एनएच सड़क घनत्व	0.08	0.06	0.04	**0.12**	0.05	0.05	0.06	0.05
एसएच सड़क घनत्व	0.02	0.03	0.04	**0.07**	0.05	0.02	0.02	0.04
एमडीआर सड़क घनत्व	0.15	0.11	0.07	**0.18**	0.10	0.11	0.03	0.12
आरआर सड़क घनत्व	**2.15**	1.09	1.65	1.19	0.86	1.15	0.59	1.38
रेलवे बुनियादी ढांचा - स्थान	**2**	**3**	**5**	**1**	**6**	**4**	**7**	**-**
अड्डों से निकटता								
पटना हवाईअड्डे से दूरी - किमी	79	242	374	0	146	132	185	-
कोलकाता से दूरी - किमी	594	**415**	503	579	576	497	470	-
सहायता सेवाएं - अन्य लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्मों से निकटता								
वाणिज्यिक बैंकों की संख्या	383	267	206	**954**	211	205	129	7267
गोदाम, भंडारण (जिला) - स्थान	**2**	**1**	**5**	**3**	**6**	**4**	**7**	**-**
एसडब्ल्यूसी क्षमता - एमटी	28757	**61583**	*	11742	0	9037	0	504221
सीडब्ल्यूसी क्षमता - एमटी	-	-	-	**23487**	6200	2500	8000	119520
कोल्ड स्टोरेज क्षमता (परिचालनरत) - एमटी	85621	15956	73548	56432	1529	120355	0	1285593
निवेश और परिचालन परिवेश								
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत - केडब्ल्यूएच	916	714	382	**4197**	785	452	310	258
वैट संग्रह ^ - लाख रु.	25706	14497	13344	**897516**	6664	6232	3920	1072609
औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या	69163	55272	52904	**147972**	52819	56329	26287	1707398
वैट संग्रह प्रति प्रतिष्ठान-रु.	37167	26228	25223	**606544**	12617	11064	14912	62821

* - पूर्णिया में एसडब्ल्यूसी की भंडारण क्षमता आधिकारिक स्रोतों में उल्लिखित नहीं है

^ - जीएसटी के संबंध में जिला स्तर के सार्वजनिक डाटा की अनुपलब्धता के चलते वैट का उल्लेख किया गया

स्रोत : बिहार सरकार, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, आरबीआई, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

आईसीडी सेवाओं की मांग की पूर्ति करने के लिए एक आईसीडी की स्थापना करना विचारणीय होगा। यह जिलों और प्रमंडलों में प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधि से संबंधित होगा। एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन से पता चलता है कि इन सभी सातों जिलों में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। जिलों में उत्पादन की बात करें तो फलोत्पादन, फूलों और सब्जियों तथा फसलोत्पादन में मुजफ्फरपुर और रोहतास सबसे उल्लेखनीय जिला उत्पादन केंद्रों के रूप में उभरे हैं। इसके अतिरिक्त, मुजफ्फरपुर के पड़ोसी जिले पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा भी शीर्ष कृषि उत्पादक जिलों में शामिल हैं। जिले में और जिले के आसपास कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना से मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार में एक बड़े उत्पादन क्लस्टर के रूप में उभरता है। राज्य के अन्य उल्लेखनीय कृषि उत्पादक जिलों में पटना (फूल, दालें और सब्जियां), रोहतास (अनाज और फल) तथा पूर्णिया (अनाज, मसाले और मखाना) शामिल हैं।

पशुपालन भी महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है और राज्य से निर्यातों में इसका प्रमुख स्थान है। पशुधन संपदा के मामले में मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया राज्य में अग्रणी हैं। पटना और तिरहुत प्रमंडल सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक हैं, जहां क्रमशः कुल दुग्ध उत्पादन का 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत उत्पादन होता है। कृषि और पशुधन संबंधी गतिविधियों के आधार पर राज्य में मुजफ्फरपुर मांग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरता है। इसके बाद भागलपुर और पूर्णिया का स्थान है।

अच्छे परिवहन बुनियादी ढांचे की उपस्थिति आईसीडी की स्थापना के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है। आम तौर पर आईसीडी वर्तमान बंदरगाहों / हवाईअड्डों से कुछ दूरी पर होते हैं और सुदृढ़ परिवहन बुनियादी ढांचा परिवहन लागत और समय को घटा सकता है।

सड़क बुनियादी ढांचे के मामले में पटना बिहार का सर्वाधिक विकसित जिला है। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और बहु-जिला सड़क मार्गों के सड़क घनत्व में पटना अग्रणी है। राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क घनत्व के मामले में पटना के बाद मुजफ्फरपुर का स्थान है, तो वहीं राज्य राजमार्गों में पटना के बाद रोहतास का स्थान है। पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के साथ स्थित मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी हैं। रेलवे बुनियादी ढांचे के मामले में, विश्लेषण बताता है कि पटना और मुजफ्फरपुर पूर्व मध्य रेल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन हैं, जिसमें बिहार का लगभग हिस्सा शामिल हो जाता है। वहीं, भागलपुर पूर्व रेल मंडल में तीसरा सबसे बड़ा जंक्शन है। समझा जा सकता है कि मौजूदा परिवहन ढांचे को देखते हुए पटना और मुजफ्फरपुर अग्रणी हैं।

पटना हवाईअड्डे और कोलकाता बंदरगाह से निकटता आईसीडी की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण पहलू होगा। विश्लेषण से पता चलता है कि जिन जिलों में आईसीडी के लिए विचार किया उनमें हवाईअड्डे तक पहुंच के मामले में मुजफ्फरपुर सबसे नजदीक है। पटना से यह मात्र 79 किलोमीटर दूर है। बेगूसराय, रोहतास और मुंगेर भी हवाईअड्डे से अधिक दूर नहीं हैं, जिनकी दूरी क्रमशः 132 किलोमीटर, 146 किलोमीटर और 185 किलोमीटर है। कोलकाता बंदरगाह तक पहुंच के मामले में भागलपुर सबसे नजदीक है, जो 415 किलोमीटर दूर है। विश्लेषण के अनुसार, पटना हवाईअड्डे और कोलकाता बंदरगाह तक पहुंच के मामले में मुजफ्फरपुर और भागलपुर प्रमुखता से उभरकर आते हैं।

आईसीडी के सुचारू संचालन के लिए सहायता सेवाओं और अन्य लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्मों से निकटता एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू है। आईसीडी पर सीमा शुल्क कार्यालय, बैंकिंग सेवाओं, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिलने की उम्मीद की जाती है। बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो फलों, सब्जियों, डेयरी उत्पादों और मांस उत्पादों जैसे जल्दी खराब होने वाले पदार्थों के निर्यातों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं प्रमुख सहयोगी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं हैं।

आईसीडी के लिए जिन जिलों पर विचार किया गया, उनमें मुजफ्फरपुर में सीमा शुल्क कार्यालय भी एक है। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के मामले में पटना अग्रणी है, जहां सर्वाधिक वाणिज्यिक बैंक हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर का स्थान है। भंडारण क्षमताओं के मामले में बिहार राज्य भंडारण निगम और केंद्रीय भंडारण निगम के अंतर्गत भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना अग्रणी जिले हैं। भागलपुर बिहार का उल्लेखनीय औद्योगिक केंद्र है, जिसकी भंडारण क्षमता उल्लेखनीय है, किन्तु कोल्ड स्टोरेज सुविधा तुलनात्मक रूप

से कम है। परिचालनगत भंडारण क्षमता के मामले में समस्तीपुर और वैशाली अग्रणी जिले हैं, किन्तु दोनों को ही इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया जा सका। ये दोनों ही मुजफ्फरपुर से निकट हैं। विश्लेषण किए गए जिलों में बेगूसराय, उसके बाद मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं हैं। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन भी तुलनात्मक रूप से अच्छा होता है और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विकास इन क्षेत्रों को और महत्त्वपूर्ण बनाता है। इस आधार पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय सबसे अधिक सहायता सेवा प्रादाता क्षेत्रों के रूप में उभरते हैं।

आपूर्ति के पहलू को देखते हुए आईसीडी सेवा प्रदाताओं के लिए निवेश और परिचालन परिवेश भी महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। परिचालन परिवेश के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति बिजली खपत, कुल वैट वसूली और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या की तुलना की गई है। प्रति व्यक्ति अधिक बिजली खपत वाले जिलों में अधिक बेहतर बिजली सुविधाएं हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, रोहतास और भागलपुर में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक बिजली खपत है, जो बेहतर बिजली सुविधाओं और बिजली की अच्छी उपलब्धता की ओर संकेत करती है। इसके अतिरिक्त, प्रति औद्योगिक प्रतिष्ठान उच्च वैट वसूली वाले जिलों में भी सकारात्मक निवेश और परिचालन परिवेश को इंगित करता है। प्रति औद्योगिक प्रतिष्ठान वैट वसूली पटना में सर्वाधिक है। इसके बाद मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया का स्थान है। आपूर्ति संबंधी विश्लेषण से पता चलता है कि मुजफ्फरपुर और भागलपुर बिहार में प्रमुख जिले हैं।

उपर्युक्त पैरामीटरों के आधार पर किए गए मूल्यांकन से पता चलता है कि आईसीडी के लिए मुजफ्फरपुर मुफीद स्थान है। कई अन्य पहलू हैं, जो मुजफ्फरपुर को आईसीडी की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनाते हैं। जैसे- एक बड़े कृषि उत्पादक क्लस्टर से निकटता, तुलनात्मक रूप से उच्चतर आर्थिक उत्पादन, परिवहन बुनियादी ढांचे तक अच्छी पहुंच, उल्लेखनीय भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं (मुजफ्फरपुर में और आसपास) तथा सकारात्मक निवेश और परिचालन परिवेश। गंगा के उत्तर में, पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के साथ स्थित मुजफ्फरपुर में निर्यातों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे के विकास से अच्छा लाभ मिल सकता है।

सेवा उपयोक्ताओं की संभावित उपयोगिता की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में तुलनात्मक रूप से बेहतर सड़क, रेल और वायु मार्ग संबंधी बुनियादी ढांचे के चलते यहां आईसीडी की स्थापना से माल का परिवहन अधिक सुगम हो सकेगा। मुजफ्फरपुर और कोलकाता को जोड़ने वाला सड़क और रेल नेटवर्क तथा पटना हवाईअड्डे से निकटता, इस जिले में आईसीडी की स्थापना के लिए और अधिक अनुकूल परिवेश बनाते हैं। उल्लेखनीय औद्योगिक विकास से जिले में वित्तीय और अन्य सहायता सेवाओं का भी विकास हुआ है और आईसीडी की स्थापना से इन सेवाओं से होने वाले लाभ को बढ़ाया जा सकता है। आईसीडी सेवा प्रदाताओं की उपयोगिता के मामले में भी मुजफ्फरपुर आईसीडी की स्थापना के लिए संभावित स्थल के रूप में उभरता है।

भागलपुर में आईसीडी की स्थापना पर भी विचार किया जा सकता है। भागलपुर जिले में भी तुलनात्मक रूप से बेहतर विकसित सड़क और रेल बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उल्लेखनीय कृषि और औद्योगिक उत्पादन क्षमता है। बिहार के उत्तर-पूर्व में उत्पादन केंद्रों से निकटता और गंगा के दक्षिण में स्थित होने के चलते कोलकाता बंदरगाह से भी इसकी दूरी अधिक नहीं है, जो इसे आईसीडी के लिए भौगोलिक रूप से उपयुक्त बनाती है। इसके अतिरिक्त, बिहार के अन्य जिलों की तुलना में भागलपुर में निवेश और परिचालनगत परिवेश भी अधिक बेहतर है।

द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त डाटा और सूचनाओं का इस्तेमाल करते हुए किए गए प्राथमिक शोध के आधार पर मुजफ्फरपुर और भागलपुर में आईसीडी की स्थापना की संस्तुति की जाती है। तथापि, इन दोनों स्थानों पर आईसीडी की वाणिज्यिक अर्थक्षमता के साथ-साथ इनकी स्थापना में लगने वाली लागत और उससे होने वाले फायदों के मूल्यांकन के लिए एक विस्तृत टेक्नो-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाना चाहिए। पटना के मौजूदा आईसीडी पर निर्यात परिवहन को लाने के लिए वहां भी एक सीमा शुल्क मंजूरी कार्यालय की संस्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त, आईसीडी के पास निर्यात जांच परिषद कार्यालय की स्थापना करने की भी जरूरत है, ताकि वस्तुओं के लिए मूल उत्पत्ति के स्थान संबंधी प्रमाणपत्र प्रदान किए जा सकें। विनियमित बाजारों में प्रवेश के लिए ये प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त, पटना और गया जैसे प्रमुख केंद्रों पर एयर

कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने तथा फतुहा और बीठा कंटेनर फ्रेट टर्मिनलों के उन्नयन की भी जरूरत है। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 में भी इसका उल्लेख विशेष रूप से किया जा चुका है।

भंडारण और कोल्ड स्टोरेज

पर्याप्त परिवहन, भंडारण और वितरण सेवाओं का अभाव देशभर के निर्यातकों के लिए एक बड़ा मसला है। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में यह प्रमुख बाधा के रूप में उभरकर सामने आता है। क्योंकि बिहार से निर्यातों में जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की अच्छी मात्रा है। कृषि और संबद्ध उत्पाद राज्य से निर्यातित प्रमुख उत्पाद हैं। इसके अतिरिक्त, फार्मास्यूटिकल्स को भी राज्य के लिए 'प्रोडक्ट चैंपियंस' श्रेणी में रखा गया है। इन खंडों से निर्यातों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी।

बिहार में कुल भंडारण क्षमता 623741 मीट्रिक टन (एमटी) है। इसमें से 504221 एमटी की स्थापना राज्य भंडारण निगम और 119520 एमटी की स्थापना केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा की गई है। क्षमता के मामले में, पटना प्रमंडल में लगभग 38.8 प्रतिशत क्षमता है। इसके बाद पूर्णिया (14.3 प्रतिशत) और तिरहुत (12.8 प्रतिशत) का स्थान है। अगस्त 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल भंडारण क्षमता का 1.4 प्रतिशत बिहार में है **(तालिका 23)**, जो देश के कुल अनाज उत्पादन में बिहार के लगभग 6.7 प्रतिशत के हिस्से को देखते हुए काफी कम है।

तालिका 23 : बिहार में भंडारण क्षमता (एमटी)

प्रमंडल	एसडब्ल्यूसी	सीडब्ल्यूसी	कुल	बिहार के कुल में हिस्सा %
तिरहुत	75197	4400	79597	12.8%
सारण	26591	13216	39807	6.4%
दरभंगा	13258	23870	37128	6.0%
कोसी	5660	9211	14871	2.4%
पूर्णिया	68956	20000	88956	14.3%
पटना	203816	38323	242139	38.8%
मगध	30123	-	30123	4.8%
मुंगेर	19037	10500	29537	4.7%
भागलपुर	61583	-	61583	9.9%
बिहार कुल	**504221**	**119520**	**623741**	**100.0%**
भारत कुल	**35776000**	**9969000**	**45745000**	**-**
भारत में बिहार का हिस्सा	**1.4%**	**1.2%**	**1.4%**	**-**

नोट : आंकड़े यथा अगस्त 2018

स्रोत : केंद्रीय भंडारण निगम, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

इसके अलावा, राज्य से निर्यात किए जाने वाले कई उत्पादों के लिए कोल्ड चेन संबंधी बुनियादी ढांचा भी महत्त्वपूर्ण होगा। इससे बागवानी और पुष्पोत्पादन से होने वाली उपज को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकेगा और अंततः ये उत्पाद विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लक्षित-उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए अधिक लंबे समय तक उपलब्ध हो सकेंगे। कोल्ड-चेन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए भी उपयोगी होगी। फार्मास्यूटिकल, जीवन विज्ञान, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को भी तापमान-नियंत्रित भंडारण में अलग-अलग तापमान की आवश्यकता होती है। बिहार के उद्यान निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार में यथा अगस्त 2017 को 1.9 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा है, जिसमें से लगभग 1.3 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता परिचालन में है।

चार्ट 11 : कोल्ड-चेन भंडारण के लिए अपेक्षित खंड

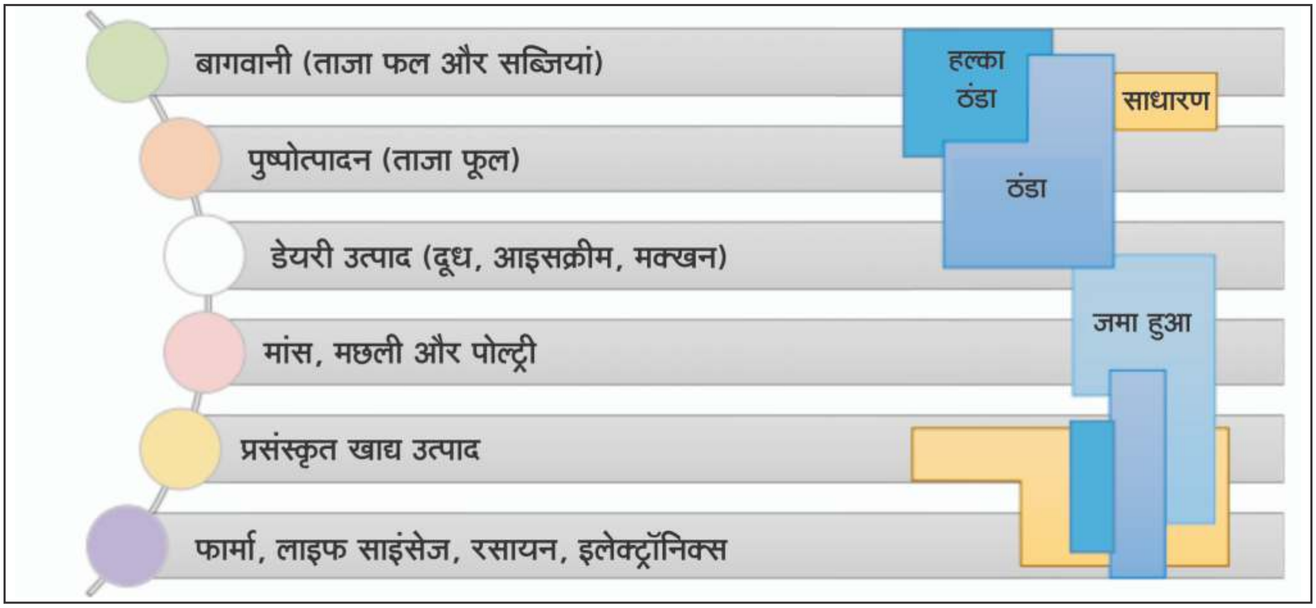

स्रोत : नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवलपमेंट

तालिका 24 : बिहार में कोल्ड-चेन संबंधी बुनियादी ढांचा (यथा अगस्त 2018, परिमाण एमटी में)

		परिचालनगत		क्षमता		कुल	
	प्रमंडल	परिमाण	हिस्सा	निर्माण	निष्क्रिय	परिमाण	हिस्सा
अंचल 1	तिरहुत	366833.5	28.5%	35349.0	75922.4	478104.9	25.8%
	सारण	182788.2	14.2%	44494.2	58178.3	285460.6	15.4%
	दरभंगा	219893.8	17.1%	0.0	33023.5	252917.3	13.7%
अंचल 2	कोसी	30296.0	2.4%	0.0	12300.0	42596.0	2.3%
	पूर्णिया	138339.2	10.8%	31247.5	9733.0	179319.7	9.7%
अंचल 3बी	पटना	167629.2	13.0%	25638.8	109720.6	302988.6	16.4%
	मगध	41550.0	3.2%		55252.0	96802.0	5.2%
अंचल 3ए	मुंगेर	122306.9	9.5%	6103.7	42198.1	170608.7	9.2%
	भागलपुर	15956.4	1.2%	0.0	25964.0	41920.4	2.3%
कुल बिहार		**1285593.0**	**100.0%**	**142833.2**	**422291.8**	**1850718.**	**100.0%**

स्रोत : बिहार राज्य उद्यान निदेशालय, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

राज्य में भंडारण और कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य में खाद्यान्नों की आपूर्ति श्रृंखला के लिए भंडारण महत्त्वपूर्ण होगा। यदि भंडारण क्षमता उत्पादन की लगभग 70 प्रतिशत भी मानें तो बिहार में 13 मिलियन एमटी क्षमता वाले गोदामों की जरूरत है, जबकि वर्तमान में सिर्फ 0.6 मिलियन एमटी की ही क्षमता है। इसके अतिरिक्त, राज्य में अनुमानित 2.2 मिलियन एमटी के कोल्ड चेन स्टोरेज बुनियादी ढांचे के विकास की भी जरूरत है। इसके साथ-साथ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की जरूरत है। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट ने 2015 में राज्य में लगभग 2.2 मिलियन मीट्रिक टन कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की आवश्यकता का आकलन किया था। तब से लगभग 0.5 मिलियन मीट्रिक टन कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे का विकास हो पाया है, जो राज्य की आवश्यकता से काफी कम है। कुशल कृषि वैल्यू चेन के लिए कटाई से लेकर अंतिम गंतव्य

तक, व्यापार चक्र के सभी चरणों में कोल्ड चेन स्थापित करने को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

एसईजेड अधिनियम 2005 के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार या वस्तुओं के निर्माण में शामिल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित किया जा सकता है। यहां तक कि भारत में कोई विदेशी कंपनी भी एसईजेड स्थापित कर सकती है। निजी क्षेत्र भारत के कई राज्यों में एसईजेड के विकास में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

एसईजेड न्यूनतम नियामकीय प्रतिबंधों के साथ अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और अनुकूल व्यावसायिक परिवेश प्रदान करते हैं। इन कारकों के चलते एसईजेड में निर्यात-उन्मुख एफडीआई के लिए आवश्यक परिवेश मिलता है। नतीजतन, उत्पादन, रोजगार और निर्यातों में इन क्षेत्रों का काफी योगदान है। वस्तुतः हाल के वर्षों के दौरान एसईजेड से निर्यात में वृद्धि, भारत से निर्यातों में वृद्धि की तुलना में अधिक रही है। उदाहरण के लिए, 2017-18 के दौरान भारत से कुल वस्तु निर्यातों में रुपये राशि में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं एसईजेड से निर्यातों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

औद्योगिक विकास और निर्यातों में एसईजेड के महत्त्व को देखते हुए, बिहार में वर्तमान में किसी एसईजेड का न होना चिंता का विषय है। राज्य में एसईजेड की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति, अधिनियम या नियम भी नहीं हैं। निर्यात उन्मुख एफडीआई को आकर्षित करने और राज्य से निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए एसईजेड की स्थापना महत्त्वपूर्ण होगी। पटना, मुजफ्फरपुर या भागलपुर जिलों में एसईजेड स्थापित किए जा सकते हैं, जहां सड़क और रेल मार्ग से अच्छी कनेक्टिविटी है। कृषि क्षेत्र से अच्छे निर्यातों को ध्यान में रखते हुए इनमें से किसी एक एसईजेड को कृषि उत्पादों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

क्षमता विकास

भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) की ब्रांडिंग

बिहार के हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादों के लिए भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) दर्जा बिहार के उत्पादों को अलग कतार में ला सकता है और यह मार्केटिंग का महत्त्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। उत्पादन की परंपरागत पद्धतियों के साथ-साथ भौगोलिक मूल स्थान का संदर्भ इन उत्पादों की मार्केटिंग को नए आयाम दे सकता है। यद्यपि बिहार में हस्तशिल्प से लेकर कृषि उत्पादों तक जीआई दर्जे वाले कई उत्पाद हैं **(तालिका 25)**, तथापि इस क्षेत्र में और काम किया जा सकता है।

जीआई दर्जे का लाभ उठाने के लिए, जीआई ब्रांड को बाजार में एक विश्वसनीय और पसंदीदा ब्रांड के रूप में स्थापित करना और उसकी एक अलग जगह बनाना महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में दार्जीलिंग चाय को ही लीजिए। दार्जीलिंग चाय ने इस ब्रांड के विकास के चलते ही बाजार पर अच्छी पकड़ बना ली है। इसी तरह की कामयाबी हासिल करने के लिए जीआई दर्जे वाले उत्पादों के लिए सुनियोजित मूल्यांकन को परिभाषित करने की जरूरत है। जीआई उत्पादों के लिए अलग लोगो और नाम विकसित करने और फिर उन्हीं नामों से उनकी मार्केटिंग करने की जरूरत है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जीआई ब्रांड के अंतर्गत बाजार में उतारे जाने वाले उत्पाद न्यूनतम विनिर्दिष्ट मानकों पर खरे उतरें।

इस संबंध में, बिहार सरकार मूलतः बिहार से बनने वाले उत्पादों के लिए वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी ब्रांड बनाने हेतु एक ब्रांड इक्विटी फंड स्थापित कर सकती है। इस फंड से इन ब्रांडेड उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मार्केटिंग के लिए भी सहायता ली जा सकती है। राज्य के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में लोकप्रिय बनाने के लिए निर्यात संबंधी ब्रोशरों के साथ-साथ चर्चापरक सीडी आदि बनाई जा सकती हैं।

राज्य से निर्यातों को बढ़ाने के लिए ऐसे अन्य उत्पादों को चिह्नित करने की पहल की जानी भी आवश्यक है, जिनके लिए जीआई दर्जा लिया जा सकता है। इनमें मखाना जैसे कृषि उत्पाद और लिट्टी-चोखा व लक्ठो जैसे खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं।

मानक, विनियम और गुणवत्ता

राज्य के निर्यातकों को गुणवत्ता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और मानकों को बनाए रखने की जरूरत है। बहुत से आयातक देश हैं, जो उत्पादों के लिए अपनी विशिष्टताएं निर्धारित करते हैं। ऐसे देशों को निर्यात करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं को पूरा करना आवश्यक होता है। यह निर्यात चक्र से जुड़े विभिन्न पक्षों का उत्तरदायित्व है कि राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद इन मानकों पर खरे उतरें।

तालिका 25 : बिहार के जीआई दर्जा प्राप्त उत्पाद

उत्पाद	क्षेत्र
मधुबनी पेंटिंग	हस्तशिल्प
बिहार का एप्लीक काम (खतवा)	हस्तशिल्प
बिहार की सुजनी कढ़ाई का काम	हस्तशिल्प
बिहार के सिक्की घास उत्पाद	हस्तशिल्प
भागलपुर सिल्क	हस्तशिल्प
भागलपुरी जरदालु	कृषि
कतरनी चावल	कृषि
मगही पान	कृषि
बिहार की शाही लीची	कृषि
सिलाव खाजा	मिठाई

स्रोत : बौद्धिक संपदा भारत

इसके लिए एक अनुकूल ईको-सिस्टम विकसित करने की जरूरत है, जिसमें फाइटोसैनिटेशन प्रमाणीकरण, ऑर्गैनिक प्रमाणीकरण, कीटनाशी मुक्त उत्पाद की सख्त अपेक्षाओं को पूरा करना, पैकेजिंग और लेबलिंग शामिल हैं। कंफर्माइट यूरोपीयन (सीई), चाइना कंपल्सरी सर्टिफिकेट (सीसीसी), जीएमपी आदि जैसे सांविधिक प्रमाणीकरण प्राप्त करने में निर्यातक द्वारा किए गए खर्च की आधी राशि तक को रिफंड करने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि प्रति निर्यातक ईकाई रिफंड की एक उच्चतम सीमा निर्धारित करनी होगी। इसके साथ ही, इन प्रमाणीकरणों से संबंधित जानकारियों के प्रसार के लिए प्रमुख उत्पादन केंद्रों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। इनमें प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने में मदद से लेकर बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहयोग की जानकारी दी जा सकती है।

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण

भारत सरकार ने भारतीय विनिर्माताओं को वैश्विक बाजार से स्पर्धा और वृद्धि हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करने और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण में सहायता के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) कम समय में प्रौद्योगिकी जुटाने के उद्देश्य से की गई उद्योग आधारित ऐसी ही एक पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को रणनीतिक और संबंधित प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रूट, इन-हाउस रूट अथवा कॉन्ट्रैक्ट और इन-हाउस के संयुक्त रूट के जरिए प्रौद्योगिकी विकास के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार, एमएसएमई क्षेत्रों द्वारा हरित प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण को सुगम बनाने और प्रौद्योगिकी संबंधी अंतर को किफायती लागत पर भरने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि (टीएडीएफ) योजना शुरू की गई है। बिहार के निर्यातक उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यातों को बढ़ाने के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इस संबंध में, राज्य सरकार इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने में निर्यातकों की सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए, टीएएफपी के अंतर्गत आवेदकों को प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के लिए किसी विशेषज्ञ थर्ड पार्टी और मान्यता प्राप्त एजेंसी से एक अनिवार्य विस्तृत मूल्यांकन अध्ययन कराना अनिवार्य होता है। यह अध्ययन मौजूदा व्यवसाय में सुधार के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता है -

- आवेदन क्षेत्र के साथ-साथ अन्य प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों के संबंध में प्रस्तावित प्रौद्योगिकी की तकनीकी विलक्षणता;
- प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के वित्तीय मूल्यांकन के लिए वाणिज्यिक अर्थक्षमता और समुचित स्पष्टीकरण;

- मौजूदा व्यवसाय में सुधार के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आवश्यक विवरण।

योजना की प्रस्ताव हेतु अनुरोध प्रक्रिया शुरू करने से पहले राज्य सरकार राज्य में निर्यात उन्मुख ईकाइयों / क्लस्टरों / कंसोर्शियम से आवेदन मंगा उनकी समीक्षा कर सकती है तथा आवेदन तैयार करने के लिए आवश्यक सलाहकारी और वित्तीय सहायता दे सकती है। चूंकि ये कार्यक्रम प्रौद्योगिकी अधिग्रहण की लागत के एक निश्चित हिस्से (टीएएफपी के मामले में 25 प्रतिशत, जो 10 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) को ही पूरा करते हैं, इसलिए राज्य सरकार मामले-वार आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकती है।

वित्तीय प्रोत्साहन

वैश्विक बाजार में घरेलू उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कभी-कभी वित्तीय प्रोत्साहन भी जरूरी होते हैं। बिहार में निर्यात अभी उदीयमान अवस्था में हैं। ऐसे में राज्य के निर्यातकों को कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।

चूंकि बिहार राज्य बंदरगाह विहीन है, अतः यहां के निर्यातकों की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने की जरूरत है। पुष्पोत्पादन, ताजा फलों, ताजा सब्जियों, पोल्ट्री, डेयरी उत्पादों और औषध पादपों पर ढुलाई भाड़े में सब्सिडी के रूप में एपीडा द्वारा सहायता दी जाती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा चुनिंदा राज्यों को ढुलाई सब्सिडी भी दी जाती थी, लेकिन 2016 से यह बंद कर दी गई है। इस तरह की सहायता निर्यातकों को बुनियादी ढांचागत अभावों के चलते बढ़ने वाली निर्यातों की लागत को कम करने में मदद मिलती है।

बिहार सरकार द्वारा राज्य से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों के ढुलाई भाड़े पर राज्य स्तर पर इसी तरह की सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जा सकती है। बजट को ध्यान में रखते हुए, ढुलाई भाड़ा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति की पात्रता और प्रतिपूर्ति की राशि जिला तथा उत्पाद-वार निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार वायु मार्ग द्वारा भेजे गए निर्यात कार्गो पर निर्यात उन्मुख ईकाइयों को सब्सिडी प्रदान करती है तथा गेटवे पोर्ट पर ढुलाई भाड़े पर सब्सिडी प्रदान करती है।[4] इसी तरह, पंजाब सरकार राज्य के किसी भी कोने में स्थित निर्यात उन्मुख एमएसएमई द्वारा माल के निर्यातों के लिए ढुलाई भाड़े में सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि फ्री ऑन बोर्ड मूल्य की 1 प्रतिशत अथवा वास्तविक ढुलाई भाड़े (सरकारी शुल्क और विनिर्माण स्थल से बंदरगाह और हवाईअड्डे तक माल के परिवहन पर लगने वाले कर को छोड़कर), जो भी कम हो, निर्धारित की गई है तथा इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये प्रति वर्ष है[5]।

निर्यात संवर्धन अभियान

निर्यात पुरस्कार

कृषि और कृषि संबंधी उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन व रसायन-संबंधी उत्पाद, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, टेक्सटाइल और गारमेंट, इंजीनियरिंग उत्पाद व पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निर्यातकों के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात पुरस्कार शुरू किए जा सकते हैं। राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अलग से पुरस्कार शुरू किए जा सकते हैं। प्रमुख सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों तथा प्रख्यात उद्योगपतियों वाली एक चयन समिति द्वारा इन पुरस्कारों के लिए आए आवेदनों का मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यांकन में निर्यात मूल्य, कुल बिक्री में निर्यातों का अनुपात, मूल्यवर्धन का स्तर, सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना, उत्पाद और प्रक्रिया में नवोन्मेष, शोध और विकास गतिविधियों जैसे मानक शामिल किए जा सकते हैं।

औद्योगिक क्लस्टरों में क्षमता विकास

किसी क्षेत्र या उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में औद्योगिक क्लस्टरों के कई फायदे होते हैं। यह देखा गया है कि यदि विभिन्न

[4] "औद्योगिक निवेश एवं रोजगार नीति, उत्तर प्रदेश 2017," उत्तर प्रदेश सरकार

[5] औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति 2017 के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए विस्तृत योजनाएं एवं परिचालन संबंधी दिशानिर्देश, 2018, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पंजाब सरकार।

उद्यम एक दूसरे का सहयोग करते हुए सामूहिक सोर्सिंग और मार्केटिंग सहित समान सुविधाओं के इस्तेमाल और सामूहिक गतिविधियों के साथ क्लस्टर परिवेश में काम करें तो उनमें स्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ती है।

बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में कई औद्योगिक क्लस्टर हैं। इन क्लस्टरों का विकास और उन्नयन राज्य सरकार के लिए महत्त्वपूर्ण एजेंडा होगा। सरकार को सबसे पहले राज्य में मौजूदा क्लस्टरों का मूल्यांकन करना होगा। इस मूल्यांकन में बुनियादी ढांचागत चुनौतियां प्रौद्योगिकी उन्नयन, कुशल मानव संसाधन तक पहुंच, पर्यावरणीय स्थिरता आदि से जुड़े पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। क्लस्टरों के मूल्यांकन के बाद सरकार द्वारा उचित क्षमता विकास गतिविधियां चलाई जा सकती हैं। क्षमता विकास में प्रमुख रूप से भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, संस्थाओं की स्थापना और मानव संसाधनों का विकास शामिल होगा।

बाजार विकास सहयोग

भारत सरकार की मार्केटिंग विकास सहायता योजना निर्यातकों को विदेश में निर्यात संवर्धन गतिविधियों में मदद करती है। उद्यमियों को व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। ये पहलें निर्यात संवर्धन गतिविधियों में निर्यातकों के लिए सहायक साबित हुई हैं। इन गतिविधियों में राज्य से निर्यातकों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय मर्केटिंग विकास सहायता योजना शुरू की जा सकती है। राज्य के निर्यात कुछ एक क्षेत्रों में ही संकेन्द्रित हैं और इस प्रकार की योजना निर्यात गंतव्यों के विशाखन में सहायक होगी। इस योजना के क्रियान्वयन को उच्च वैल्यू ऐडेड और प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों के निर्यातकों पर फोकस के साथ खंड विशिष्ट बनाने की जरूरत है।

संस्थागत समन्वय

बिहार के समग्र आर्थिक परिवेश को इस रूप में विकसित करने की जरूरत है जो राज्य से निर्यातों को बढ़ावा देने में सक्षम हो। संबंधित राज्य मशीनरियों से बना संस्थागत ढांचा इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण हो सकता है। इस संदर्भ में, अध्ययन में बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत बिहार निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने की संस्तुति की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य से निर्यात निष्पादन को बढ़ावा देना होगा। इस परिषद की स्थापना राज्य सरकार, निर्यातकों और उद्योग संघों की भागीदारी से की जा सकती है। साथ ही यह परिषद विचारों तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान कर सकती है तथा निर्यातकों के सामने आने वाली परेशानियों को चिह्नित करने और उनसे निपटने के उपाय कर सकती है।

बिहार में सम्पूर्ण परिवेश इस प्रकार बनाने की जरूरत है जिससे राज्य की गिनती उच्चतर निर्यातकों में हो सके। इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य मशीनरी के साथ संस्थागत ढांचे की अहम भूमिका रहेगी। इस संदर्भ में, राज्य से बेहतर निर्यातों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत बिहार निर्यात संवर्धन परिषद (बीईपीसी) का गठन किया जा सकता है। इस परिषद का गठन राज्य सरकार, निर्यातकों और उद्योग संघों की सहभागिता से किया जा सकता है। यह परिषद निर्यातकों के बीच विचारों के आदान प्रदान के साथ-साथ जानकारी साझा करने, निर्यातकों के सामने आने वाली बाधाओं को चिह्नित कर उन्हें दूर करने के संभावित समाधान करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगी।

बीईपीसी के प्रस्तावित ढांचे में चार मुख्य परिचालन क्षेत्र होंगे- मर्चेंडाइज निर्यात प्रमंडल, सेवा निर्यात प्रमंडल, निर्यात संपर्क प्रमंडल और सूचना प्रौद्योगिकी प्रमंडल **(चार्ट 12)**। इसके अलावा, बीईपीसी के विभिन्न कार्यों के एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (पीएमयू) की स्थापना भी की जा सकती है। इन प्रमंडलों के कार्य निम्नलिखित अनुसार होंगे :

1. **मर्चेंडाइज व सेवा प्रमंडल :** मर्चेंडाइज विंग राज्य निकायों, निर्यातकों आदि से समन्वय करते हुए मर्चेंडाइज निर्यात खंड पर फोकस कर सकती है। वहीं, सेवा विंग आईटी और पर्यटन जैसे सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इन दोनों विंग में सरकारी अधिकारी शामिल होंगे, जो अपने संबंधित क्षेत्रों में लक्ष्य हासिल करने के लिए रणनीतियां बनाएंगे। ये निर्यातकों को सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करेंगे।

   मर्चेंडाइज और सेवा विंग में क्षेत्र विशिष्ट (सेक्टोरल) समितियां और क्षेत्रीय समितियां भी बनाई जा सकती हैं। सेक्टोरल समिति निर्यात संवर्धन उत्पादों और निर्यात किए जाने वाले क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्यों का प्रबंधन कर सकती है। वहीं, क्षेत्रीय समिति दूतावासों / उच्चायोगों, निर्यात संवर्धन

परिषदों, एक्ज़िम बैंक और अन्य वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के जरिए भारत और विदेश स्थित व्यापार और वाणिज्य संबंधी कार्यालयों के साथ कार्य कर सकती है। सेक्टोरल समिति जीआई के लिए आवेदनों, प्रस्तावित ढुलाई भाड़ा सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाभ देने, प्रस्तावित ब्रांड इक्विटी फंड के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने और भारत सरकार के प्रौद्योगिकी अधिग्रहण कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्यातकों को लाभ प्रदान करने पर फोकस कर सकती है। वहीं, क्षेत्रीय समिति प्रस्तावित मार्केटिंग विकास सहायता कार्यक्रम और विभिन्न बाजारों में निर्यातों के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति पर फोकस कर सकती है।

2. **निर्यात संपर्क प्रमंडल :** यह निर्यात संबंधी महत्त्वपूर्ण सहायता सेवाएं प्रदान करेगा और इसमें गुणवत्ता प्रणाली, वित्त सुविधा, प्रशिक्षण और कौशल विकास, ब्रांडिंग, प्रचार और मार्केटिंग जैसी प्रत्येक सहायता सेवा के लिए अलग ईकाइयां हो सकती हैं। इस विभाग में विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। निर्यात संपर्क प्रमंडल की विभिन्न ईकाइयों के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं :

- **गुणवत्ता प्रमंडल :**
  - o गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण प्रोटोकॉल पर फोकस बढ़ाना
  - o निर्यातों से जुड़े विभिन्न पक्षों तक महत्त्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाना
  - o क्षेत्रीय समिति को मानकों और प्रमाणीकरण पर इनपुट देना
- **प्रौद्योगिकी प्रमंडल :**
  - o गुणवत्ता प्रमंडल से इसका समन्वय होना चाहिए और इसमें विषय विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए, जो प्रौद्योगिकी व नवोन्मेष को बढ़ाने के लिए निर्यातों से जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ काम करेंगे
  - o वैल्यू एडिशन के संबंध में जानकारियों का प्रसार करना और स्थानीय उत्पादों व सेवाओं में स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना
  - o प्रौद्योगिकी अधिग्रहण फंडिंग के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की सहायता के लिए सेक्टोरल समिति को इनपुट प्रदान करना
- **क्षमता विकास ईकाई :**
  - o राज्य में निर्यातकों के लिए समुचित कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, क्षेत्र कौशल परिषद और राज्य स्तर के संस्थानों के साथ काम करना
- **वित्त विंग :**
  - o निर्यात वित्त और गारंटी का लाभ उठाने संबंधी प्रक्रियाओं पर सूचना का प्रसार करना
- **ब्रांडिंग, प्रचार और मार्केटिंग :**
  - o स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सुधार की दिशा में काम करना
  - o प्रस्तावित ब्रांड इक्विटी फंड के तहत वित्तपोषण के लिए सेक्टोरल समिति को इनपुट प्रदान करना
  - o जीआई के आवेदन पर सेक्टोरल समिति को परामर्श देना
  - o मार्केटिंग विकास सहायता योजना के तहत वित्तपोषण पर क्षेत्रीय समिति को परामर्श देना

3. **आईटी प्रमंडल :** आईटी प्रमंडल वेबसाइटों, कौशल और प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित विभिन्न पक्षों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रणालियों का प्रबंधन कर सकता है।

4. **कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (पीएमयू) :** बीईपीसी के विभिन्न प्रभागों के सभी कार्यों को एकीकृत करने के लिए पीएमयू की स्थापना की जा सकती है। पीएमयू निर्यात लक्ष्यों, उन्हें हासिल करने और उन्हें हासिल करने में समय-समय पर आ रही बाधाओं की निरंतर निगरानी कर सकती है, ताकि अनुमानित लक्ष्यों से विचलन होने पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पीएमयू महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय निर्यात निकायों से संपर्क कर सकती है।

चार्ट 12 : बिहार निर्यात संवर्धन परिषद का ढांचा

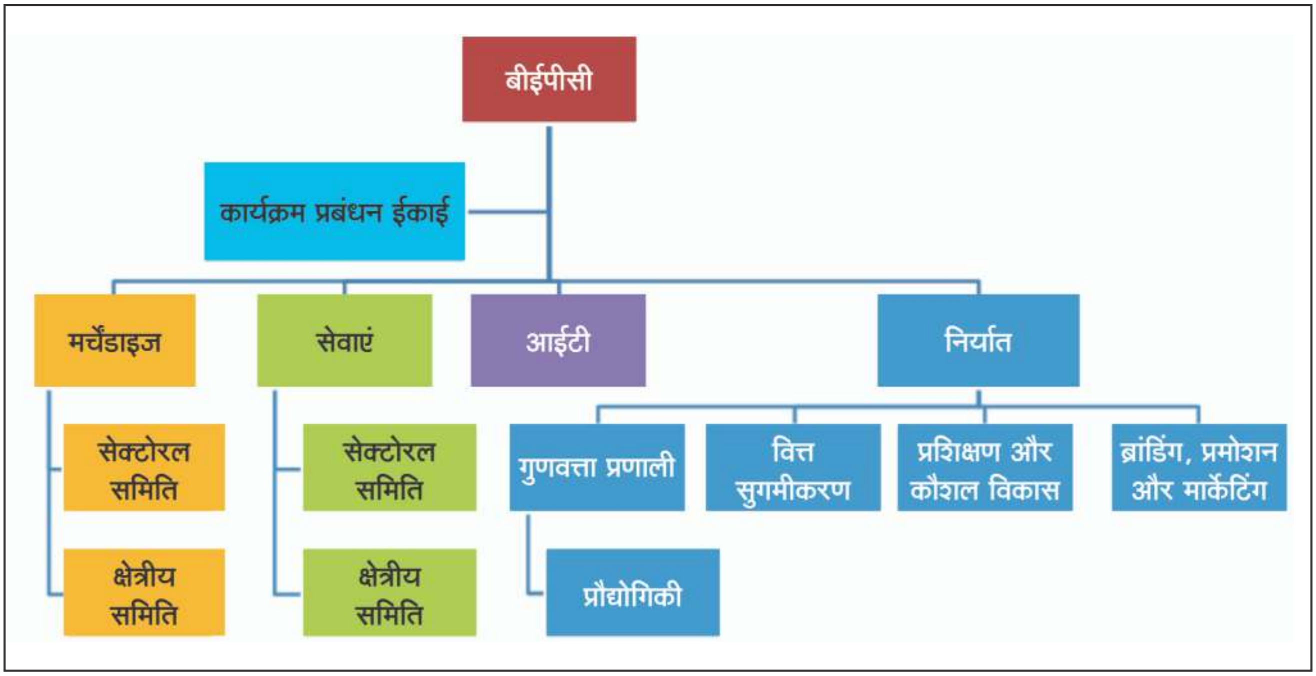

संस्थागत मजबूती के लिए निर्यातों के लिए एकल सूचना पोर्टल स्थापित किया जा सकता है। इस पोर्टल के जरिए निर्यातकों को अपनी जानकारी बढ़ाने और बाजारों, वित्त, निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों का विवरण हासिल करने में मदद मिलेगी। पोर्टल के माध्यम से सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। इस पोर्टल को सीधे बीईपीसी के आईटी प्रमंडल द्वारा प्रशासित और प्रबंधित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

राज्य से 40 अरब यूएस डॉलर के निर्यात के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापार स्पर्धात्मकता बढ़ाने, नवोन्मेष को बढ़ावा देने, निर्यात वित्त की उपलब्धता बढ़ाने, ब्रांडिंग के वृहत्तर प्रयास करने और निर्यातों के लिए संस्थागत क्षमताएं बढ़ाने जैसे उपायों की जरूरत होगी। इस अध्ययन में रेखांकित की गई छह-बिंदुओं वाली रणनीति राज्य के लिए निर्यात नीति बनाने तथा वांछित परिणाम हासिल करने के लिए कार्ययोजना बनाने में मददगार होगी।

अनुलग्नक : प्रोडक्ट चैंपियंस श्रेणी में बिहार के लिए प्रमुख बाजार और प्रतिस्पर्धी

एचएस कोड	विवरण	बिहार से निर्यात ('000 यूएस डॉलर)	वैश्विक आयात (मिलियन यूएस डॉलर)	भारत के निर्यातों में बिहार का हिस्सा	शीर्ष आयातक	आयात (मिलियन यूएस डॉलर)	विश्व आयातों में हिस्सेदारी	बाजार में शीर्ष आपूर्तिकर्ता
20622	फ्रोजन गोवंशीय लिवर	126.0	501.4	1.2%	बेल्जियम	7.9	12.0%	जर्मनी (59.1), नीदरलैंड (23.9), इटली (5.4), पोलैंड (4.4), डेनमार्क (4.1)
					इंडोनेशिया	6.4	9.7%	ऑस्ट्रेलिया (71.8), न्यूजीलैंड (15.7), यूएसए (12.4), स्पेन (0.1)
					ब्राजील	5.1	7.8%	ऑस्ट्रेलिया (41.6), अर्जेंटीना (40.1), उरुग्वे (8.4), यूएसए (7), पैराग्वे (2.9)
					कोत दि'वार	4.8	7.2%	फ्रांस (37.8), आयरलैंड (14.3), नीदरलैंड (7.4), बेल्जियम (6.9), यूके (6.2)
					मोज़ाम्बिक	3.6	5.4%	यूएसए (35.3), कनाडा (24.3), इटली (9.6), ऑस्ट्रिया (6.5), दक्षिण अफ्रीका (4.4)
20629	फ्रोजेन गोजातीय ऑफल (जिह्वा और लिवर को छोड़कर)	7449.9	2153.0	4.0%	**हांगकांग**	979.8	56.3%	ब्राजील (50.6), यूएसए (14.5), अर्जेंटीना (8.5), ऑस्ट्रेलिया (7.6), उरुग्वे (2.9)
					मेक्सिको	163.2	9.4%	यूएसए (89.6), कनाडा (7.6), ऑस्ट्रेलिया (1.9), निकारागुआ (0.6), न्यूजीलैंड (0.2)
					दक्षिण कोरिया	156.9	9.0%	ऑस्ट्रेलिया (52.1), यूएसए (33.1), न्यूजीलैंड (12.3), कनाडा (2), चिली (0.3)
					चीन	69.5	4.0%	उरुग्वे (59.4), ऑस्ट्रेलिया (21.6), न्यूजीलैंड (16.5), कोस्टारिका (2.5), यूएसए (2-6)
					इंडोनेशिया	64.6	3.7%	ऑस्ट्रेलिया (50.8), यूएसए (31.3), न्यूजीलैंड (15.1), कनाडा (2.1), स्पेन (0.5)
					नीदरलैंड	20.6	35.2%	फ्रांस (20.1), चेकिया (19), बेल्जियम (18.5), जर्मनी (17.6), इंडोनेशिया (7.1)
					इटली	4.5	7.6%	ग्रीस (19.5), इंडोनेशिया (18.7), फ्रांस (15.3), पुर्तगाल (13.5), स्पेन (9.7)

30119	जिंदा सजावटी मछली (मीठे पानी को छोड़कर)	36.0	75.5	4.8%	**हांगकांग**	4.4	7.4%	इंडोनेशिया (23.4), यूएसए (22.7), फिलीपींस (19.6), जिबूती (5.4), श्रीलंका (5.1)
					जर्मनी	3.4	5.8%	इंडोनेशिया (27.4), नीदरलैंड (19.1), यूएसए (15.8), फिलीपींस (11.6), श्रीलंका (7.4)
					चीन	2.9	4.9%	इंडोनेशिया (34.1), यूएसए (22.6), फिलीपींस (18), श्रीलंका (8.3), अन्य एशिया, एनईएस (7.3)
30219	ताजा या ठंडी साल्मोनिड मछलियां	658.4	237.2	6.3%	बेनिन	40.6	36.1%	मॉरिटानिया (44.6), मोरक्को (26.1), नीदरलैंड (7.3), दक्षिण अफ्रीका (4.5), नामीबिया (3.5)
					इटली	15.4	13.7%	स्पेन (43.9), फ्रांस (19.8), स्वीडन (19.2), नीदरलैंड (5.1), डेनमार्क (5)
					फ्रांस	10.4	9.2%	यूके (47.7), नॉर्वे (30.9), आयरलैंड (9.5), नीदरलैंड (5), जर्मनी (2)
					यूनान	7.1	6.3%	चेकिया (42.5), स्पेन (26.9), डेनमार्क (14.2), इटली (8.1), फ्रांस (2)
					कुवैत	6.9	6.1%	नॉर्वे (95.1), डेनमार्क (1.7), यूएई (0.6), यूके (0.6), तुर्की (0.5)
30272	ताजा या ठंडी कैटफिश ''पंगेसियस एसपीपी।, सिलुरस एसपीपी., क्लारियस एसपीपी., इक्टालुरस एसपीपी.''	171.6	12.2	33.6%	डेनमार्क	1.5	35.7%	स्वीडन (85.7), एस्टोनिया (10.7), जर्मनी (1.6), ऑस्ट्रिया (0.8), पुर्तगाल (0.4)
					आयरलैंड	0.4	10.6%	जर्मनी (97.5), यूके (2.5)
					नीदरलैंड	0.4	8.7%	डेनमार्क (47.9), बेल्जियम (33.5), जर्मनी (7.2), अन्य यूरोप, एनईएस (2.3), फ्रांस (2)
					फ्रांस	0.4	8.5%	आइसलैंड (72.5), नीदरलैंड (11.3), वियतनाम (4.4), डेनमार्क (3.3), बेल्जियम (3.3)
					ऑस्ट्रिया	0.2	5.4%	जर्मनी (62.7), स्वीडन (17.4), नीदरलैंड (11.8), चेकिया (1.8), फ्रांस (1.5)
					इटली	193.5	18.4%	स्पेन (27.1), फ्रांस (11.7), स्वीडन (11), ग्रीस (9.9), नीदरलैंड (8.9)

30289	ताजा या ठंडी मछली, एनईएस	180.6	1914.2	0.6%	**हांगकांग**	184.0	17.5%	चीन (60.8), जापान (18.6), अन्य एशिया, एनईएस (7.4), इंडोनेशिया (3.3), फिलीपींस (2.2)
					मलेशिया	95.3	9.0%	इंडोनेशिया (59.7), थाईलैंड (38.4), वियतनाम (0.6), जापान (0.6), म्यांमार (0.4)
					फ्रांस	93.6	8.9%	यूके (23.7), आइसलैंड (12.1), नीदरलैंड (10.4), स्पेन (9), सेनेगल (8.4)
					नीदरलैंड	71.5	6.8%	बेल्जियम (25), जर्मनी (20.9), डेनमार्क (11.7), फ्रांस (8.4), ब्रिटेन (8.4)
30569	मछली, नमकीन या केवल नमकीन में	322.0	201.8	4.4%	ब्राजील	89.7	70.8%	नॉर्वे (54), चीन (43.5), पुर्तगाल (2.5)
					कनाडा	8.9	7.0%	नॉर्वे (37.9), फेरो आइड्स (27.7), चीन (16.8), आइसलैंड (7.1), चिली (4.1)
					जर्मनी	4.7	3.7%	आइसलैंड (52.1), नॉर्वे (31), लातविया (7.4), स्पेन (2.9), नीदरलैंड (2.9)
					फ्रांस	2.6	2.1%	नामीबिया (39.1), नीदरलैंड (20.8), नॉर्वे (8.6), फेरो आइड्स (8.2), स्पेन (7)
					इटली	2.5	1.9%	स्पेन (28.2), नीदरलैंड (22.4), क्रोएशिया (11.8), स्वीडन (9.8), मोरक्को (9.7)
30614	जमे हुए केकड़ों, यहां तक कि स्मोक्ड, चाहे शेल में या नहीं, शेल में केकड़ों सहित, भाप से पकाए गए	319.8	2673.9	1.7%	**जापान**	500.9	38.3%	रूस (52), कनाडा (28.9), यूएसए (10), नॉर्वे (3.8), चीन (1.1)
					चीन	277.4	21.2%	कनाडा (50.8), चिली (15), यूएसए (12.6), रूस (6.3), उत्तर कोरिया (6.1)
					दक्षिण कोरिया	132.1	10.1%	चीन (42.6), रूस (28), बहरीन (9.3), पाकिस्तान (4.8), नामीबिया (3.5)
					हांगकांग	96.9	7.4%	चीन (64.7), कनाडा (8.2), दक्षिण कोरिया (5.2), जापान (4.8), म्यांमार (3.3)
					इंडोनेशिया	54.4	4.2%	कनाडा (52.7), यूएसए (16.7), रूस (6.5), नॉर्वे (6.3), चीन (5.1)

30617	जमे हुए झींगे और प्रॉन, यहां तक कि स्मोक्ड, चाहे वे शेल में हों या नहीं	9937.4	15498.7	0.2%	**जापान**	1679.2	23.4%	वियतनाम (25.7), भारत (20.3), इंडोनेशिया (16.8), अर्जेंटीना (10.8), थाईलैंड (7.6)
					फ्रांस	812.1	11.3%	इक्वाडोर (28.3), भारत (11.9), मेडागास्कर (11.6), वियतनाम (6.8), वेनेजुएला (6.4)
					नीदरलैंड	697.0	9.7%	भारत (25.3), बांग्लादेश (21.3), वियतनाम (15.8), बेल्जियम (12.3), नाइजीरिया (5.1)
					इटली	491.7	6.8%	इक्वाडोर (35.4), अर्जेंटीना (24.9), स्पेन (14.7), भारत (7.1), वियतनाम (3.4)
					चीन	473.2	6.6%	अर्जेंटीना (29.2), इक्वाडोर (22.7), भारत (14.6), थाईलैंड (14.6), इंडोनेशिया (3)
40510	मक्खन (निर्जलित मक्खन और घी को छोड़कर)	724.3	7188.8	1.9%	नीदरलैंड	1324.5	22.6%	आयरलैंड (27.5), जर्मनी (24.7), बेल्जियम (17.4), पोलैंड (9.2), फ्रांस (4)
					फ्रांस	961.5	16.4%	नीदरलैंड (27.2), बेल्जियम (22.3), जर्मनी (13.8), आयरलैंड (12.4), फिनलैंड (7.6)
					जर्मनी	683.7	11.7%	नीदरलैंड (47.3), आयरलैंड (25), बेल्जियम (10.2), पोलैंड (4.4), डेनमार्क (3)
					बेल्जियम	526.0	9.0%	नीदरलैंड (43.5), जर्मनी (13.2), आयरलैंड (12.1), फ्रांस (11.8), यूके (8.1)
					चीन	344.1	5.9%	न्यूजीलैंड (80.3), फ्रांस (11.1), ऑस्ट्रेलिया (3.1), बेल्जियम (2.8), नीदरलैंड (0.9)
40590	दूध और निर्जलित मक्खन व घी से प्राप्त वसा और तेल	602.2	2318.4	1.0%	बेल्जियम	240.5	15.3%	आयरलैंड (37.1), यूके (28.8), नीदरलैंड (11.8), जर्मनी (9.6), फ्रांस (5)
					मेक्सिको	200.0	12.8%	न्यूजीलैंड (82.4), नीदरलैंड (6.5), यूएसए (4.3), चिली (2.5), ऑस्ट्रेलिया (2.4)
					इटली	194.9	12.4%	फ्रांस (31.7), बेल्जियम (17), यूके (13.8), स्पेन (13.6), नीदरलैंड (13.2)
					फ्रांस	177.6	11.3%	नीदरलैंड (43.3), बेल्जियम (25.2), न्यूजीलैंड (11.8), जर्मनी (9), स्पेन (5.9)

					चीन	155.2	9.9%	न्यूजीलैंड (90.3), बेल्जियम (4.1), नीदरलैंड (3.1), जर्मनी (1.5), फ्रांस (0.4)
60390	सूखे, रंगे, ब्लीच किए, इंप्रेग्नेंटेड या अन्यथा तैयार किए गए कटे हुए फूल और कलियां	137.9	467.9	1.2%	नीदरलैंड	244.3	55.0%	जर्मनी (25.2), स्पेन (21.5), इटली (14.3), बेल्जियम (13.3), फ्रांस (8.2)
					फ्रांस	57.2	12.9%	नीदरलैंड (85.6), इटली (2.9), कोलम्बिया (2.8), स्पेन (2.5), बेल्जियम (2.4)
					डेनमार्क	23.7	5.3%	नीदरलैंड (88.3), जर्मनी (6.3), बेल्जियम (1.9), इटली (1.4), पोलैंड (0.6)
					बेल्जियम	19.3	4.3%	नीदरलैंड (92.6), इटली (2.4), जर्मनी (1.8), फ्रांस (1.1), भारत (0.9)
					जापान	15.2	3.4%	कोलम्बिया (32.4), इक्वाडोर (26.8), चीन (21.8), थाईलैंड (6.7), यूएसए (5.6)
70999	ताजा या ठंडी सब्जियां एनईएस	864.7	2715.5	0.7%	नीदरलैंड	318.6	20.2%	बेल्जियम (25.4), स्पेन (24.9), इटली (15.5), जर्मनी (12), फ्रांस (5.1)
					जर्मनी	293.7	18.6%	नीदरलैंड (31.9), इटली (31.8), स्पेन (15.5), फ्रांस (10.8), बेल्जियम (1.7)
					फ्रांस	203.6	12.9%	स्पेन (35.8), इटली (23), नीदरलैंड (7.6), बेल्जियम (7), होंडुरास (3.2)
					कनाडा	151.2	9.6%	यूएसए (72.9), मेक्सिको (13.5), होंडुरास (3.1), निकारागुआ (3), भारत (1.9)
					बेल्जियम	95.2	6.0%	नीदरलैंड (35.1), फ्रांस (26.4), स्पेन (10.3), जर्मनी (9.8), इटली (6.1)
71220	सूखे प्याज, पूरे, कटे हुए, टूटे या पाउडर के रूप में, लेकिन और आगे तैयार नहीं	112.4	385.8	0.1%	जर्मनी	55.3	20.0%	भारत (27.9), चीन (16.7), फ्रांस (11.5), मिस्र (10.5), संयुक्त राज्य अमेरिका (10.2)
					नीदरलैंड	34.9	12.6%	बेल्जियम (32), मिस्र (25.6), भारत (12.8), स्पेन (7.2), फ्रांस (6.9)
					जापान	28.0	10.1%	यूएसए (53), चीन (22.7), मिस्र (15.8), फ्रांस (3.1), बुल्गारिया (2)

					कनाडा	16.4	5.9%	यूएसए (76.3), चीन (10), भारत (7.9), जर्मनी (2.2), मिस्र (2)
					बेल्जियम	16.1	5.8%	भारत (34.1), फ्रांस (26), नीदरलैंड (12.6), यूएसए (8.9), स्पेन (6.5)
80112	आंतरिक खोल ''एंडोकार्प'' में ताजा नारियल	325.1	197.6	8.4%	**चीन**	165.8	86.8%	इंडोनेशिया (48.4), थाईलैंड (37.3), वियतनाम (9.2), फिलीपींस (3.5), भारत (1.6)
					नीदरलैंड	6.0	3.1%	थाईलैंड (47.9), कोत दि'वार (34.1) बेल्जियम (3.4), वियतनाम (3.1), घाना (2.7)
					ऑस्ट्रेलिया	3.0	1.6%	थाईलैंड (67.3), समोआ (10.9), वियतनाम (10.9), भारत (4.1), टोंगा (3.2)
					इटली	2.8	1.5%	नीदरलैंड (37), कोत दि'वार (24.2), निकारागुआ (17), फ्रांस (7.9), डोमिनिक गणराज्य (।4.8)
					हांगकांग	2.7	1.4%	थाईलैंड (88.9), चिली (11), चीन (0.2)
80450	ताजे या सूखे अमरूद, और आम	388.6	2862.0	0.2%	नीदरलैंड	459.9	29.9%	ब्राजील (33.6), पेरू (31.5), कोत दि'वार (5.6), फ्रांस (3.3), डोमिनिक गणराज्य (3.1)
					जर्मनी	202.5	13.2%	ब्राज़ील (35.1), पेरू (26), स्पेन (6.8), कोत दि'वार (4.9), इजरायल (4.1)
					चीन	166.8	10.9%	थाईलैंड (90), अन्य एशिया, एनईएस (3.9), ऑस्ट्रेलिया (2.9), पेरू (2.2), फिलीपींस (0.5)
					फ्रांस	132.9	8.7%	पेरू (23.1), स्पेन (15.4), इजरायल (12.5), ब्राजील (11.2), कोत दि'वार (8.8)
					कनाडा	106.3	6.9%	मेक्सिको (50.9), फिलीपींस (12), ब्राजील (7.7), थाईलैंड (7.2), पेरू (7)
					जर्मनी	229.2	24.6%	स्पेन (66), इटली (18.3), कोस्टा रिका (3.6), तुर्की (3.5), ब्राजील (3)
					नीदरलैंड	197.0	21.2%	कोस्टा रिका (26.4), ब्राजील (21), स्पेन (18.5), पनामा (11.8), मोरक्को (9.7)

80711	ताजा तरबूज	171.7	1671.3	1.9%	फ्रांस	117.9	12.7%	स्पेन (57.5), मोरक्को (32.1), इटली (4.8), नीदरलैंड (1), ट्यूनीशिया (0.9)
					कनाडा	115.0	12.4%	यूएसए (63.2), मेक्सिको (29.9), ग्वाटेमाला (4.3), होंडुरास (2), कोस्टा रिका (0.3)
					चीन	31.9	3.4%	वियतनाम (99), म्यांमार (1)
81090	ताजा इमली, काजू सेब, कटहल, लीची, सपोडिलो प्लम, जोश फल (पैशन फ्रूट), कैरम्बोला	680.5	3184.5	0.6%	**चीन**	887.6	37.0%	वियतनाम (65.8), थाईलैंड (29.8), अन्य एशिया, एनईएस (4.3), इंडोनेशिया (0.1)
					नीदरलैंड	460.9	19.2%	स्पेन (23.4), कोलम्बिया (20.2), पेरू (9.7), बेल्जियम (5.6), दक्षिण अफ्रीका (5.5)
					हांगकांग	170.2	7.1%	थाईलैंड (65), चीन (7.9), वियतनाम (7), अन्य एशिया, एनईएस (5.1), इक्वाडोर (4.2)
					इंडोनेशिया	163.1	6.8%	थाईलैंड (95.4), वियतनाम (2.1), मिस्र (0.7), चीन (0.6), ऑस्ट्रेलिया (0.3)
					जर्मनी	120.5	5.0%	नीदरलैंड (16.8), स्पेन (12.5), तुर्की (11.9), कोलंबिया (11.9), दक्षिण अफ्रीका (9)
91030	हल्दी ''करकुमा''	211.1	264.2	0.1%	ईरान	21.7	14.9%	भारत (86.9), यूएई (10.1), म्यांमार (1.8), पाकिस्तान (0.6), इथियोपिया (0.5)
					नीदरलैंड	17.0	11.7%	भारत (65.3), पेरू (15.5), वियतनाम (6.2), थाईलैंड (3.6), चीन (2.7)
					मोरक्को	12.6	8.7%	भारत (96.2), इथियोपिया (2.7), म्यांमार (0.7), फ्रांस (0.2), स्पेन (0.1)
					जर्मनी	11.5	7.9%	भारत (58.4), नीदरलैंड (8.3), मेडागास्कर (7), पेरू (6.3), थाईलैंड (3.7)
					मलेशिया	10.7	7.4%	भारत (91.7), बांग्लादेश (3.8), म्यांमार (1.8), चीन (1.2), इंडोनेशिया (0.6)
					जर्मनी	54.9	14.4%	पोलैंड (24.2), ऑस्ट्रिया (11.8), नीदरलैंड (11), तुर्की (9.4), इटली (6.5)

91099	मसाले (जीनस पाइपर की काली मिर्च को छोड़कर, जीनस शिमला मिर्च या जीनस पिमेंटा	101.9	759.5	0.1%	नीदरलैंड	46.4	12.1%	बेल्जियम (16.9), स्पेन (16.8), तुर्की (10.5), जर्मनी (9.4), थाईलैंड (7.3)
					बेल्जियम	27.6	7.2%	नीदरलैंड (45.3), फ्रांस (15.2), भारत (6.7), जर्मनी (6.3), तुर्की (4.8)
					फ्रांस	23.8	6.2%	जर्मनी (34.9), इटली (9.6), स्पेन (8.4), तुर्की (5.1), भारत (4.4)
					डेनमार्क	23.3	6.1%	जर्मनी (28.7), स्वीडन (20.7), यूके (20), आयरलैंड (13.4), इटली (5.8)
100640	टुकड़ा चावल	438.7	3346.2	0.1%	बेनिन	604.5	29.1%	भारत (48.9), थाईलैंड (43.1), पाकिस्तान (4.8), यूएई (1.9), सिंगापुर (0.4)
					चीन	326.1	15.7%	थाईलैंड (49.9), वियतनाम (38.6), पाकिस्तान (11.3), कंबोडिया (0.2)
					घाना	297.3	14.3%	वियतनाम (62.8), थाईलैंड (23.6), भारत (9.8), अमेरिका (2.5), पाकिस्तान (0.7)
					इंडोनेशिया	132.8	6.4%	थाईलैंड (45.4), पाकिस्तान (26.2), म्यांमार (14.7), भारत (8.6), वियतनाम (5.1)
					कोत दि'वार	116.1	5.6%	थाईलैंड (90.7), वियतनाम (5.3), भारत (2.8), पाकिस्तान (0.5), म्यांमार (0.3)
100810	कूटू	128.3	109.9	19.2%	**जापान**	35.2	38.8%	यूएसए (43.8), चीन (40.2), रूस (11.3), ब्राजील (3.1), कनाडा (1.3)
					नीदरलैंड	10.2	11.3%	लिथुआनिया (41.1), पोलैंड (22.8), जर्मनी (15.1), बेल्जियम (8.8), फिनलैंड (2.7)
					इटली	7.9	8.7%	पोलैंड (55), लिथुआनिया (23.9), फ्रांस (5.1), नीदरलैंड (5), जर्मनी (4.2)
					फ्रांस	6.4	7.0%	लिथुआनिया (31.2), चीन (19.3), पोलैंड (10.5), लातविया (8.2), चेकिया (7.6)
					लिथुआनिया	5.8	6.4%	रूस (79.5), लातविया (18.3), एस्टोनिया (1.6), पोलैंड (0.6)

100829	बाजरा (अनाज की बुवाई को छोड़कर, और बुवाई के लिए बीज)	173.2	146.0	1.2%	**इंडोनेशिया**	13.5	13.5%	यूएसए (91.1), यूक्रेन (3.9), चीन (3.6), कनाडा (1.1), रूस (0.2)
					जर्मनी	12.0	12.0%	यूक्रेन (22.8), ऑस्ट्रिया (16.5), चीन (13.3), फ्रांस (12.8), पोलैंड (10.7)
					ईरान	10.6	10.7%	अजरबैजान (61.8), रूस (26.7), यूएई (10), यूक्रेन (0.8), तुर्की (0.7)
					नीदरलैंड	8.5	8.6%	यूक्रेन (18.4), चीन (16.7), फ्रांस (15.6), भारत (11.7), बेल्जियम (9.8)
					बेल्जियम	8.2	8.2%	फ्रांस (26.9), यूक्रेन (18.5), नीदरलैंड (14.9), भारत (11.6), जर्मनी (9.5)
110290	अनाज का आटा (गेहूं, मेस्लिन और मक्का को छोड़कर)	45.3	494.3	0.3%	नीदरलैंड	60.2	17.9%	बेल्जियम (55.4), जर्मनी (21.2), इटली (10.6), थाईलैंड (2.7), स्पेन (2.6)
					चीन	31.6	9.4%	थाईलैंड (99.7), यूएसए (0.1), जापान (0.1)
					फ्रांस	28.4	8.4%	जर्मनी (25.1), इटली (17.2), बेल्जियम (17.1), नीदरलैंड (12.1), थाईलैंड (7.3)
					बेल्जियम	26.1	7.8%	नीदरलैंड (43), फ्रांस (14.7), इटली (14.7), जर्मनी (11.4), यूके (4.5)
					जर्मनी	23.3	6.9%	नीदरलैंड (32.1), बेल्जियम (30.4), इटली (21.5), डेनमार्क (2.8), ऑस्ट्रिया (2.2)
110319	अनाज और अनाज का भोजन (गेहूं और मक्का को छोड़कर)	75.1	170.4	6.4%	कनाडा	8.0	13.5%	यूएसए (89.4), रूस (2.2), चीन (1.7), पोलैंड (1.3), भारत (1.1)
					जर्मनी	7.8	13.1%	क्रोएशिया (64.9), बेल्जियम (24.5), नीदरलैंड (6.7), ऑस्ट्रिया (1.7), पोलैंड (0.9)
					नीदरलैंड	7.1	11.9%	यूके (52.7), जर्मनी (20.3), बेल्जियम (11.1), फ्रांस (7.3), इटली (3.4)
					अन्य एशिया, एनईएस	5.3	9.0%	लाओ (70.7), चीन (19.5), थाईलैंड (9.3), इटली (0.3), यूक्रेन (0.1)
					बेलारूस	4.3	7.2%	रूस (100)

120110	सोयाबीन का बीज, बुवाई के लिए	197.9	1091.3	6.5%	**मलेशिया**	174.4	70.9%	यूएसए (71.1), कनाडा (21.5), ब्राजील (4.2), उरुग्वे (2.7), चीन (0.3)
					कनाडा	28.6	11.6%	यूएसए (97.2), चिली (1.8), भारत (0.6), अर्जेंटीना (0.2), चीन (0.2)
					इटली	17.9	7.3%	यूएसए (64.9), क्रोएशिया (13.1), ऑस्ट्रिया (4.4), फ्रांस (4.2), सर्बिया (3.9)
					बोलीविया	5.6	2.3%	अर्जेंटीना (99.9), ब्राजील (0.1)
					जर्मनी	3.0	1.2%	ऑस्ट्रिया (79.3), फ्रांस (9.3), यूएसए (4.4), नीदरलैंड (2.1), जापान (1.7)
120770	तरबूज के बीज	41.3	271.8	1.5%	नीदरलैंड	73.5	43.8%	पेरू (33.2), यूएसए (13.5), चिली (12.7), जापान (8.5), चीन (7.1)
					मोरक्को	18.2	10.8%	पेरू (38), फ्रांस (27.8), चीन (12.1), स्पेन (7.2), जॉर्डन (4.2)
					ब्राजील	13.9	8.3%	पेरू (50.4), स्पेन (39), फ्रांस (4.3), चीन (2.4), थाईलैंड (1.7)
					फ्रांस	10.3	6.1%	नीदरलैंड (43.4), स्पेन (27.2), थाईलैंड (7), यूएसए (6.3), चिली (6.1)
					चीन	7.5	4.4%	म्यांमार (32.9), थाईलैंड (27.6), पेरू (17.7), इंडोनेशिया (13.6), दक्षिण कोरिया (4)
130190	लैक; प्राकृतिक मसूड़े, रेजिन, गम-रेजिन, बाल्सम और अन्य प्राकृतिक ओलेओरे-सिंस	107.7	539.9	0.2%	फ्रांस	32.3	16.2%	सोमालिया (33.2), ईरान (9.5), लाओ (8.2), जर्मनी (8.2), माली (8)
					चीन	31.8	16.0%	इंडोनेशिया (50.7), इथियोपिया (11.2), सोमालिया (6.6), मेडागास्कर (6.5), भारत (4.2)
					जर्मनी	27.8	14.0%	ईरान (30), भारत (17.7), थाईलैंड (11.4), सूडान (5.4), इथियोपिया (5.1)
					नीदरलैंड	26.7	13.4%	जर्मनी (54.5), फ्रांस (31.5), पोलैंड (4.1), बेल्जियम (3.1), भारत (1.5)
					इटली	14.8	7.4%	स्पेन (51.9), जर्मनी (13.1), इंडोनेशिया (10.3), नीदरलैंड (6.3), भारत (6.1)

140490	वनस्पति उत्पाद एन.ई.एस.	421.5	966.2	1.4%	**चीन**	92.9	17.6%	मलेशिया (48.2), भारत (21.4), पेरू (11.6), इंडोनेशिया (4.4), मेक्सिको (2.8)
					जापान	91.0	17.2%	चीन (28.6), इंडोनेशिया (28.1), श्रीलंका (15.3), मलेशिया (13.4), थाईलैंड (2.8)
					नीदरलैंड	82.3	15.6%	भारत (34.4), चेकिया (19), जर्मनी (11.5), बेल्जियम (8.9), यूके (5)
					दक्षिण कोरिया	70.1	13.3%	इंडोनेशिया (48.8), भारत (21.7), श्रीलंका (14.6), वियतनाम (6.9), यूएसए (3.6)
					जर्मनी	29.4	5.6%	ऑस्ट्रिया (54.8), भारत (7.1), नीदरलैंड (6), चीन (5.3), फ्रांस (4.9)
151550	तिल का तेल और उसके अंश, चाहे रिफाइंड हों या न हों, लेकिन रासायनिक रूप से मोडिफाइड न हों	96.7	258.7	0.4%	नीदरलैंड	17.1	13.4%	मेक्सिको (42.8), यूएसए (10.8), सिंगापुर (10.1), जर्मनी (5.9), चीन (5.8)
					कनाडा	13.7	10.7%	जापान (41.7), अन्य एशिया, एनईएस (14.9), मेक्सिको (13.7), यूएस (6.5), चीन (5.6)
					ऑस्ट्रेलिया	10.3	8.0%	सिंगापुर (28.6), चीन (23.1), अन्य एशिया, एनईएस (13.3), मलेशिया (8.2), दक्षिण कोरिया (7.9)
					जर्मनी	9.4	7.4%	मेक्सिको (29.8), नीदरलैंड (15.8), फ्रांस (8.8), यूके (6.7), सिंगापुर (6.6)
					हांगकांग	9.3	7.2%	चीन (53.7), जापान (30.5), सिंगापुर (13.5), दक्षिण कोरिया (1.7), फ्रांस (0.3)
170113	फ्लेवर या रंग विहीन कच्ची चीनी, ठोस रूप में	194.5	3025.7	1.2%	ईरान	414.7	61.2%	यूके (30.2), सिंगापुर (26.1), यूएई (21.6), स्विट्ज़रलैंड (16), ब्राजील (6.2)
					केन्या	133.5	19.7%	ब्राजील (51.3), थाईलैंड (17.8), ज़िम्बाब्वे (7.9), मिस्र (7.5), मेडागास्कर (4.4)
					नेपाल	30.5	4.5%	भारत (92.8), पाकिस्तान (5.2), बांग्लादेश (1.2), वियतनाम (0.8)
					बेलारूस	20.1	3.0%	क्यूबा (69.2), ब्राजील (30.8)
					जापान	11.5	1.7%	थाईलैंड (41.4), चीन (41.1), बोलीविया (7.6), फिलीपींस (7.5), ब्राजील (1.8)

190220	मांस या अन्य पदार्थों से स्टफ्ड पास्ता, पका हुआ या अन्यथा तैयार	302.4	1347.5	6.7%	जर्मनी	166.0	17.4%	इटली (29.6), बेल्जियम (16.3), ऑस्ट्रिया (14.5), स्विट्ज़रलैंड (11.1), फ्रांस (8.8)
					फ्रांस	159.0	16.7%	इटली (55.8), बेल्जियम (18.2), थाईलैंड (6.5), जर्मनी (4.8), हंगरी (4.7)
					नीदरलैंड	150.9	15.8%	बेल्जियम (42.8), जर्मनी (19.7), इटली (19.3), यूके (4.7), फ्रांस (3.4)
					कनाडा	75.4	7.9%	यूएसए (90.3), इटली (5.4), चीन (2.3), दक्षिण कोरिया (0.9), बांग्लादेश (0.4)
					बेल्जियम	67.2	7.1%	इटली (25.7), फ्रांस (23.2), नीदरलैंड (23.2), जर्मनी (8.6), वियतनाम (8)
190300	फ्लेक, अनाज, या दालों के रूप में स्टार्च से तैयार किए गए, टैपिओका और विकल्प	13.5	95.8	0.5%	नीदरलैंड	7.9	14.3%	चीन (43.9), यूके (37), थाईलैंड (8.3), वियतनाम (3.5), जर्मनी (1.3)
					हांगकांग	5.8	10.4%	चीन (56), अन्य एशिया, एनईएस (19.2), मलेशिया (9.1), थाईलैंड (8), इंडोनेशिया (7.1)
					चीन	5.1	9.2%	थाईलैंड (93.9), अन्य एशिया, एनईएस (5.4), इंडोनेशिया (0.6)
					फ्रांस	4.8	8.7%	थाईलैंड (58.1), कोत दि'वार (14.4), नीदरलैंड (7.8), स्पेन (5), बेल्जियम (3.3)
					जापान	4.3	7.7%	अन्य एशिया, एनईएस (45.1), थाईलैंड (43), मलेशिया (11.8), भारत (0.1)
200899	फलों और पौधों के अन्य खाद्य भाग, तैयार या संरक्षित	313.7	4362.5	0.8%	नीदरलैंड	418.1	19.3%	भारत (13.9), यूएसए (13.8), कोस्टा रिका (7.8), कनाडा (6.8), जर्मनी (6.2)
					जापान	254.8	11.8%	चीन (50.7), थाईलैंड (15.3), फिलीपींस (7.9), यूएसए (7.5), भारत (4)
					जर्मनी	197.2	9.1%	इटली (11.6), ऑस्ट्रिया (9.7), नीदरलैंड (9.3), चीन (7.8), कोस्टा रिका (7.1)
					कनाडा	195.4	9.0%	यूएसए (44.2), मेक्सिको (13.6), दक्षिण कोरिया (9), चीन (8.3), थाईलैंड (6.2)

					फ्रांस	192.5	8.9%	जर्मनी (17.3), इटली (8.8), चीन (8.5), भारत (7.2), नीदरलैंड (7.1)
252510	क्रूड अभ्रक और अभ्रक शीट या स्प्लिटिंग में रिफ्टेड अभ्रक	423.3	78.0	3.7%	**चीन**	51.4	75.4%	भारत (85.3), मेडागास्कर (11.9), नाइजीरिया (1.4), ब्राजील (0.8), जापान (0.2)
					जापान	8.0	11.8%	भारत (69), चीन (13.1), फिनलैंड (9.3), श्रीलंका (6.9), मेडागास्कर (1.4)
					जर्मनी	3.4	5.0%	भारत (80.7), ब्राजील (16.7), जापान (2.1), नीदरलैंड (0.3), फ्रांस (0.1)
					फ्रांस	1.0	1.5%	ब्राजील (78.1), फिनलैंड (12.9), मेडागास्कर (5), भारत (3), चीन (0.4)
					दक्षिण कोरिया	1.0	1.5%	भारत (86.3), चीन (7.4), श्रीलंका (2.2), जापान (2.1), मेडागास्कर (1.9)
270120	कोयले से निर्मित ब्रिकेट, ओवोइड और इसी तरह के ठोस ईंधन	609.6	457.3	33.9%	नीदरलैंड	697.8	91.3%	जर्मनी (96.3), बेल्जियम (2.9), यूके (0.5), स्पेन (0.1), इटली (0.1)
					जापान	16.0	2.1%	चीन (100)
					आयरलैंड	14.1	1.8%	नीदरलैंड (47.5), यूके (30.7), क्षेत्र, एनईएस (17.7), पोलैंड (2), जर्मनी (2)
					जर्मनी	12.5	1.6%	बेल्जियम (60.9), रूस (28.4), नीदरलैंड (8.2), यूके (1.3), डेनमार्क (0.7)
					बेल्जियम	7.0	0.9%	नीदरलैंड (87.8), यूके (8.9), आयरलैंड (2.1), जर्मनी (1.2)
300339	एंटी-बायोटिक रहित, हार्मोनों या हार्मोनों के रूप में प्रयुक्त स्टेरॉयड युक्त दवाएं	13788.0	937.1	44.0%	डेनमार्क	107.8	21.2%	पोलैंड (57.1), यूके (9.1), चेकिया (6.7), जर्मनी (6.4), यूएसए (2.6)
					आयरलैंड	97.8	19.3%	यूएसए (63.2), कनाडा (32.6), यूके (1.9), बेल्जियम (1.8), इटली (0.2)
					हंगरी	62.4	12.3%	भारत (85.3), ऑस्ट्रेलिया (13.6), इजरायल (0.8), जर्मनी (0.3), यूके (0.1)
					जर्मनी	59.9	11.8%	यूएसए (68.5), इजरायल (17.4), ऑस्ट्रिया (7.7), यूके (2.8), डेनमार्क (2.7)

					नीदरलैंड	25.1	4.9%	बेल्जियम (37.1), जर्मनी (21.4), यूके (10.5), स्पेन (10.2), साइप्रस (5.6)
300432	कॉर्टिको-स्टेरॉइड हार्मोन युक्त दवाएं, उनके व्युत्पन्नी या समगुणी	1169.8	9188.4	3.0%	**चीन**	1320.8	26.6%	ऑस्ट्रेलिया (42), फ्रांस (17.5), स्वीडन (15.7), बेल्जियम (6.1), जर्मनी (5.6)
					जापान	650.8	13.1%	फ्रांस (30.8), यूके (21.2), स्वीडन (20.1), स्पेन (11.4), बेल्जियम (6)
					जर्मनी	471.0	9.5%	इटली (28.8), स्वीडन (26.9), यूके (9.4), आयरलैंड (7.5), फ्रांस (6.1)
					फ्रांस	453.5	9.1%	स्वीडन (45), यूके (15.1), इटली (13.1), जर्मनी (9.9), स्पेन (4.2)
					ऑस्ट्रेलिया	242.8	4.9%	स्पेन (25), फ्रांस (24.7), स्वीडन (12.9), बेल्जियम (12.6), यूके (12.1)
300490	चिकित्स-कीय या रोगनिरोधी प्रयोजनों के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पादों से युक्त दवाएं	28117.0	286740.5	0.3%	जर्मनी	22630.1	14.4%	स्विट्ज़रलैंड (20.6), यूएसए (12.6), नीदरलैंड (10.5), आयरलैंड (8.7), इटली (8.2)
					बेल्जियम	15058.2	9.6%	यूएसए (32.9), इटली (17), फ्रांस (12.3), आयरलैंड (6.9), जर्मनी (6.5)
					नीदरलैंड	14284.9	9.1%	जर्मनी (37.7), यूके (13.5), बेल्जियम (9.1), यूएसए (6.6), फ्रांस (5.3)
					इटली	12441.8	7.9%	बेल्जियम (16.3), यूएसए (15.3), आयरलैंड (13.7), जर्मनी (12.8), फ्रांस (9.7)
					जापान	12235.4	7.8%	यूएसए (18.6), जर्मनी (17), स्विट्ज़रलैंड (10.2), फ्रांस (8.1), यूके (7.9)
320490	ल्यूमिनोफोर के रूप में प्रयुक्त एक प्रकार के सिंथेटिक जैविक उत्पाद, रासायनिक रूप से परिभाषित या अपरिभाषित	74.6	827.9	0.4%	**दक्षिण कोरिया**	383.1	55.5%	यूएसए (53.8), जापान (22.7), जर्मनी (20.6), चीन (2.6), यूके (0.2)
					चीन	143.5	20.8%	जापान (47.1), दक्षिण-कोरिया (21.1), जर्मनी (13), यूएसए (7.3), यूके (6.2)
					नीदरलैंड	38.8	5.6%	स्पेन (36.1), इटली (27.7), बेल्जियम (17.3), जर्मनी (8.2), फ्रांस (3.8)

					इंडोनेशिया	13.4	1.9%	चीन (41.4), जापान (14.2), वियतनाम (13.6), भारत (5.8), दक्षिण कोरिया (5.4)
					जर्मनी	12.1	1.8%	यूएसए (17.7), फ्रांस (14.9), फिनलैंड (13.1), बेल्जियम (7.5), यूके (6.6)
330190	निकाले गए ओलेओरिंस; वसा में गंध तेल, निश्चित तेल, मोम और इस तरह के संकेंद्रण	184.1	835.8	0.0%	नीदरलैंड	73.5	17.9%	जर्मनी (25.8), स्पेन (19.1), भारत (15.5), यूएसए (9.7), ऑस्ट्रिया (6.9)
					जर्मनी	41.8	10.2%	भारत (35.8), ब्राजील (12.6), चीन (8.6), श्रीलंका (7.2), यूएसए (6.2)
					दक्षिण कोरिया	31.8	7.7%	भारत (42.4), चीन (24.9), स्पेन (16), तुर्की (4.4), जर्मनी (3.2)
					फ्रांस	31.7	7.7%	भारत (18.6), आयरलैंड (13.7), जर्मनी (11.2), स्पेन (7.4), मोरक्को (6.6)
					चीन	28.3	6.9%	यूएसए (32.1), भारत (22.2), बुल्गारिया (13.6), फ्रांस (4.7), यूके (3.2)
330741	'अगरबत्ती' और अन्य समरूपी गंधयुक्त बत्तियां	43.3	306.8	0.0%	**मलेशिया**	22.6	16.8%	चीन (46.7), भारत (21.3), वियतनाम (20.3), थाईलैंड (5.3), अन्य एशिया, नाइल (2.3)
					जापान	13.8	10.2%	मलेशिया (39.4), चीन (21), वियतनाम (14.5), अन्य एशिया, एनईएस (8), भारत (5.5)
					नीदरलैंड	10.3	7.6%	भारत (35.5), इटली (22.1), पोलैंड (15.3), चीन (8.7), बेल्जियम (3.9)
					अन्य एशिया, एनईएस	9.6	7.1%	चीन (70.7), वियतनाम (20), इंडोनेशिया (3.6), जर्मनी (2.2), जापान (1.6)
					नेपाल	6.7	5.0%	भारत (55.6), वियतनाम (43.2), चीन (1.2), थाईलैंड (0.1)
					नीदरलैंड	108.6	12.7%	जर्मनी (57.8), बेल्जियम (20), यूके (7.9), फ्रांस (3.7), चीन (1.8)
					फ्रांस	77.8	9.1%	जर्मनी (34.6), इटली (19.2), जापान (10.5), स्पेन (8.2), बेल्जियम (6.4)

380899	खुदरा बिक्री या तैयारी के लिए रखे गए रोडेंटि-साइड्स और अन्य पौधे संरक्षण उत्पाद	2815.2	2240.2	0.6%	इटली	67.3	7.9%	जर्मनी (35.5), स्पेन (19.7), जापान (18.7), बेल्जियम (5.6), यूके (5.2)
					कनाडा	57.1	6.7%	यूएसए (91.8), चीन (2), भारत (1.9), जर्मनी (1.7), यूके (1.3)
					जर्मनी	52.9	6.2%	नीदरलैंड (27.3), यूके (11.3), स्विट्जरलैंड (9.2), फ्रांस (8.8), चीन (8.3)
420221	हैंडबैग, कंधे की बेल्ट के बिना या बेल्ट सहित, और बिना हैंडल वाले हैंडबैग सहित	1908.6	13822.0	0.4%	**हांगकांग**	1930.1	21.5%	फ्रांस (27.5), इटली (27.1), चीन (26.3), स्विट्ज़रलैंड (9.6), चीन, मकाऊ (1.4)
					फ्रांस	1254.9	14.0%	इटली (70.6), चीन (7), क्षेत्र, एन ई एस (5.7), भारत (2.9), स्पेन (2.5)
					चीन	1027.7	11.5%	इटली (49.9), फ्रांस (20.5), वियतनाम (11.1), फिलीपींस (2.8)
					इटली	794.7	8.9%	फ्रांस (35.3), स्विट्ज़रलैंड (17.3), चीन (10.6), नीदरलैंड (7.8), रोमानिया (5.5)
					दक्षिण कोरिया	705.6	7.9%	इटली (59.5), फ्रांस (19.2), चीन (10.6), वियतनाम (5.3), स्पेन (1.4)
420231	वॉलेट, पर्स, की-पाउच, सिगरेट-केस, तंबाकू-पाउच और समरूपी वस्तुएं	4314.8	4643.6	0.9%	**जापान**	724.9	22.4%	इटली (38.8), चीन (20.9), फ्रांस (11.6), वियतनाम (9), स्पेन (7.1)
					हांगकांग	505.2	15.6%	चीन (32.1), फ्रांस (24.5), इटली (23.5), स्विट्ज़रलैंड (11.5), जर्मनी (1.2)
					फ्रांस	367.2	11.4%	इटली (57.9), चीन (10.8), स्पेन (10.4), क्षेत्र, एनईएस (6), भारत (3.3)
					इटली	267.0	8.3%	फ्रांस (25.6), स्विट्ज़रलैंड (20.1), चीन (11), भारत (10.9), नीदरलैंड (7.9)
					जर्मनी	238.9	7.4%	भारत (36.9), इटली (20.2), चीन (17.2), फ्रांस (6.2), थाईलैंड (3.7)
					इटली	10.5	14.6%	फ्रांस (20.9), यूके (16.2), जर्मनी (9.7), नीदरलैंड (7.5), भारत (4.8)

420340	चमड़े या कंपोजिशन लेदर के कपड़े के सामान	113.8	177.7	0.8%	नीदरलैंड	8.3	11.6%	भारत (23.5), बेल्जियम (21.2), जर्मनी (12.3), चीन (6.5), इटली (6.4)
					फ्रांस	6.3	8.8%	इटली (38.2), चीन (14.2), बेल्जियम (11.1), फ्रांस (8.2), भारत (4.9)
					चीन	6.2	8.7%	कनाडा (20.4), हांगकांग (11.2), इटली (9.1), जापान (5.6)
					जर्मनी	5.5	7.7%	इटली (37.2), तुर्की (18.6), चीन (11.8), भारत (7.8), पाकिस्तान (3.9)
440810	लैमिनेटेड वुड, कॉनिफेरस प्लाईवुड को काटकर बनाई गई चादरें	47.7	598.7	1.6%	**जापान**	100.5	31.5%	रूस (91.9), चीन (6.2), इंडोनेशिया (0.9), न्यूज़ीलैंड (0.6), कनाडा (0.3)
					नीदरलैंड	27.9	8.7%	फ्रांस (41.9), बेल्जियम (24.7), स्वीडन (8.2), जर्मनी (7.2), लातविया (4.2)
					मलेशिया	26.4	8.3%	ब्राजील (30.8), चीन (30.4), न्यूज़ीलैंड (13), वियतनाम (7.4), फिनलैंड (5.1)
					जर्मनी	23.7	7.4%	इंडोनेशिया (37.1), रोमानिया (32), स्वीडन (17.8), चीन (3.3), ऑस्ट्रिया (2.8)
					दक्षिण कोरिया	21.8	6.8%	चिली (42.2), ब्राजील (29.8), रूस (11.1), चीन (7.5), वियतनाम (4.3)
530310	जूट और अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर, कच्चा या रेटेड (फ्लैक्स, सुतली और रेमी को छोड़कर)	5168.3	185.0	34.7%	**नेपाल**	44.5	54.0%	भारत (67), बांग्लादेश (33)
					चीन	16.7	20.3%	बांग्लादेश (99.9), मलेशिया (0.1)
					कोत दि'वार	4.4	5.4%	बांग्लादेश (88.2), भारत (4.3), चीन (4.3), तंजानिया का संयुक्त प्रतिनिधि (1.9), केन्या (1)
					जर्मनी	4.1	4.9%	बांग्लादेश (79.9), बेल्जियम (19), चीन (1), फिलीपींस (0.1), भारत (0.1)
					ब्राजील	2.8	3.4%	बांग्लादेश (100)
					चीन	86.2	51.4%	बांग्लादेश (99.9), मिस्र (0.1)

530710	जूट का सिंगल यार्न या 5303 हेडिंग के अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर	49.4	433.2	4.1%	ईरान	40.6	24.2%	बांग्लादेश (99.3), बेल्जियम (0.3), चीन (0.2), भारत (0.2), सिंगापुर (0.1)
					कोत दि'वार	15.1	9.0%	बांग्लादेश (99.2), भारत (0.8)
					कजाकि-स्तान	3.0	1.8%	बांग्लादेश (87.7), तुर्की (12.3)
					बेल्जियम	3.0	1.8%	बांग्लादेश (96.2), यूके (2.2), भारत (0.9), नीदरलैंड (0.7)
531010	जूट के बुने हुए फैब्रिक या 5303 हेडिंग के अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर, अनब्लीच्ड	1194.7	196.2	1.3%	नीदरलैंड	21.7	25.5%	भारत (62.6), बांग्लादेश (28.4), जर्मनी (3), बेल्जियम (2), चीन (0.9)
					ईरान	11.6	13.6%	बांग्लादेश (65.2), पाकिस्तान (18.3), यूएई (8.3), भारत (8.2), चीन (0.1)
					जर्मनी	9.3	10.9%	भारत (81.3), बांग्लादेश (10.3), नीदरलैंड (6.3), बेल्जियम (1.2), चीन (0.6)
					कनाडा	4.9	5.8%	भारत (73.7), बांग्लादेश (13.1), यूएसए (7.2), चीन (3.2), इंडोनेशिया (1.7)
					जापान	4.8	5.6%	भारत (52.2), बांग्लादेश (47.3), चीन (0.5), वियतनाम (0.1)
540771	वजन में, मोनोफिला-मेंट सहित > = 85% सिंथेटिक फिलामेंट वजन वाले धागे के बुने हुए कपड़े	194.1	204.1	0.5%	**इंडोनेशिया**	20.2	17.0%	चीन (81.4), दक्षिण कोरिया (14.9), जापान (2.3), हांगकांग (0.7), अन्य एशिया, एनईएस (0.4)
					मोरक्को	18.7	15.8%	स्पेन (77.8), इटली (13.7), चीन (4.7), जर्मनी (2), अर्जेंटीना (1.6)
					मलेशिया	14.7	12.4%	इंडोनेशिया (52.7), वियतनाम (39.8), दक्षिण कोरिया (2.8), जापान (1.4), चीन (1.1)
					मेक्सिको	11.2	9.5%	स्पेन (39.8), चीन (17.8), इजरायल (13.5), इटली (9.8), नीदरलैंड (6.7)
					चीन	8.4	7.1%	जर्मनी (46.8), अन्य एशिया, एनईएस(22.7), चीन (5.2), दक्षिण कोरिया (4.8), जापान (4.5)
					जर्मनी	13.8	21.6%	चीन (80.1), तुर्की (8.7), इटली (4.8), स्विट्ज़रलैंड (2.7), स्पेन (1.2)

540794	धागे के बुने हुए कपड़े जिनमें मुख्य रूप से, लेकिन < 85% सिंथेटिक फिलामेंट का वजन होता है	47.3	129.8	0.2%	**म्यांमार**	6.3	9.9%	चीन (91.1), इंडोनेशिया (3.4), अन्य एशिया, एनईएस(2.3), जापान (1.2), दक्षिण कोरिया (1.2)
					इटली	6.2	9.8%	चीन (53.1), जर्मनी (11.8), अन्य एशिया, एनईएस (7.9), स्विट्ज़रलैंड (4.9), जापान (4.8)
					मलेशिया	4.9	7.6%	चीन (91.4), भारत (2.8), हांगकांग (1.8), यूके (1), अन्य एशिया, एनईएस (0.6)
					किर्गिज़स्तान	3.4	5.4%	चीन (99.7), पोलैंड (0.2), तुर्की (0.1)
540810	> = 67 डेसीटेक्स के मोनोफिला-मेंट सहित हाई टीनेसिटी के विस्कोस धागे के बुने हुए कपड़े	3.4	191.9	0.1%	**इंडोनेशिया**	53.6	55.2%	चीन (64.6), हांगकांग (13.5), दक्षिण कोरिया (11.9), स्पेन (3.6), यूके (2.9)
					इटली	7.8	8.0%	चीन (26), पोलैंड (22.4), मोरक्को (16.5), हंगरी (16.5), जर्मनी (6.4)
					अल्जीरिया	7.2	7.4%	चीन (83.9), तुर्की (7.3), मोरक्को (6), भारत (2.2), मिस्र (0.3)
					श्रीलंका	5.7	5.9%	चीन (68.5), भारत (17.8), हांगकांग (7.5), इंडोनेशिया (4.4), अन्य एशिया, एनईएस (0.8)
					डोमिनिक गणराज्य	5.4	5.6%	चीन (82.3), भारत (7.4), यूएसए (3.6), स्पेन (3.5), अन्य एशिया, एनईएस (1.2)
550820	कृत्रिम स्टेपल फाइबर का सिलाई धागा, खुदरा बिक्री के लिए या अन्यथा	5.9	35.1	8.4%	श्रीलंका	1.5	14.6%	हांगकांग (53), चीन (31.5), यूके (4.3), जर्मनी (4.2), दक्षिण कोरिया (2.4)
					ईरान	1.5	14.4%	चीन (91.6), फ्रांस (6), यूएई (1.2), ओमान (1.2), तुर्की (0.1)
					चीन	1.3	12.6%	जापान (12.6), हांगकांग (6.9), अन्य एशिया, एनईएस(0.9), दक्षिण कोरिया (0.7)
					इंडोनेशिया	1.1	10.8%	दक्षिण कोरिया (65.2), चीन (26.4), जापान (7.5), हांगकांग (0.3), सिंगापुर (0.3)
					नेपाल	0.6	5.6%	भारत (91.5), चीन (7.5), थाईलैंड (1)

551130	कृत्रिम स्टेपल फाइबर का धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया (सिलाई धागे को छोड़कर)	9.8	20.0	0.3%	डेनमार्क	1.9	16.9%	स्वीडन (42), स्पेन (23.9), नॉर्वे (17.7), ऑस्ट्रिया (6.2), चीन (3.7)
					जर्मनी	1.4	12.5%	इटली (62.1), चीन (20.3), तुर्की (12.4), क्रोएशिया (2.6), स्विट्जरलैंड (2.1)
					मोरक्को	1.2	11.0%	इटली (58.3), तुर्की (16.9), चीन (8.3), भारत (7.9), बुल्गारिया (4.3)
					इंडोनेशिया	1.0	9.0%	श्रीलंका (30.7), हांगकांग (21.7), चीन (18), जापान (14.3), दक्षिण कोरिया (2.9)
					इटली	0.8	7.3%	बुल्गारिया (49.2), तुर्की (46.9), चीन (1.2), फ्रांस (0.9), जर्मनी (0.5)
551349	वजन में < 85% सिंथेटिक स्टेपल फाइबर वाला बुना हुआ कपड़ा	7.5	159.1	0.1%	श्रीलंका	7.6	19.0%	भारत (27.4), हांगकांग (23.7), सिंगापुर (13.4), पाकिस्तान (8.8), चीन (8.1)
					इंडोनेशिया	4.0	9.9%	चीन (96.7), वियतनाम (0.9), पाकिस्तान (0.7), भारत (0.5), दक्षिण कोरिया (0.3)
					मोरक्को	3.7	9.3%	स्पेन (62.5), चीन (18.7), इटली (8.7), जर्मनी (3.8), तुर्की (3.6)
					मॉरीशस	3.0	7.6%	चीन (86.7), भारत (9.2), थाईलैंड (1.9), पाकिस्तान (1), दक्षिण अफ्रीका (0.5)
					मेक्सिको	1.9	4.8%	यूएसए (31.4), चीन (30.1), भारत (20.5), इजरायल (9.3), पाकिस्तान (3.2)
551449	वजन में < 85% सिंथेटिक स्टेपल फाइबर वाला बुना हुआ कपड़ा	51.0	540.8	2.5%	**म्यांमार**	471.8	93.3%	चीन (85.9), दक्षिण कोरिया (6.4), जापान (1.9), अन्य एशिया, एनईएस (1.5), थाईलैंड (1)
					इंडोनेशिया	7.2	1.4%	चीन (64.4), अन्य एशिया, एनईएस (11.1), थाईलैंड (7), मलेशिया (6.5), दक्षिण कोरिया (5)
					नेपाल	7.1	1.4%	चीन (99.6), बांग्लादेश (0.4)
					मोरक्को	3.7	0.7%	स्पेन (35.7), चीन (34.2), फ्रांस (19.5), मिस्र (7.2), तुर्की (2.9)
					केन्या	1.8	0.4%	चीन (52.9), भारत (46.5), यूगांडा (0.6)

551599	< 85% सिंथेटिक स्टेपल फाइबर युक्त बुने हुए कपड़े	33.5	470.4	0.2%	किर्गिज़स्तान	48.0	24.3%	चीन (99.1), तुर्की (0.6), दक्षिण कोरिया (0.1), इटली (0.1)
					बेल्जियम	31.4	15.9%	फ्रांस (81.8), जर्मनी (11.2), चीन (4.7), यूएसए (1.3), इटली (0.4)
					मोरक्को	14.6	7.4%	फ्रांस (36.8), पुर्तगाल (18.8), स्पेन (13.1), तुर्की (12.2), इटली (10.4)
					इंडोनेशिया	10.6	5.3%	चीन (48.1), अन्य एशिया, एनईएस (23.7), जापान (7.7), हांगकांग (4.2), दक्षिण कोरिया (4)
					जॉर्जिया	9.9	5.0%	तुर्की (45), यूएई (28.3), चीन (24.5), दक्षिण कोरिया (0.6), ईरान (0.6)
551694	< 85% कृत्रिम स्टेपल फाइबर युक्त बुने हुए कपड़े	44.0	106.1	0.5%	मोरक्को	20.8	43.0%	इटली (38.5), स्पेन (22.5), जर्मनी (14.8), चीन (13.1), तुर्की (9.8)
					नेपाल	5.3	10.9%	चीन (100)
					किर्गिज़स्तान	3.7	7.7%	चीन (99.8), अन्य एशिया, एनईएस (0.2)
					इंडोनेशिया	3.0	6.1%	अन्य एशिया, एनईएस (44.5), हांगकांग (43.4), चीन (11.7), दक्षिण कोरिया (0.4)
					फ्रांस	2.1	4.4%	जापान (33.1), इटली (26.9), चीन (7.6), दक्षिण कोरिया (6.5), तुर्की (5.2)
560790	सुतली, जहाजी रस्से, रस्सियां और केबल, प्लेटेड या ब्रांडेड या अन्य और इंप्रेग्नेंटेड या अन्य	41.3	321.8	0.1%	नीदरलैंड	15.1	9.2%	जर्मनी (28.4), बेल्जियम (21.6), चीन (15.9), भारत (6.8), यूएसए (4.2)
					इंडोनेशिया	13.8	8.4%	चीन (31.1), जापान (17.7), थाईलैंड (14.9), सिंगापुर (10), वियतनाम (8.6)
					फ्रांस	12.0	7.3%	ट्यूनीशिया (40), स्पेन (12.2), चीन (12.1), रोमानिया (5.8), पुर्तगाल (5.6)
					कनाडा	9.5	5.8%	भारत (28.5), चीन (20.1), पुर्तगाल (15.2), अमेरिका (15), फिलीपींस (8.7)
					मेक्सिको	8.7	5.3%	यूएसए (41.8), बांग्लादेश (17.7), दक्षिण कोरिया (14.4), कनाडा (9.4), चीन (8.3)

580410	रेशमी पतली जाली और कपड़े की अन्य जालियां (बुनी हुई, या क्रोशिया की हुई)	75.7	622.8	0.6%	**चीन**	61.1	20.1%	अन्य एशिया, एनईएस (34.6), दक्षिण कोरिया (32.5), जापान (15.3), चीन (6.8), इटली (2.3)
					हांगकांग	46.2	15.2%	चीन (51.7), दक्षिण कोरिया (21.8) अन्य एशिया, एनईएस (14.9), स्विट्ज़रलैंड (1.6), यूएसए (1.2)
					इंडोनेशिया	31.1	10.2%	हांगकांग (40.6), चीन (20.5), अन्य एशिया, एनईएस (14.9), दक्षिण कोरिया (12.3), यूएसए (7.2)
					श्रीलंका	30.6	10.1%	अन्य एशिया, एनईएस (35.3), चीन (12.5), इंडोनेशिया (11.8), जापान (6.8), भारत (6.4)
					म्यांमार	16.5	5.4%	चीन (80.4), वियतनाम (6.9), दक्षिण कोरिया (5), हांगकांग (3.3), जापान (1.4)
580429	टुकड़े, स्ट्रिप या मोटिफ में यांत्रिक रूप से बनाए गए फीते	54.8	321.7	1.1%	श्रीलंका	68.7	46.0%	चीन (53), हांगकांग (26.5), थाईलैंड (7.3), यूएसए (4.5), दक्षिण कोरिया (3.9)
					इंडोनेशिया	14.5	9.7%	चीन (43.8), दक्षिण कोरिया (28), हांगकांग (14), थाईलैंड (5.7), अन्य एशिया, एनईएस (3.6)
					इटली	12.1	8.1%	फ्रांस (57.1), चीन (27.9), तुर्की (2.6), यूके (2.6), जर्मनी (2.1)
					हांगकांग	5.3	3.6%	चीन (68.7), फ्रांस (8.8), दक्षिण कोरिया (6.2), जापान (4.1), इटली (4)
					बुल्गारिया	5.2	3.5ड़	फ्रांस (87.5), ग्रीस (3.1), इटली (3), चीन (2.5), जर्मनी (2)
581010	टेक्सटाइल फैब्रिक पर विजिबल ग्राउंड के बिना पीस, स्ट्रिप में की गई कढ़ाई	57.4	130.5	0.1%	इटली	31.6	38.2%	भारत (75), चीन (9.1), स्विट्ज़रलैंड (5.3), अल्बानिया (1.9), थाईलैंड (1.8)
					हांगकांग	10.5	12.7%	चीन (56.4), अन्य एशिया, एनईएस (26.8), ऑस्ट्रिया (5.2), थाईलैंड (3.6), भारत (3.4)
					फ्रांस	8.5	10.3%	भारत (36.4), जर्मनी (13.4), स्विट्ज़रलैंड (13.4), इटली (13.3), थाईलैंड (6.3)
					मोरक्को	4.7	5.7%	स्पेन (76.1), चीन (6.8), इटली (6.3), फ्रांस (4.7), भारत (2.6)

					जर्मनी	3.3	4.0%	रोमानिया (31.2), स्विट्ज़रलैंड (16.7), ग्रीस (13.3), ऑस्ट्रिया (11.4), चीन (6.8)
600390	< = 30 सेमी की चौड़ाई का बुना हुआ या क्रोशिया किया हुआ फैब्रिक	18.4	60.9	5.1%	**इंडोनेशिया**	3.4	38.9%	चीन (44.4), सिंगापुर (25.7), जापान (12.5), दक्षिण - कोरिया (9.7), हांगकांग (4.8)
					नेपाल	2.0	23.6%	भारत (97.8), चीन (2.2)
					डोमिनिक-गणराज्य	0.8	9.3%	एनईएस (74.3), चीन (25.7)
					जर्मनी	0.5	5.3%	अन्य एशिया, एनईएस (45.9), चीन (27.6), श्रीलंका (6.4), इटली (5.7), पुर्तगाल (5.1)
					ब्रुनेई दारुस्सलाम	0.3	3.8%	चीन (65.9), हांगकांग (33.5), भारत (0.4), मलेशिया (0.2)
610,290	स्की जैकेट, विंडचिटर सहित महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कार कोट, कैप, लहंगे, टोपीदार बरसाती कोट आदि	218.6	101.9	10.5%	जर्मनी	11.1	19.7%	इटली (30.9), ऑस्ट्रिया (16.6), फ्रांस (11.9), चीन (8.6), नीदरलैंड (8.2)
					ऑस्ट्रिया	5.4	9.6%	जर्मनी (72.1), चीन (7.7), इटली (4.1), रोमानिया (2.7), बुल्गारिया (1.6)
					इटली	4.9	8.8%	बुल्गारिया (45.3), फ्रांस (21.9), जर्मनी (5.8), चीन (5.7), रोमानिया (3.6)
					फ्रांस	4.3	7.6%	इटली (26.4), चीन (12.7), पुर्तगाल (8.3), यूके (7.2), पाकिस्तान (4.9)
					डेनमार्क	2.5	4.4%	नीदरलैंड (27.4), स्वीडन (19.6), इटली (18.1), बुल्गारिया (10.2), चीन (7.7)
610719	पुरुषों या लड़कों के अंतर्वस्त्र और बुनी हुई, क्रोशिया की हुई अन्य टेक्सटाइल सामग्री	130.4	168.6	0.2%	**मलेशिया**	6.7	13.4%	चीन (89.2), हांगकांग (3.3), इटली (2.4), श्रीलंका (1), बांग्लादेश (0.9)
					आयरलैंड	5.1	10.3%	यूके (98.1), भारत (0.8), चीन (0.6), बांग्लादेश (0.5)
					जर्मनी	4.4	8.8%	चीन (32.3), वियतनाम (21.7), स्वीडन (15.9), नीदरलैंड (4.9), डेनमार्क (4)
					डेनमार्क	2.9	5.9%	इटली (31.2), चीन (29.4), लिथुआनिया (18.4), नीदरलैंड (4.9), जर्मनी (4.5)

					फ्रांस	2.5	5.0%	चीन (31.3), इटली (22.4), पोलैंड (10.3), ट्यूनीशिया (6.1), वियतनाम (4.9)
610729	पुरुषों या लड़कों की नाइटशर्ट या पायजामा और बुनी हुई, क्रोशिया की हुई टेक्सटाइल सामग्री	10.5	21.4	0.0%	इटली	1.0	10.6%	रोमानिया (25), बांग्लादेश (18), अल्बानिया (16.6), पाकिस्तान (14.8), क्रोएशिया (5.8)
					मलेशिया	0.9	9.4%	चीन (96), हांगकांग (2.1), ऑस्ट्रेलिया (1.7), यूएसए (0.2), थाईलैंड (0.1)
					कनाडा	0.8	8.6%	यूएसए (66.8), चीन (11.8), जर्मनी (4), फ्रांस (3.5), जापान (3.3)
					कुवैत	0.6	6.7%	चीन (44.8), भारत (42.4), पुर्तगाल (8.3), तुर्की (2.3), बांग्लादेश (1.1)
					जॉर्डन	0.6	6.3%	तुर्की (94.8), चीन (5.2)
610799	पुरुषों या लड़कों के स्नान वस्त्र, ड्रेसिंग गाउन और बुनी हुई टेक्सटाइल सामग्री	35.8	234.6	1.3%	**दक्षिण कोरिया**	13.7	22.1%	चीन (45.1), वियतनाम (30.8), इंडोनेशिया (9.6), कंबोडिया (7.9), म्यांमार (4)
					ऑस्ट्रेलिया	5.9	9.5%	चीन (92), बांग्लादेश (3.9), थाईलैंड (1.2), ऑस्ट्रेलिया (0.7), अल साल्वाडोर (0.4)
					कनाडा	5.4	8.7%	चीन (78.3), कंबोडिया (9.4), अल साल्वाडोर (2.7), वियतनाम (2.2), बांग्लादेश (2.1)
					जर्मनी	4.8	7.6%	चीन (62.9), पोलैंड (9.9), तुर्की (9.6), बांग्लादेश (8.6), कंबोडिया (2.1)
					फ्रांस	4.3	6.9%	चीन (61.9), बेल्जियम (6.8), ट्यूनीशिया (6.3), स्पेन (2.3), कंबोडिया (2.2)
620469	महिलाओं या लड़कियों के ट्राउजर, बिब और ब्रेस और ब्रीच और शॉर्ट्स व टेक्सटाइल सामग्री	404.1	3207.8	0.4%	जर्मनी	258.5	16.6%	चीन (24.3), बांग्लादेश (16.9), तुर्की (8.7), भारत (6.3), कंबोडिया (5.5)
					जापान	241.6	15.5%	चीन (58.4), कंबोडिया (14.2), वियतनाम (10.2), इंडोनेशिया (5.3), म्यांमार (2.8)
					फ्रांस	184.0	11.8%	चीन (25.8), एनईएस (13.7), इटली (10), बांग्लादेश (8.5), मोरक्को (5.9)
					कनाडा	94.9	6.1%	चीन (35.8), कंबोडिया (21.1), बांग्लादेश (14.4), यूएसए (6.6), वियतनाम (4.1)

					इटली	78.8	5.1%	चीन (11.9), रोमानिया (11), फ्रांस (8.5), बुल्गारिया (7.1), बांग्लादेश (6.6)
620990	शिशुओं के वस्त्र और वस्त्र एसेसरीज और टेक्सटाइल सामग्री	47.5	305.9	0.1%	फ्रांस	11.1	11.9%	चीन (34.8), साइप्रस (8.5), बांग्लादेश (6.9), इटली (5.6), ट्यूनीशिया (5.4)
					लेबनान	8.0	8.5%	चीन (39.9), जर्मनी (38.5), हांगकांग (9.2), यूएसए (2.5), तुर्की (1.5)
					आर्मेनिया	6.4	6.9%	तुर्की (87.2), चीन (11.2), यूएई (0.9), रूस (0.4), ईरान (0.1)
					इटली	6.1	6.5%	फ्रांस (12.7), चीन (12.7), पोलैंड (12.7), स्पेन (8.9), बांग्लादेश (6.7)
					जर्मनी	5.1	5.4%	चीन (46.5), बांग्लादेश (21.6), भारत (4.7), इटली (3.9), नीदरलैंड (2.9)
621420	शॉल, स्कार्फ, मफलर, दुपट्टे, बुर्के और ऊन के समरूपी सामान	183.1	948.9	0.3%	**जापान**	146.1	22.5%	चीन (37.5), इटली (30.3), यूके (20.8), फ्रांस (4.2), भारत (3.2)
					फ्रांस	104.4	16.1%	इटली (58.6), ब्रिटेन (15.5), चीन (8.4), भारत (5.6), नेपाल (3.3)
					हांगकांग	77.3	11.9%	फ्रांस (41.5), इटली (22.5), यूके (12.8), स्विट्ज़रलैंड (7.2), चीन (6.4)
					चीन	73.2	11.2%	इटली (56.9), यूके (23.8), फ्रांस (12), भारत (3.7),
					इटली	58.3	9.0%	स्विट्ज़रलैंड (23.9), फ्रांस (22.5), यूके (18.8), ट्यूनीशिया (9.2), चीन (8)
640690	जूते-चप्पलों के पार्ट्स; सोल, हील कुशन और समरूपी सामान; गैटर, लेगिंग	648.3	2740.1	2.5%	जर्मनी	202.6	13.6%	चीन (28.2), पोलैंड (18), स्पेन (8.6), रोमानिया (8), फिलीपींस (6.1)
					चीन	201.7	13.5%	यूएसए (44.3), वियतनाम (21.4), चीन (15), दक्षिण कोरिया (6.5), अन्य एशिया, एनईएस (4.6)
					इटली	183.6	12.3%	अल्बानिया (21.5), रोमानिया (20.4), बुल्गारिया (15.3), चीन (11.2), स्पेन (5.4)

					इंडोनेशिया	121.0	8.1%	चीन (32.4), हांगकांग (25.7), वियतनाम (17.3), यूएसए (12.1), दक्षिण अफ्रीका (4.8)
					हांगकांग	107.5	7.2%	चीन (48.5), यूएसए (23.4), वियतनाम (20.1), दक्षिण कोरिया (2.6), अन्य एशिया, एनईएस (1.6)
741810	टेबल, रसोई या अन्य घरेलू सामान और उसके कुछ हिस्से, और बर्तन और सफाई का सामान	36.5	166.4	0.4%	जर्मनी	12.9	20.0%	पोलैंड (37.5), चेकिया (16.1), डेनमार्क (9.5), भारत (6.5), फ्रांस (4.8)
					कनाडा	4.6	7.1%	चीन (41.8), भारत (28.7), फ्रांस (8.2), यूएसए (7.8), इटली (4.3)
					चेकिया	3.6	5.6%	स्लोवाकिया (51.8), जर्मनी (15.9), पोलैंड (7.9), इटली (6.7), फ्रांस (5)
					फ्रांस	3.3	5.1%	इटली (17.8), फ्रांस (16.5), जर्मनी (14.6), स्पेन (9.3), यूके (8.6)
					नेपाल	2.7	4.2%	भारत (99.6), चीन (0.3), थाईलैंड (0.1)
780110	अनिर्मित लैड, रिफाइंड	532.3	4941.1	0.2%	जर्मनी	259.7	14.0%	बेल्जियम (44.1), नीदरलैंड (15.9), यूके (14.5), फ्रांस (7.1), स्वीडन (7.1)
					चेकिया	217.3	11.7%	जर्मनी (44.9), पोलैंड (30.6), रूस (11.3), यूके (9.5), बेल्जियम (2.3)
					अन्य एशिया, एनईएस	197.9	10.6%	कजाकिस्तान (46.1), भारत (16.3), ऑस्ट्रेलिया (14.3), चीन (10.2), यूएई (4.1)
					चीन	190.0	10.2%	ऑस्ट्रेलिया (50.5), कजाकिस्तान (34.2), फ्रांस (5), दक्षिण कोरिया (4.4), इटली (3)
					दक्षिण कोरिया	171.2	9.2%	भारत (24.2), यूएई (20), ऑस्ट्रेलिया (12.2), फ्रांस (10), ईरान (8.3)
					चीन	2.0	21.5%	फ्रांस (25.8), जापान (19.5), दक्षिण कोरिया (16.1), जर्मनी (15.1)
					जर्मनी	2.0	20.5%	चीन (73.8), अन्य एशिया, एनईएस (20.3), यूएसए (1.5), इजरायल (1), ऑस्ट्रिया (1)

821195	टेबल चाकू, जेब चाकू और 8211 हेडिंग के अन्य चाकुओं के लिए आधार धातु के हैंडल	2.5	20.9	4.0%	**जापान**	1.0	10.9%	चीन (92.5), दक्षिण कोरिया (2.9), वियतनाम (1.9), पाकिस्तान (1.5), अन्य एशिया, एनईएस (0.8)
					इंडोनेशिया	0.6	6.4%	चीन (64.3), सिंगापुर (25.5), अन्य एशिया, एनईएस(1.7), ऑस्ट्रिया (1.6), यूएसए (1.5)
					कनाडा	0.3	3.5%	चीन (43.9), यूएसए (32.8), थाईलैंड (4.3), जर्मनी (3.8), जापान (3.5)
830610	बेस मेटल की घंटियां, घंटे और नॉन-इलेक्ट्रिक समरूपी सामान, संगीत वाद्य यंत्रों को छोड़कर)	41.0	139.7	0.7%	जर्मनी	11.4	21.1%	चीन (67.2), अन्य एशिया, एनईएस (10.1), जापान (5.1), भारत (5), हांगकांग (3)
					जापान	8.3	15.4%	चीन (83.9), अन्य एशिया, एनईएस (6.2), इंडोनेशिया (4.7), दक्षिण कोरिया (1.6), यूएसए (0.8)
					कनाडा	5.6	10.3%	चीन (65.5), यूएसए (18.2), अन्य एशिया, एनईएस (5.2), भारत (3.8), जापान (2.4)
					फ्रांस	3.6	6.7%	चीन (64.9), नीदरलैंड (6.7), जर्मनी (4.9), अन्य एशिया, एनईएस (3.4), यूके (3.1)
					इटली	2.4	4.5%	चीन (46.9), भारत (10.1), नीदरलैंड (6.3), स्पेन (4.3), फ्रांस (4.2)
841320	तरल पदार्थों के लिए हैंड पंप (8413.11 और 8413.19 को छोड़कर)	67.4	895.9	0.7%	कनाडा	57.8	13.9%	चीन (35.7), यूएसए (29.3), अन्य एशिया, एनईएस (9.2), मेक्सिको (8.2), फ्रांस (4.8)
					जर्मनी	50.8	12.2%	चीन (28.1), पोलैंड (16.1), नीदरलैंड (8.5), फ्रांस (7.7), इटली (7.1)
					जापान	43.7	10.5%	थाईलैंड (38.3), चीन (35.8), दक्षिण कोरिया (10.2), अन्य एशिया, एनईएस (4), फ्रांस (3.3)
					फ्रांस	25.8	6.2%	स्पेन (26.7), चीन (15.1), यूके (14.3), नीदरलैंड (13), जर्मनी (8.5)
					म्यांमार	22.0	5.3%	चीन (81), जर्मनी (4.5), जापान (3.2), थाईलैंड (3.1), इटली (1.9)

841451	सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर वाले टेबल, फर्श, दीवार, खिड़की, या छत के पंखे	632.0	4420.1	1.1%	**जापान**	235.5	12.5%	चीन (82), थाईलैंड (6.3), मलेशिया (5.4), अन्य एशिया, एनईएस (2.9), वियतनाम (1.8)
					दक्षिण कोरिया	226.9	12.1%	चीन (81.5), मलेशिया (11.7), जापान (2.1), यूएसए (2), अन्य एशिया, एनईएस (1.2)
					चीन	149.6	8.0%	मलेशिया (18.8), जर्मनी (15.4), हंगरी (8.9), फिलीपींस (8.5)
					ऑस्ट्रेलिया	121.3	6.5%	चीन (76), मलेशिया (10.3), अन्य एशिया, एनईएस (4.9), स्पेन (2.9), कनाडा (1.3)
					कनाडा	113.2	6.0%	चीन (81.9), यूएसए (8.9), मलेशिया (5.4), मेक्सिको (1.5), इटली (0.5)
845290	सिलाई मशीनों और उनके कवरों के लिए फर्नीचर बेस, कुर्सियां और कवर; सिलाई मशीनों के अन्य पुर्जे	100.4	928.7	1.1%	**चीन**	77.0	16.0%	जापान (56.6), अन्य एशिया, एनईएस (28.3), वियतनाम (8.4), जर्मनी (1.5)
					जापान	74.4	15.4%	चीन (48.6), वियतनाम (28.7), अन्य एशिया, एनईएस (20.3), दक्षिण कोरिया (0.6), यूएसए (0.4)
					मलेशिया	53.8	11.2%	चीन (45.5), जापान (30.6), भारत (8.9), अन्य एशिया, एनईएस (3.9), नीदरलैंड (3.5)
					अन्य एशिया, एनईएस	48.0	10.0%	चीन (77.5), जापान (14), थाईलैंड (5.1), वियतनाम (1.2), क्षेत्र, एनईएस (0.9)
					जर्मनी	31.0	6.4%	चेकिया (20.5), रोमानिया (16.4), चीन (14.7), जापान (9.7), अन्य एशिया, एनईएस (8.7)
940159	बेंत की सीटें या समरूपी सामग्री (बांस या रैटेन को छोड़कर)	9.4	97.1	2.6%	इटली	14.8	32.0%	रोमानिया (49.5), बुल्गारिया (26.5), इंडोनेशिया (10.6), जर्मनी (3.8), चीन (2)
					जर्मनी	5.4	11.8%	नीदरलैंड (34.5), पोलैंड (13.6), इंडोनेशिया (13.5), डेनमार्क (13.3), चेकिया (5.1)
					कनाडा	2.9	6.4%	चीन (86.4), वियतनाम (7.8), इंडोनेशिया (2.2), फिलीपींस (2), यूएसए (1.3)
					फ्रांस	2.9	6.3%	चीन (16.8), इंडोनेशिया (14.3), वियतनाम (11.9), इटली (11.9), बेल्जियम (10.6)

					दक्षिण कोरिया	2.0	4.3%	चीन (53.7), वियतनाम (32), इंडोनेशिया (6.3), यूएसए (2.5), फ्रांस (1.7)
960891	पेन निब और निब पॉइंट	17.3	132.6	0.1%	जर्मनी	9.7	18.0%	जापान (76.8), फ्रांस (9.3), यूएसए (4.7), इंडोनेशिया (3.4), चीन (1.6)
					इटली	6.6	12.2%	जापान (43.6), जर्मनी (39.2), चीन (12.1), अन्य एशिया, एनईएस (2.8), चेकिया (1)
					मलेशिया	6.2	11.5%	जापान (61.7), थाईलैंड (12.9), स्विट्ज़रलैंड (7.6), चीन (6), यूएसए (3.2)
					इंडोनेशिया	5.0	9.2%	जापान (64.8), थाईलैंड (18.7), चीन (14.5), भारत (1), अन्य एशिया, एनईएस (0.4)
					केन्या	4.4	8.2%	फ्रांस (74.6), दक्षिण अफ्रीका (14.8), मेक्सिको (5.5), भारत (4.5), स्विट्ज़रलैंड (0.7)

नोट : बिहार के लिए डाटा 2017-18 वर्ष का है। वैश्विक आयातों और निर्यातों का डाटा 2017 के लिए है।

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, यूएन कॉमट्रेड, एक्ज़िम बैंक शोध अध्ययन

एक्ज़िम बैंक के कार्यकारी आलेखों की श्रृंखला

भारतीय निर्यातकों के ज्ञान वर्द्धन और उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता को विकसित करने के प्रयास में एक्ज़िम बैंक समय-समय पर शोध अध्ययन कराता रहता है। इन शोध अध्ययनों को प्रमुख रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है- क्षेत्र (सेक्टर) अध्ययन, देश अध्ययन और समष्टि आर्थिक (मैक्रो-इकॉनमिक)संबंधी विश्लेषण। ये शोध अध्ययन प्रासंगिक आलेखों, कार्यकारी आलेखों और पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। कार्यकारी आलेखों के नाम से प्रकाशित किए जाने वाले इन शोध अध्ययनों के लिए गहन विश्लेषण कर विभिन्न स्रोतों से आंकड़े जुटाए जाते हैं। इन शोध अध्ययनों में व्यापार और निवेश संबंधी विभिन्न विषयों पर विश्लेषणात्मक अध्ययन मिलता है।

एक्ज़िम बैंक के पिछले कार्यकारी आलेख

कार्यकारी आलेख संख्या 61	प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अंतरराष्ट्रीय व्यापारः भारतीय परिप्रेक्ष्य, मार्च 2017
कार्यकारी आलेख संख्या 62	भारत में मशीनरी सेक्टरः व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में विकल्पों की तलाश, मार्च 2017
कार्यकारी आलेख संख्या 63	पोषित अफ्रीकाः भागीदारी के जरिए प्रगति, मई 2017
कार्यकारी आलेख संख्या 64	अफ्रीका में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं : सुविधाओं को बढ़ावा, विकास को गति, मई 2017
कार्यकारी आलेख संख्या 65	एकीकृत अफ्रीकाः बहुआयामी परिप्रेक्ष्य, मई 2017
कार्यकारी आलेख संख्या 66	अफ्रीका में विनिर्माणः सतत विकास के लिए रोडमैप, मई 2017
कार्यकारी आलेख संख्या 67	अफ्रीका में विद्युत क्षेत्रः संभावना और क्षमता, मई 2017
कार्यकारी आलेख संख्या 68	पूर्वी अफ्रीका में भारतीय निवेशः वर्तमान प्रवृत्तियां और संभावनाएं, नवंबर 2017
कार्यकारी आलेख संख्या 69	पर्यावरण संबंधी वस्तुओं का व्यापारः एक परिप्रेक्ष्य, दिसंबर 2017
कार्यकारी आलेख संख्या 70	तेल की कीमतें और कच्चे पेट्रोलियम एवं उत्पादों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, भारतीय परिप्रेक्ष्य, जनवरी 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 71	विकास बैंकों और निर्यात ऋण एजेंसियों के जरिए व्यापार वित्त को बढ़ाना, फरवरी 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 72	अफ्रीका में संपर्क सूत्रः परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे की भूमिका, मार्च 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 73	फार्मास्यूटिकल उद्योगः विनियामक परिदृश्य और भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर, मार्च 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 74	भारत-श्रीलंका व्यापार और निवेश संबंधः वर्तमान प्रवृत्तियां और संभावनाएं, मार्च 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 75	लैटिन अमेरिका तथा कैरिबिया में भारतीय निवेशः प्रवृत्तियां और संभावनाएं, मार्च 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 76	सीएलएमवी देशों के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाना, जून 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 77	बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारतीय व्यापार का संवर्धन, जून 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 78	मध्य प्रदेश के लिए निर्यात रणनीति, जून 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 79	भारत-रूस व्यापार संबंधः वर्तमान प्रवृत्तियां और क्षमताएं, अगस्त 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 80	भारतीय हथकरघा उद्योगः क्षमताएं और संभावनाएं, सितंबर 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 81	भारत-लैक व्यापारः चुनिंदा देशों में वर्तमान प्रवृत्तियां और अवसर, सितंबर 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 82	पश्चिम अफ्रीका में भारतीय निवेशः वर्तमान प्रवृत्तियां और संभावनाएं, अक्टूबर 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 83	प्रौद्योगिकी टेक्सटाइल में निर्यात संवर्धन, दिसंबर 2018
कार्यकारी आलेख संख्या 84	भारतीय पर्यटन उद्योगः उद्यमिता को बढ़ाने हेतु अवसरों की तलाश, फरवरी 2019
कार्यकारी आलेख संख्या 85	भारत-सैडेक व्यापार एवं निवेश संबंधः क्षमताओं का उपयोग करना, मार्च 2019
कार्यकारी आलेख संख्या 86	पंजाब से निर्यातः प्रवृत्तियां, अवसर और नीतिगत विश्लेषण, मार्च 2019
कार्यकारी आलेख संख्या 87	भारतीय निर्यात और विकास की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन, मार्च 2019

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्‍व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005
फोन : (91 22) 22172600 फैक्स : (91 22) 22182572
ई-मेल : ccg@eximbankindia.in वेबसाइट : www.eximbankindia.in, www.eximmitra.in

लंदन शाखा

5वीं मंज़िल, 35 किंग स्ट्रीट, लंदन ईसी 2वी 8बीबी, यूनाइटेड किंगडम
फोन : +44 20 77969040, फैक्स : +44 20 76000936
ई-मेल : eximlondon@eximbankindia.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार II, पहली मंज़िल,
एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास,
एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद 380 006
फोन : + 91 79 26576852/26576843
फैक्स : + 91 79 26577696
ई-मेल : eximahro@eximbankindia.in

बैंगलोर
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल,18,
एम. जी. रोड, बैंगलोर 560 001
फोन : +9180 25585755 / 25589101-04
फैक्स : +9180 25589107
ई-मेल : eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़
सी-213, दूसरी मंज़िल,
एलान्ते कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, फेज -1
चंडीगढ़ 160 002
फोनः +91172 4629171-73
फैक्स : +91172 4629175
ई-मेल : eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै
ओवरसीज टॉवर,
चौथी एवं पांचवीं मंज़िल,
नं. 756-एल, अन्ना सलाई,
चेन्नै 600 002
फोन : +9144 28522830/31
फैक्स : +9144 28522832
ई-मेल : eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस. रोड,
दिसपुर, गुवाहाटी 781 006
फोन : +91 361 2237607/609
फैक्स : +91 361 2237701
ई-मेल : eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल,
6-3-639/640, राजभवन रोड,
खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004
फोन : +91 40 23307816-21
फैक्स : +91 40 23317843
ई-मेल : eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल,
(अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016
फोन : +91 33 22833419-20
फैक्स : +91 33 22891727
ई-मेल : eximkro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, सातवीं मंज़िल,
एड्जेसेंट रिंग रोड, किदवई नगर (पूर्व),
नई दिल्ली 110 023
फोन : +91 11 61242600/24607700
फैक्स : +91 11 20815029
ई-मेल : eximndo@eximbankindia.in

पुणे
नं. 402 और 402 (बी), चौथी मंज़िल,
सिग्नेचर बिल्डिंग, भाम्बुर्डा, भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे 411 0034
फोन : +91 20 25648856
फैक्स : +91 20 25648846
ई-मेल : eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

आबिदजान
5वीं मंज़िल,
अज्यूर बिल्डिंग,
18-डॉक्तर क्रोज़े रोड,
प्लेत्यो-आबिदजान,
कोत दि'वार
फोन : +225 20 24 29 51
मोबाइल : +225 79707149
फैक्स : + 225 20 24 29 50
ईमेल : eximabidjan@eximbankindia.in

अदिस अबाबा
हाउस नं. 46,
जैक्रोस एस्टेट कंपाउंड,
वोरेडा 07,
बोले सब-सिटी,
अदिस अबाबा,
इथियोपिया
फोन : +251 118222296
फैक्स : +251 116610170
ई-मेल : aaro@eximbankindia.in

ढाका
मधुमिता प्लाज़ा कॉनकॉर्ड, 12वीं मंज़िल,
प्लॉट नंबर 11, रोड नंबर 11, ब्लॉक जी,
बनानी, ढाका, बांग्लादेश - 1213
फोनः +88 01 708520444
ईमेल : eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1 बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं.3
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र,
पीओ बॉक्स नं. 506 541, दुबई, यूएई
फोन : +971 43637462,
फैक्स : +971 43637461
ई-मेल : eximdubai@eximbankindia.in

जोहांस्बर्ग
दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट,
सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3, सैंटन 2196,
जोहांस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका
फोन : +27 11 3265103/13
फैक्स : +27 11 7844511
ई-मेल : eximjro@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कोलियर क्वे, 10-02
सिंगापुर 049319
फोन : +65 65326464
फैक्स : +65 65352131
ई-मेल :eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी. सी.
1750, पेंसिल्वेनिया एवेन्यु एन. डब्ल्यू.,
सूइट 1202, वाशिंगटन डी. सी. 20006,
संयुक्त राज्य अमेरिका
फोन : +1 202 223 3238
फैक्स : +1 202 785 8487
ई-मेल :eximwashington@eximbankindia.in

यांगून
हाउस नं. 54/ए, तल मंज़िल, बोरान्युत मार्ग,
डैगन टाउनशिप, यांगून, म्यांमार
फोन : +95 1389520
मोबाइल : +95 1389520
ई-मेल : eximyangon@eximbankindia.in

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन : (91-22) 2217 2600 । फैक्स : (91-22) 2218 2572
ई-मेल : ccg@eximbankindia.in । वेबसाइट : www.eximbankindia.in, www.eximmitra.in